असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

21 मार्च, 2017

षोडश विधान सभा 21 मार्च, 2017 ई0

---------- मंगलवार,तिथि ----------

पंचम सत्र 30 फाल्गुन, 1938(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तरकाल । अल्प-सूचित प्रश्न लिये जायेंगे । अल्प-सूचित प्रश्न संख्या : 19, श्री समीर कुमार महासेठ ।

श्री महबूब आलम : अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ का सुन लीजिये । आप को जो कहना होगा, 12 बजे कहियेगा ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, सूचना तो कम से कम ग्रहण कर लीजिये ।

अध्यक्ष : 12.00 बजे ही सूचना ग्रहण करेंगे । अभी सुनिये न । ठीक है । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

प्रश्नोत्तरकाल

अल्प-सूचित प्रश्न

अल्प-सूचित प्रश्न संख्या : 19 (श्री समीर कुमार महासेठ)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड 1 : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड 2 : आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राज्य के 5160 उच्च विद्यालयों के विरूद्ध लगभग 1832 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर सामग्री उपलब्ध है ।

खंड 3 : राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं राज्य संसाधन अंतर्गत राशि की उपलब्धता के उपरांत माध्यमिक विद्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने की कार्रवाई चरणबद्ध तरीके से की जायेगी ।

खंड 4 : प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है । उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध सहायक शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि जिस-जिस विद्यालय में कंप्यूटर है, वहां कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त हैं अथवा नहीं ? चूंकि शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक में अंतर है । इसीलिये यह जानना जरूरी है ।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, जहां-जहां कंप्यूटर है, हमलोग आई0सी0टी0 शुरू किये हुये हैं, अभी हमारे यहां 832 में आई0सी0टी0 चल रहा है, बाकी जगह जहां हमारे यहां कंप्यूटर हैं, यह प्रश्न ऑनलाईन से रीलेटेड है, इन्टरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा में हम जो ऑनलाईन अप्लाई करा रहे हैं, उस से रीलेटेड है तो आनेवाला जो वित्तीय वर्ष 2017-18 है, इसमें बाकी विद्यालयों में भी हम सभी जगह मैट्रिक और इन्टरमीडिएट परीक्षा ऑनलाईन करा रहे हैं, वहां पर कम्प्यूटर उपलब्ध करायेंगे और साथ-साथ जो हमारे टीचर हैं, उनको ट्रेंड करायेंगे इसलिए कि ऑनलाईन फार्म जमा करा सके ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी इतना स्मार्ट, इतना बढिया हैं, सही माने में विभाग ने निर्देश दिया था कि जहां कम्प्यूटर नहीं है, वहां प्रधानाध्यापक के सामने ही फार्म भरा जायेगा और इस का अनुपालन किया गया कि नहीं, माननीय मंत्री जी बतायें ।

अध्यक्ष : वही तो माननीय मंत्री ने बताया है कि जहां पर कम्प्यूटर है, वहां कम्प्यूटर से हो रहा है, जहां पर नहीं है, वहां पर प्रधानाध्यापक के सामने में करने की व्यवस्था है, जहां पर रेगुलर प्रधानाध्यपक नहीं हैं, वहां जो कार्यकारी हैं, जो प्रभारी हैं, उन के सामने काम किया जा रहा है तो अब आप क्या जानना चाहते हैं ?

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, एक समय-सीमा का निर्धारण चाहेंगे कि प्रधानाध्यापक और कम्प्यूटर की उपलब्धता सभी विद्यालयों में सुनिश्चित होगी, कब तक ?

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, वह मैट्रिक एवं इन्टरमीडिएट 2017 की परीक्षा के लिये ऑनलाईन फार्म भरवाने से संबंधित है । प्रश्न में स्पष्ट है और माननीय मंत्री महोदय ने इस बात को स्वीकार किया है कि 5160 उच्च विद्यालयों में से केवल 1832 में ही कम्प्यूटर हैं । उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि सभी विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं । महोदय, परीक्षा समिति ने निर्णय लिया था कि इस बार ऑनलाईन फार्म भरने का काम किया जायेगा । जब कंप्यूटर नहीं था तो सरकार ने यह भी निर्देश दिया कि वहां प्राचार्य/प्रधानाध्यापक के माध्यम से वैकल्पिक व्यवस्था की गयी थी । लेकिन मंत्री महोदय ने खुद भी स्वीकार किया है कि सभी स्कूलों में न तो कम्प्यूटर थे, न तो प्रधानाध्यापक थे तो क्या हाल होगा बच्चों का ? माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति अभी प्रक्रियाधीन है। महोदय, सवाल इस बात का है कि सरकार का एक अंग अगर यह निर्देश देता है कि सब ऑनलाईन करेंगे, सब जगह कम्प्यूटर नहीं है, कम्प्यूटर ऑपरेटर भी नहीं है, यह भी मंत्री महोदय ने स्वीकार किया, प्रधानाध्यापक भी नहीं हैं तो बच्चों के भविष्य का क्या होगा ? इसीलिए

हम सरकार से जानना चाहते हैं कि यह जो प्रक्रियाधीन प्रधानाध्यापक का मामला है तो सभी विद्यालयों में कब तक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति हो जायेगी ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : महोदय, सबसे पहले हम सदन को यह बताना चाहते हैं कि सरकार ने ऑनलाईन व्यवस्था क्यों की । यह बात सत्य है कि ऑनलाईन प्रोसेस जो हमलोगों ने शुरू किया, उसमें परेशानियां थी । लेकिन हमलोगों ने ऑनलाईन प्रोसेस इसलिये शुरू किया कि खास कर के जहां हमारे एफिलियेटड स्कूल हैं, वहां पर स्कूल का जो स्ट्रेंथ है, जो 50-100 होता था और जब फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होती थी, वहां से 500-1000 हजार बच्चे का फार्म भरा जाता था । इसीलिए हमलोगों ने इस प्रोसेस को ऑनलाईन प्रक्रिया शुरू किया । इसमें परेशानियां थी, हमलोगों को जानकारी थी, लेकिन बावजूद इसके कि प्रदेश के बाहर के बच्चे आ कर के यहां मैट्रिक की परीक्षा देते थे और जिस में अनियमिततायें होती थी, इसको रोकने के लिये हमलोगों ने ऑनलाईन प्रोसेस शुरू किया । यह बात भी सत्य है कि हमलोगों ने प्रभारी को जिम्मेवार बनाया, जहां प्रिंसपल थे, Principals were responsible, जहां पर नहीं थे, वहां Acting Principals were responsible और बहुत हद तक हमलोगों ने पेरशानियों को कम किया है, जहां पर सवाल है प्रोपर प्रिंसिपल करने का, हम ने वरीयता सूची निकाली है, हम समझते हैं मैक्सिमम दो महीने के अंदर, डेढ़ से दो महीने के अंदर प्रिंसपल का एप्वायंटमेंट कर दिया जायेगा और कमिंग फाईनेन्शियल ईयर में जहां-जहां प्लस टू और मैट्रिक है, जब जगह हम औनलाईन कम्प्यूटर से फॉर्म भरने की व्यवस्था करेंगे ।

अल्प सूचित प्रश्न संख्या : 20 (श्री अनिल सिंह)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, खंड 1 : उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुतः राज्य के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु प्रख्यापित बिहार राज्य संशोधन अधिनियिम, 2013 की धारा 3 (क) (iii) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/कौंसिल फॉर साइंटिफिक एण्ड इण्डस्ट्रीयल रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता/राज्य पात्रता परीक्षा को ही मान्य करने का प्रावधान है । तदनुसार विभागीय पत्रांक 763 दिनांक 10.04.2015 द्वारा BET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को NET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के समतुल्य मान्यता नहीं दी गई है ।

खंड 2 : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड 3 : वस्तुस्थिति यह है कि BET को NET के समतुल्य मान्यता दिये जाने के संबंध में LPA NO. 227/2016 एवं एल0पी0ए0 संख्या 511/2016 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्याय निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का निर्णय लिया गया है । ऐसी स्थिति में

BET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को Ph D/M.Phil उपाधि के आलोक में अधिभार दिये जाने का औचित्य नहीं है ।

श्री अनिल सिंह : अध्यक्ष महोदय, विज्ञापन संख्या 51/2014 के आलोक में 2002 के पूर्व उत्तीर्ण के साथ पी0एच0डी0 उपधारी अभ्यर्थी को 5 अंकों का अधिभार देने का निर्णय लिया गया था और उक्त निर्णय के आलोक में मेधासूची प्रकाशित करने से पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग पत्रांक 2262 दिनांक 3 नवंबर,2016 द्वारा शिक्षा विभाग से दिनांक 17 नवंबर, 2016 तक दिशा-निर्देश मांगा गया और विभाग द्वारा कोई निर्देश नहीं दिये जाने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने दिनांक 7 दिसंबर,16 को बैठक में लिया गया निर्णय और परीक्षा फल प्रकाशित कर दिया । उसके कारण 2002 तक पूरे देश में 2002 के पूर्व आयोजित बिहार इलेजिब्लिटी टेस्ट बेट को नेट के समकक्ष मानते हुये सभी केन्द्रीय एवं राज्यों के विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, असिसटेंट प्रोफेसर नियुक्ति में बेट अभ्यर्थियों को पात्रता हासिल है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये न । सरकार ने बताया है कि इस मामले में सरकार कोर्ट जा रही है । उसके बाद आपको क्या कहना है ?

श्री अनिल सिंह : महोदय, सरकार कोर्ट जा रही है, जो निर्णय लिया गया था, जिसके आलोक में इन्होंने विज्ञापन प्रकाशित किया था तो उस आलोक में कोर्ट का अभी निर्णय नहीं आया है तो जबतक निर्णय नहीं आया, जो पहले से निर्णय है, वह तो लागू होगा । इस आलोक में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी ...

अध्यक्ष : निर्णय के विरूद्ध ही न हाईकोर्ट में जाने का सरकार सोच रही है । वही तो मंत्री जी ने बताया है । अब आप का क्या पूरक प्रश्न है ?

श्री अनिल सिंह : मेरा यह कहना है कि जब उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद बेट में पी0एच0डी0 उपाधिधारी अभ्यर्थियों की पात्रता मानी गयी परन्तु जो 5 अंक का वेटेज मिलना था, वह नहीं दिये तो इस में हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बेट पी0एच0डी0 के लिये 5 अंक में अधिमानता देकर परीक्षाफल में संशोधन करना चाहती है ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बेट की परीक्षा 1996 में हुई थी, सरकार का जो नियम है, एक्ट की कॉपी है, एक्ट हम सदन में पढ़ देते हैं - ''आयोग प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय एवं उसके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु केवल वैसे अभ्यर्थियों से विषयवार आवेदन आमंत्रित करेगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/कौंसिल फॉर साइंटिफिक इन्डस्ट्रीयल रिसर्च द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता, राज्य पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लिये हों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता एवं समय से विहित अर्हतायें प्राप्त हो ।

क्रमश :

टर्न–2/राजेश/21.3.17

श्री अशोक चौधरी, मंत्री, क्रमशः ... तो महोदय, यह बेट का 1996 का रिजल्ट है और उस समय यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने बेट लिया था लेकिन सरकार ने जब नियम बनाया, उसमें प्रावधान नहीं है, हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है, उसके खिलाफ हमलोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ।

श्री अनिल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूँ कि विज्ञापन प्रकाशित कौन करता है, यह डिपार्टमेंट के आलोक में होता है, मंत्री महोदय के एप्रूभल से होता है या कोई व्यक्ति करता है और अगर इन्होंने विज्ञप्ति प्रकाशित किया है, उसके आलोक में ये जो हवाला दे रहे है, मैं बता रहा हूँ 51/2014 का और यह हवाला दे रहे हैं उससे बहुत ही पीछे का, जब आपने विज्ञप्ति जारी की, तो विज्ञाप्ति के अनुसार 5 अंक वेटेज मिलना चाहिए कि नहीं महोदय, मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा और मंत्री महोदय से जवाब चाहूंगा कि जब विभाग ने आपसे मांगा और इस आलोक में आपके द्वारा किसी प्रकार का निदेश नहीं दिया गया, तब उन्होंने निर्णय लेते हुए परीक्षाफल प्रकाशित किया, जिसके कारण बिहार के बहुत ऐसे मेधावी लोगों को इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली, उनको इसमें अवसर नहीं मिला और बिहार के बाहर के लोग बिहार में आकर जॉब कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिहार के बहुत से हमारे मेधावी छात्र पिछड़ गये हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इसमें संशोधन करते हुए पुनः परीक्षाफल प्रकाशित करना चाहते हैं जिससे कि बिहार के लोगों को, बिहार के युवाओं को अवसर मिले ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव जी का भी सुन लीजिये ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः अध्यक्ष महोदय .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः दोनों का जवाब साथ ही हो जायेगा ।

श्री अनिल सिंहः अध्यक्ष महोदय, तब तो कंबाईन्ड हो जायेगा । पहले मेरा पूरक हो जाय, क्योंकि यह अल्पसूचित प्रश्न है, इसलिए हम चाहेंगे कि वन वाई वन सब को पूछने का मौका मिले । इसलिए मैं आपसे आग्रह करुंगा ।

अध्यक्षः चलिये माननीय मंत्री जी ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्रीः महोदय, सरकार के एक्ट में प्रोविजन नहीं है, सरकार ने जो एक्ट बनाया है उसमें स्पष्ट है कि यू0जी0सी0 का गाईडलाइन्स है, उससे हमलोग कभर होते हैं, बेट 1996 में हुआ था, आयोग भंग हो गया, बहुत से उसके डिटेल सरकार के पास उपलब्ध भी नहीं हैं, इसलिए बेट का प्रोविजन यू0जी0सी0 गाईडलाइन है, सरकार का जो एक्ट है, हम उसको फॉलो करते हैं ।

श्री अनिल सिंहः अध्यक्ष महोदय,.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः अब तो छोड़ दीजिये ।

श्री अनिल सिंहः महोदय, हमको पूरा करने दिया जाय । महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, तो यह विज्ञापन किसने निकाला और अगर विभागीय पदाधिकारी बिना सरकार का परमिशन लिये हुए विज्ञापन निकाला है, तो माननीय मंत्री महोदय उनपर क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ?

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री विनोद प्रसाद यादव ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः महोदय, सरकार द्वारा कहा गया है कि विज्ञापन में 51/2014 के अधीन 5 अंक देना था, तो उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है, कोई भी नियुक्ति राज्य सरकार की नीतियों के तहत होती है और राज्य सरकार ने नियुक्तिकर्ता को यह दिया था कि इनको 5 अंक दिया जायेगा पी0एच0डी0 डिग्रीधारियों को, दूसरी बात यह है कि यू0जी0सी0 गाईडलाइन के पहले महोदय जो उच्च डिग्रीधारी लोग थे, पी0एच0डी0 के डिग्रीधारियों को डायरेक्ट साक्षात्कार से विश्वविद्यालय को सहायक प्रधानाध्यापक बनाया जाता था महोदय, तो माननीय मंत्री जी का यह कहना कि राज्य के लोग जो उच्च डिग्रीधारी लोग थे, उनको एक मौका मिलता था महोदय, तो अभी जो यू0जी0सी0 का नया गाईडलाइन बना, उसमें उच्च डिग्रीधारियों को छांट दिया गया महोदय, केवल नेट, बेट को रखा गया, सरकार उच्च डिग्रीधारी प्राप्त लोगों को .....

(व्यवधान)

अध्यक्षः गाईडलाइन में बिहार सरकार क्या करेगी ?

श्री विनोद प्रसाद यादवः महोदय, मैं पूरक यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार राज्य के उच्च डिग्रीधारियों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनको नौकरी में अवसर मिले, इसके लिए सरकार यू0जी0सी0से वार्ता करके पी0एच0डी0 डिग्रीधारियों को कोई विशेष व्यवस्था कराने का विचार रखती है ?

अध्यक्षः यह सुझाव है माननीय मंत्री जी ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः महोदय, यह सुझाव नहीं है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, यह अहम प्रश्न है राज्य के लोगों के लिए । महोदय, इसमें माननीय मंत्री महोदय को संज्ञान में लेकर कहना चाहिए कि पी0एच0डी0 डिग्रीधारी हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था सरकार करेगी ?

अध्यक्षः सरकार जब कुछ नहीं कह रही है, तो मान लीजिये कि सरकार को अभी कुछ नहीं कहना है ।

श्री विनोद प्रसाद यादवः सरकार को इसमें पहल करना चाहिए ।

अध्यक्षः तारांकित प्रश्न ।

श्री नंदकिशोर यादवः महोदय, मूल प्रश्न को देखा जाय । यह ठीक है माननीय मंत्री महोदय ने वक्तव्य दिया है, अपने नियम के अनुसार दिया है लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बी0पी0एस0सी0 ने विज्ञापन निकाला, तो विज्ञापन में जिन अहर्ताओं का जिक्र था, उसका पालन क्यों नहीं हुआ, पहला प्रश्न ?

दूसरा प्रश्न यह है कि बी0पी0एस0सी0 को जब कंफ्यूजन हुआ, तो उसने विभाग से मंतव्य मांगा, विभाग ने मंतव्य नहीं दिया क्यों ? जिसके कारण से जो परीक्षार्थी शामिल हुए उसमें, उनको दंड भुगतना पड़ा, तो जो सवाल मैंने किये हैं, उन सवालों का क्या जवाब है ?

अध्यक्षः मंत्री महोदय ने बताया ...

(व्यवधान)

श्री नंदकिशोर यादवः नहीं बताया महोदय ।

अध्यक्षः उन्होंने बताया कि चूंकि यू0जी0सी0 का गाईडलाइन आ गया, तो उस स्थिति में विभाग ने उसको लिया ।

श्री नंदकिशोर यादवः महोदय, आप भी मंत्री रहे हैं और हमलोग भी मंत्री रहे हैं महोदय और हमलोग जानते हैं कि यदि किसी भैकेंसी के लिए बी0पी0एस0सी0 को लिखते हैं या किसी को लिखते हैं, तो अर्हता क्या होगी, उसको हमलोग तय करते हैं और जो बी0पी0एस0सी0 ने जो विज्ञापन निकाला, अहर्ता तय कर दिया, कंफ्जन कहीं हुआ, उसने विभाग को चिट्ठी लिखा, तो विभाग ने जवाब नहीं दिया, तो महोदय यह बहुत ही गंभीर विषय है, इसलिए इन दोनों विषयों पर सरकार का क्या रुख है, क्या जवाब है, यह मैं जानना चाहता हूँ ?

अध्यक्षः सरकार को कुछ अतिरिक्त चीज बतानी है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्रीः महोदय, बी0पी0एस0सी0 ने जो एडभरटिजमेंट दिया, उसमें शिक्षा विभाग के कहीं न कहीं, जो नीचे के पदाधिकारी हैं, जो सैंक्सन किया, उनकी कहीं न कहीं भूमिका है, जिसके कारण यह परेशानी हुई है, तो वैसे जो पदाधिकारी हैं, उनके उपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायगी ।

अध्यक्षः चलिये ।

श्री नंदकिशोर यादवः महोदय आ गया न । महोदय, यह बहुत बड़ा घोटाला है, इसपर कार्रवाई होनी चाहिए ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्याः 2161(श्री अनिल कुमार यादव)</u>

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्रीः महोदय, खण्ड 1:- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: जिला पदाधिकारी अररिया का पत्रांक-136 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी दिनांक 10.3.17 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अररिया जिलान्तर्गत भरगामा प्रखंड के धनेश्वरी पंचायत के वार्ड नं0-4 में सेविका चयन के विरुद्ध वाद दायर किया

गया है, जो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अररिया के न्यायालय में वाद-संख्या- 2/16-17 विचाराधीन है ।

खण्ड 3: उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

खण्ड 4: उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री अनिल कुमार यादव: महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूँ कि यह पॉच महीना हो गया, स्पष्ट है कि पंचायत चुनाव आयोग के द्वारा दूसरे वार्ड का जो वोटरलिस्ट है, उसमें उसका नाम है, उसमें उसका घर है, यह एकदम स्पष्ट है, तो अभी तक जिला में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी पैसे का दलाली कर रहे हैं कि आप इसको रद्द करें या इसकी नयी बहाली हो, तो अगर यह स्पष्ट है कि यह दूसरे जगह का वासी है, वोटर लिस्ट में उसने मतदान भी किया है और पंचायत सूची में उसका नाम है, तो उसको अविलंब क्यों नहीं खाली किया जाता है, क्यों इस मामले को लंबित किया जाता है ?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री: महोदय, चयन नियमावली में नगरी नक्शा बनाने में गड़बड़ियॉ करती थी, इसलिए मैंने नया नियमावली बनाया और उसमें स्पष्ट निदेश दिया कि किसी भी सूरत में वार्ड का जो परिसिमन है, जो अंक है, जो अंतिम मतदाता सूची है पंचायत चुनाव का, वह उसको नहीं लॉघ सकती है लेकिन देखने से लगता है कि इसमें गड़बड़ियॉ हुई हैं, तो मैं अपने स्तर से इसकी जांच करवा करके संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी को दंडित करुंगी, सत्र के बाद ।

अध्यक्ष: आप नियुक्ति की प्रक्रिया भी जारी करवा दीजियेगा ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री: जी, मैं वह करवा दूंगी ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या: 2162 (श्री प्रभुनाथ प्रसाद)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री: महोदय, खण्ड 1: उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खण्ड 2: राज्य संसाधन एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत राशि की उपलब्धता के उपरान्त प्रश्नगत विद्यालय के जीर्णोद्धार का कार्य किया जायेगा ।

श्री प्रभुनाथ प्रसाद: महोदय, मैं जानना चाहता हूँ, यह इतना जर्जर हो गया है कि अगर प्राथमिकता के आधार पर उस विद्यालय में काम लग जाता, तो अच्छा होता ।

डा0 सुनील कुमार: महोदय, यह पूरे बिहार का मामला है ।

अध्यक्ष: नहीं है, यह केवल गड़हनी का मामला है । इसमें पूरा बिहार कहॉ से आ गया । इसमें बिहार तो कहीं है नहीं । पूछिये ।

डा0 सुनील कुमार: महोदय, पूरे बिहार राज्य में विद्यालयों का स्थिति जर्जर है । प्राईमरी स्कूल और मिडिल स्कूल का स्पीड से जीर्णोद्धार हो जाता है लेकिन अभी केन्द्र सरकार ने

अल्पसंख्यक समुदाय बहुल इलाकों में स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए काफी राशि दिया है, तो क्या बाकी स्कूलों का जीर्णोद्धार करने के लिए बिहार सरकार राज्य बजट से राशि देकर उसका जीर्णोद्धार कराना चाहती है ?

अध्यक्षः अल्पसंख्यक विद्यालयों के जीर्णोद्धार के लिए राशि किसने दी है ?

डा0 सुनील कुमारः अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में सेन्ट्रल गवर्नमेंट की राशि आयी है, जिससे जीर्णोद्धार हो रहा है ।

टर्न-3/सत्येन्द्र/21-3-17

तारांकित प्रश्न संख्या- 2163(श्रीमती पूर्णिमा यादव)

श्री संतोष कुमार निराला,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्य के सुशासन कार्यक्रम 2015-20 के अन्तर्गत विकसित बिहार के लिए मुख्यमंत्री के संकल्पित सात निश्चय कार्य के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की जानी है । तदनुसार नवादा जिला अन्तर्गत खनवां नरहट प्रखंड में पोलिटेकनिक संस्थान की स्थापना की जा चुकी है तथा वित्तीय वर्ष 2016-17 से पठन पाठन का कार्य आरम्भ है । नवादा जिला अन्तर्गत अन्य प्रखंडों में अतिरिक्त पोलिटेकनिक संस्थान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्रीमती पूर्णिमा यादवः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहती हूँ कि ये गोविन्दपुर प्रखंड का प्रश्न है और माननीय मंत्री जी नवादा के बारे में बतलाये हैं ।

अध्यक्षः नहीं, मंत्री जी ने कहा कि अभी सरकार की नीति जिले में कम से कम एक पोलिटेकनिक खोलने की है और वह खनवां में खुल गया है । अभी गोविन्दपुर में खोलने का इनका कोई प्रस्ताव नहीं है, यही मंत्री जी ने कहा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2164(श्री विनय वर्मा)

श्री अशोक चौधरी,मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण सत्र 2014-16 की परीक्षा संबंधी सभी प्रक्रिया पूरी कर दिनांक 21-11-16 से आयोजित करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी थी परन्तु सी0डब्लू0जे0सी0 नं0-11079/16 में माननीय उच्च न्यायालय,पटना द्वारा दिनांक 21-10-16 को पारित आदेश के आलोक में वैसे अध्यापक शिक्षा संस्थान जिन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सम्बद्धता नहीं प्रदान की गयी है, उनकी परीक्षा आयोजित नहीं की जाय ।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति(अध्यापक शिक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गमन सम्बद्धता मानदंड तथा प्रक्रिया)विनियमावली 2016 तैयार की जा चुकी है । उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत

पाया गया है कि राज्य के 44 अध्यापक शिक्षा संस्थान (34 सरकारी एवं 10 गैर सरकारी) समिति से सम्बद्ध नहीं है।

उक्त सभी संस्थानों की सम्बद्धता संबंधी कार्रवाई अगले 20 दिनों के अन्दर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,पटना द्वारा पूर्ण करने के उपरांत सत्र 2014-16 की डी0एल0डी0 कोर्स की परीक्षा आयोजित की जायेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2165(श्री आनंद भूषण पाण्डेय)

(मा0 सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 2166(श्री संजय सरावगी)

अध्यक्ष: नितिन नवीन जी।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री: महोदय,(क)आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। डी0पी0ओ0 एवं सी0डी0पी0ओ0 के रिक्त पद पर विभिन्न जिलों में स्थानीय व्यवस्था के तहत कार्य लिया जा रहा है । आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन में कोई समस्या नहीं है । डी0पी0ओ0 एवं सी0डी0पी0ओ0 के रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

श्री नितिन नवीन: अध्यक्ष महोदय, पहले माननीय मंत्री जी को स्थानीय व्यवस्था के तहत यह स्पष्ट करना चाहिए कि स्थानीय व्यवस्था किस प्रकार की है और जो 50 प्रतिशत जब पद रिक्त हैं तो निश्चित रूप से क्या काम हो पा रहा होगा आंगनबाड़ी केन्द्रों में, ये समझ सकते हैं । आपके पद तीन सालों से रिक्त है तो माननीय मंत्री जी पहले तो बतायें कि स्थानीय व्यवस्था क्या है और दूसरा सवाल यह है कि ये पूरे पद जो रिक्त हैं यह किस समय तक यह सभी पद भर दिये जायेंगे, उसका समय सीमा बतलायें ।

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री: महोदय, पद तो रिक्त है हीं और स्थानीय व्यवस्था यही है कि बगल के पदाधिकारी को उसका प्रभार दिया जाता है और डी0पी0ओ0 के बदले में जिला में डिप्टी कलक्टर या और डी0एम0 के स्तर पर प्रभार दिया जाता है और काम हो रहा है लेकिन कमियां हैं और उसको दूर करने के लिए विभाग जो है सीधी भर्त्ती और प्रोन्नति पर काम कर रही है ।

श्री नितिन नवीन: अध्यक्ष महोदय, समय सीमा बतायें माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि इससे समस्या है तो किस समय सीमा के अन्दर ये 50 प्रतिशत जो पद रिक्त है इसको भर लिये जायेंगे ?

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री: मैं चार महीना के अन्दर पद भर लूंगी ।

श्री अशोक कुमार सिंह: यह गरीबों से जुड़ा मामला है महोदय, माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग ने बच्चों के मृत्यु दर पर बताया था कि बिहार में बढ़ गया है और कुपोषण से बचाने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों का बहुत महत्वपूर्ण रौल है..

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये ।

श्री अशोक कुमार सिंह: पूरक है महोदय कि क्या माननीय मंत्री जी यह हमें बतलाने की कृपा करेंगी कि कबतक सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सभी प्रखंडों में आंगनबाड़ी पदाधिकारी की नियुक्ति हो जायेगी ।

अध्यक्ष: ठीक है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2167(श्री महबूब आलम)

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि पूर्व में अवस्थित छात्रावास का भू-खंड वर्त्तमान में खाली है । राज्य योजनान्तर्गत छात्रावास निर्माण की कोई योजना नहीं है ।

श्री महबूब आलम: महोदय, जिस जमीन पर हिन्दू होस्टल था उस जमीन में एक भवन सरकार के तरफ से बनी है और वह भवन किस उद्देश्य के लिए बनी है ये मंत्री महोदय के जानकारी में नहीं है मेरी भी जानकारी में नहीं है साथ-साथ जो मुस्लिम होस्टल जिस जमीन में था महोदय वहां कुछ भी अस्तित्व नहीं है, खाली जमीन है और आबादी के बीच की जमीन है और उस जमीन के अतिक्रमण होने की संभावना हो गयी है । मैं मंत्री महोदय से पूछता हूँ कि उस जमीन का सीमांकन कर कबतक उसको मुस्लिम होस्टल बनाने की परिकल्पना रखते हैं और जो हिन्दू होस्टल का भवन बन गया है उसे हिन्दू होस्टल के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना है कि नहीं?

अध्यक्ष: महबूब आलम जी, पहले तो जो बिल्डिंग बनी है वह किस विभाग ने बनाया है कहां से बना है यही पता नहीं है तो अभी मंत्री जी कैसे कह देंगे कि हम उसमें होस्टल चलायेंगे।

श्री महबूब आलम: महोदय, स्कूल की जमीन है उच्च विद्यालय की जमीन है, वहां कैसे कोई भवन बना लेगा उसकी जानकारी लेनी चाहिए ।

अध्यक्ष: उसको दिखवा लीजियेगा मंत्री जी, कहां भवन है ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2168(श्री नारायण प्रसाद)

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा,मंत्री: महोदय,(1) अस्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण वेतिया के पत्रांक 19 दिनांक 17-3-17 से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वस्तुस्थिति यह है कि बैरिया प्रखंड अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 23 तदवानंदपुर पंचायत में संचालित है परन्तु स्थलीय जांच के आधार पर सूर्यपुर पंचायत में विनोद पटेल के घर के पास निर्मित आंगनबाड़ी भवन परियोजना संख्या- 1/2011-12 का शिलापट्ट लगा हुआ है जिसमें वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या 124 संचालित है । बार्ड नं0-7 कोईरपट्टी में स्कूल

के पास एक भवन निर्मित है जिस पर योजना संख्या 2013-14, योजना के नाम कोईरपट्टी, बार्ड नं0-7,8 में आंगनबाड़ी भवन का निर्माण कार्य योजना पट्ट लगा है। इस भवन में केन्द्र संख्या-123 संचालित है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी पश्चिम चम्पारण, बेतिया से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार केन्द्र संख्या 123 का पोषक क्षेत्र बार्ड नं0-7 एवं 8 है । पूर्व में यह केन्द्र किराये के भवन में संचालित था । विनोद सरपंच के घर के पास वर्त्तमान में केन्द्र संख्या 124 संचालित है । उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है । उपरोक्त में कोई केन्द्र पोषक क्षेत्र के बाहर चल रहा है अथवा नहीं इस बिन्दु पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बैरिया से प्रतिवेदन की मांग की गयी है साथ ही उनसे यह बिन्दु पर भी प्रतिवेदन की मांग किया गया है कि क्या एक ही पोषक क्षेत्र में दो सरकारी भवन निर्मित है । यदि एक ही पोषक क्षेत्र में दो केन्द्र निर्माण का मामला जांच में प्रकाश में आता है तो दोषी व्यक्तियों से उक्त राशि की वसूली के साथ ही विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी ।

श्री नारायण प्रसादः अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी मैं कहना चाहता हूॅ कि 123 आंगनबाड़ी संख्या है और बिनोद सरपंच के घर के पास जो बना है वह सूर्यपुर में है न कि तदबानंदपुर में है सूर्यपुर में आंगनबाड़ी केन्द्र बना है जो बार्ड नं0-5 में है और उसकी कोई उपयोगता नहीं है वहां अभी स्थानीय लोग रहते है उसमें और 123 में जो सात नं0 बार्ड नं0 में बना है वह उसी में कार्यरत है आंगनबाड़ी का कार्य चलता है। मेरा प्रश्न यह है कि बिनोद सरपंच के घर के पास जो बना हुआ है वह दूसरे के कब्जा में है और वहां बनाने की उपयोगिता क्या है । 123 के नाम पर जब वह भी बना है तो उसकी उपयोगिता क्या है । आंगनबाड़ी संख्या 123 पर दो-दो बना हुआ है तो क्या सरकार उस पर अभी वर्त्तमान मुखिया पर और सचिव पर कार्रवाई सरकार करना चाहती है या नहीं ?

टर्न-4/मधुप/21.03.2017

श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, मंत्री : महोदय, मैं मुख्यालय स्तर से जॉच करवा लेती हूॅ, अगर एक ही पोषक क्षेत्र में दो आंगनबाड़ी केन्द्र बने होंगे तो कार्रवाई होगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2169 (श्री सरोज यादव)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, 1- आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत इन्टर महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2014-16 से सशर्त्त संबद्धता प्रदान की गयी है ।

महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन जिला पदाधिकारी, भोजपुर के माध्यम से उप विकास आयुक्त, भोजपुर की अध्यक्षता में गठित जॉच दल द्वारा कराया गया । जॉच दल ने प्रश्नगत इंटर कॉलेज का बोर्ड शहीद राजनाथ बी0एड0 कॉलेज के भवन में पाया । निर्धारित शर्त्तों की पूर्त्ति नहीं किये जाने के कारण बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इसकी संबद्धता को निलम्बित करते हुए इन्टर महाविद्यालय प्रबंधन से कारण पृच्छा किया गया है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- प्रश्नगत इन्टर महाविद्यालय प्रबंधन से कारण पृच्छा का उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि डी0डी0सी0 की अध्यक्षता में जॉच टीम बनाई गई और उसका स्थल निरीक्षण भी कराया गया, न उसका भवन पाया गया, कुँवर सिंह कॉलेज में अवस्थित करके उसको संचालित किया जाता था ।

अध्यक्ष : यह सब बात मंत्री जी ने माना है ।

श्री सरोज यादव : अध्यक्ष महोदय, उस कॉलेज की संबद्धता को रद्द कर दी गई, तीन साल छात्र और छात्राओं को एक्जाम में भाग भी दिलाया गया उस कॉलेज के माध्यम से, तो क्या सिर्फ संबद्धता रद्द कर देना ही कार्रवाई है या उसपर दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिये ? ऐसे लोगों पर एफ0आई0आर0 करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय, उसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ एक और मामला है, इसी तरह कुँवर सिंह कॉलेज को भी वह व्यक्ति लूट रहा है । मैं बार-बार सदन में इस मामला को उठाता हूँ मगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और सरकार द्वारा दी गई अनुदान राशि को वह हमेशा गबन करता है वह व्यक्ति और उनपर कोई कार्रवाई नहीं किया जाता है ?

श्री मो0 नवाज आलम : महोदय, जो एडहॉक कमिटी है, जो तदर्थ कमिटी है, सरकार ने माना है कि है कि कहीं न कहीं उसमें गबन हुआ है और जो प्रक्रिया और मापदंड है कॉलेज का, उसको पूरा नहीं किया है ।

महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या वैसी कमिटी पर कोई कार्रवाई करेंगे ? करेंगे तो कबतक ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष जो घटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में हुई, उसके बाद सरकार ने इस पूरे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में ऑपरेशन क्लीन

शुरूआत की । इस प्रदेश में लगभग हजार से उपर ऐसे +2 के इन्टर कॉलेजेज थे जिनकी संबद्धता को रद्द किया गया और वैसे कॉलेज, पूरी तरह से एडहॉक एजुकेशन देने के सिस्टम पर सरकार पूरी तरह से गम्भीर है और वैसे विद्यालय की न सिर्फ संबद्धता खतम होगी, वैसे विद्यालय को शो-कॉज किया गया है क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में जब हाईकोर्ट जाते हैं, पूरा टाईम उनको दिया जाता है । इसलिये इनके उपर न सिर्फ एफ0आई0आर0 होगा बल्कि ऐसे सभी लोगों को जेल के अन्दर भेजने का काम सरकार करेगी ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अब क्या हो गया ? सवाल से आगे जवाब था ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : बहुत गम्भीर मामला है ।

अध्यक्ष : एफ0आई0आर0 की बात कह रहे थे, यहाँ तो जेल भेजने की बात हो रही है ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि बिहार में ऐसे हजारों विद्यालय जो फर्जी तरीके से एफिलियेशन लेकर चलाने का काम कर रहे थे, इसपर आदेश देने वाले कौन लोग थे, उसपर कौन-सी कार्रवाई की गई है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : आदेश जो कर रहे थे, वे तो जेल में चले गये । जो थे करने वाले उनपर सरकार ने कार्रवाई किया ओर वे ऑलरेडी जेल में हैं ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में यह घटना घटी है तो क्या ऐसे कार्य करने वाले उस विद्यालय की सम्पत्ति को जब्त करने का सरकार विचार रखती है ?

<u>तारांकित प्रश्न संख्या- 2170 (श्री विनोद कुमार सिंह)</u>

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, विभागीय संकल्प संख्या- 1021 दिनांक- 05.07.2013 के आलोक में जिला पदाधिकारी से अनुशंसा प्राप्त होने पर प्रश्नाधीन विद्यालय के उत्क्रमण पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि कार्रवाई की जायेगी । सरकार की घोषणा है और वह एन0डी0ए0 सरकार की घोषणा थी कि राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक-एक हाई स्कूल का निर्माण कराया जायेगा । आज भी सम्पूर्ण बिहार के अन्दर 50 प्रतिशत पंचायतों के अन्दर....

अध्यक्ष : आपने प्रश्न में अपने क्षेत्र का नाम देकर पूछा है और पूरे बिहार का बता रहे हैं ।

श्री विनोद कुमार सिंह : सिर्फ बता रहे हैं । 50 प्रतिशत स्कूलों में हाई स्कूल का निर्माण नहीं कराया गया है, उसी में उदाहरण स्वरूप आजमनगर प्रखंड के चोल्हर पंचायत तथा प्राणपुर प्रखंड के गौरीपुर पंचायत में कबतक हाई स्कूल को उत्क्रमित करने का सरकार विचार रखती है ? समय-सीमा बतावें, कबतक ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : एक तो हम माननीय सदस्य को अपडेट करना चाहते हैं कि यू0पी0ए0 सरकार के सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत यह निर्णय हुआ था कि सरकार सभी विद्यालयों में जहॉ पंचायत है वहॉ उसको हम अपग्रेड करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के तहत।

इसमें हमने कहा है कि हमलोगों का यह नियम है कि हम सभी पंचायतों में करेंगे, हमने कहा है कि जिलाधिकारी से जमीन कितना है, अहर्त्ता पूरा करता है या नहीं करता है, उसको करते हुये हम करेंगे ।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, वहॉ तो मिडिल स्कूल है ही, उसको तो उत्क्रमित करना है उस पंचायत के अन्दर में । समय-सीमा तो बता दें कि कबतक करेंगे ? फिर वह पदाधिकारी से जानकारी क्या लेना है ?

तारांकित प्रश्न संख्या- 2171 (श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)

अध्यक्ष : श्री राणा रणधीर को प्राधिकृत किया है ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : महोदय, स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधीन वर्त्तमान में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिये कुल 12, अन्य पिछड़ा कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय संचालित है । जिनमें वर्ग 6 से 12 तक की कक्षाएँ संचालित की जाती हैं । वर्त्तमान में विभाग के अन्तर्गत ऐसा कोई विद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है ।

2- वर्त्तमान में सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये कला, सिलाई, बुनाई, पेंटिंग आदि का आवासीय +2 विद्यालय खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि पूरा देश चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष मना रहा है । माननीय मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम मोतिहारी में होना है और यही कल्याणपुर प्रखंड में राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी जी शुक्ला जी और लोमराज जी के बुलावे पर गये थे और यह अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़ा हुआ मामला है, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, तो मैं आग्रह करता हूँ कि सरकार इसपर विचार करे और शताब्दी वर्ष में अगर खोलती है तो बहुत ही सकारात्मक काम होगा चम्पारण के लिये, गॉधी जी को श्रद्धांजलि होगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2172 (श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, गोपालगंज से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज का सैनिक स्कूल, हथुआ, हथुआ प्रखंड मुख्यालय के वैकल्पिक भवन में संचालित है, जो हथुआ प्रखंड के मुख्यालय में अवस्थित है ।

इस विद्यालय के लिये निर्माणाधीन भवन में एकेडेमिक भवन, प्रशासनिक भवन एवं एक छात्रावास का कार्य अन्तिम चरण में है । प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक/कर्मचारी आवास एवं 3 छात्रावास का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम स्वयं गये थे सैनिक स्कूल, हथुआ में और वहाँ के प्राचार्य से भी मेरी बातचीत हुई । प्राचार्य जी ने कहा कि छात्र जो हैं, सीढ़ीनुमा रूम में रहते हैं, एक चौकी के उपर चौकी, चौकी के उपर चौकी, एक नीचे, उसके उपर एक और उसके उपर एक रहता है । छात्रों को रहने का स्थान नहीं है । शिक्षक और कर्मचारियों के लिये आवास नहीं है और हथुआ महाराज के पुराने भवन में है, वह कभी भी गिर सकता है, बीच में भूकम्प आया था तो प्राचार्य जी ने कहा कि हमलोग कॉप रहे थे, सारे बच्चों को निकाल कर फील्ड में रखा था...

अध्यक्ष : अब पूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि वहाँ शिक्षण भवन बन गया है लेकिन छात्रावास और शिक्षक/कर्मचारियों के लिये भवन नहीं बने हैं, वह भवन कबतक बनवा दिया जायेगा ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, उत्तर में हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस विद्यालय के लिये निर्माणाधीन भवन में एकेडमिक भवन, प्रशासनिक भवन एवं एक छात्रावास का कार्य अन्तिम चरण में है । प्राचार्य, उप प्राचार्य, शिक्षक/कर्मचारी आवास एवं 3 छात्रावास का कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायेगा ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि कार्य शुरू है, माननीय मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूँ कि वहाँ पैसा एलौटमेंट नहीं है, मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि जॉच करायी जाय कि वहाँ काम चल रहा है या नहीं चल रहा है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो कहा है कि अंतिम चरण में है ।

श्री सत्यदेव प्रसाद सिंह : काम ही शुरू नहीं हुआ है, अध्यक्ष महोदय । इन्होंने सदन को गुमराह किया है, काम नहीं शुरू हुआ है, मैं गया था एक महीना पहले ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, देखवा लीजियेगा ।

(व्यवधान)

मंत्री जी को कहा है, वे देख लेंगे । गुमराह किया होगा तो देख लेंगे । वह सब सूचना आप मंत्री जी को दे दीजियेगा ।

टर्न–5/आजाद/21.03.2017

तारांकित प्रश्न सं0–2173(श्री राम बालक सिंह)

श्री शिवचन्द्र राम,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क–उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि समस्तीपुर जिला के धर्मपुर ग्राम में अवस्थित एक परिवर्तित मध्यकालीन मंदिर है, जिसमें लखौरी, ईटों एवं सुखे चुने का प्रयोग किया गया है । परन्तु आधुनिक काल में जीर्णोद्धार के क्रम में आधुनिक सामग्रियों यथा सिमेंट,बालू आदि का प्रयोग किया गया है और इसके मूल स्वरूप में काफी परिवर्तन हो चुका है । मंदिर के मूल स्थाप्त संबंधी विशेषता यदि कभी रही हो तो वह बदली जा चुकी है । ऐसी स्थिति में इस स्थल के संरक्षण हेतु एक उच्चस्तरीय टीम को भेजकर इस ऐतिहासिक मंदिर का आकलन कराया जायेगा, तदुपरान्त अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री राम बालक सिंह : कब तक इसपर अगली कार्रवाई की जायेगी महोदय ?

अध्यक्ष : शीघ्र करा दीजिए ।

श्री शिवचन्द्र राम,मंत्री : शीघ्र करा देंगे महोदय ।

तारांकित प्रश्न सं0–2174(श्री श्याम रजक)

श्री शिवचन्द्र राम,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1– उत्तर स्वीकारात्मक है । विभागीय दल द्वारा दिनांक 21.02.2017 को बक्सर एवं राजपुर के ऐतिहासिक किलों का स्थल निरीक्षण किया गया है । तत्पश्चात् सर्वप्रथम राजपुर किलों को सुरक्षित घोषित करने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही बक्सर स्थित किले के दीवार को भी संरक्षित किया जायेगा ।

2– उत्तर स्वीकारात्मक है ।

3– बिहार सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित स्मारक टेकारी, गया किलों को विभाग द्वारा संरक्षित किया जा रहा है, शेष का ऐतिहासिक तथ्य संकलित कर अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है और इन्होंने कहा है कि 21.02.2017 को टीम गई थी और उसकी जॉच हो रही है लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसके अलावा भी और भी कई किलायें हैं, पटना विश्वविद्यालय का दरभंगा हाऊस जर्जर है, उसी तरह से आपका दरभंगा महाराज का किला 1977 में भूकम्प आया था, वह काफी जर्जर है, उसी तरह से कई ऐसे किलायें हैं, उस संदर्भ में राज्य सरकार क्या करना चाहती हे, क्योंकि यह भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के अधीन रहता है और वह सिर्फ अपना नेमप्लेट लगा देती है और कुछ काम होता नहीं है । राज्य सरकार इसपर विशेष रूप से क्या करना चाहती है और इसको समय सीमा के अन्दर करेगी, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं ?

श्री शिवचन्द्र राम,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, तमाम जितने भी माननीय सदस्य का सवाल है, सबकी जॉच के लिए हमने प्रतिवेदन मांगा है और जितनी भी हमारे यहां सिर्फ सुरक्षित स्थल और स्मारक 40 है । हम सभी जगहों पर अपने पूरी कमिटी को भेजकर सबको जॉच करा रहे हैं और जॉच कराकर के जितना भी हमारा सुरक्षित है, उसको ज्यादा से ज्यादा सुन्दर और सबल बनाने का सरकार काम कर रही है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

(व्यवधान)

दोनों का मामला एक साथ हो गया है । दोनों एक-दूसरे को देख करके फैसला कर लीजिये कि पूरक कौन पूछियेगा । चलिये अभय जी ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदय, इसमें टेकारी का मामला आया है । मैं टेकारी किला के संबंध में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी को और सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि टेकारी किला बहुत ही प्राचीन किला है और उसको भू-माफियों के द्वारा षडयंत्र के तहत 16 आना किला जो था, उसको 9 आना और 7 आना में विभाजित कर दिया गया है । 9 आना हिस्सा सरकार ने अधिग्रहित करके 7 आना को फ्री छोड़ दिया । एक कमिटी गठित हुई थी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार, तकरीबन 2008 में कमिटी गठित हुई थी विधान सभा की । विधान सभा की कमिटी ने 2008 में रिपोर्ट दिया कि 7 आना में घनी आबादी है, इसलिए उसको अधिगृहित नहीं किया जा सकता है । हम सदन के माध्यम से यही आग्रह करना चाहते हैं कि उस रिपोर्ट पर अभी जॉच करा लिया जाय चूँकि 2008 में रिपोर्ट सौंपा गया कि घनी आबादी है, अब विगत 8 वर्षों में तो और घनी आबादी हो गई होगी तो उस रिपोर्ट को एक बार पुनः जॉच करा ली जाय, चूँकि वहां पर किसी प्रकार का घनी आबादी अवस्थित नहीं है । इसलिए 7 आना को भू-माफियाओं के द्वारा एक षडयंत्र के तहत उसको बेचा जा रहा है, इससे वहां भारी आक्रोश है महोदय । बहुत बार हमने सरकार का ध्यान यहां पर आकृष्ट कराया है ।

अध्यक्ष : सरकार इसको देख लेगी ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदय, यह बहुत ही गंभीर विषय है .....

अध्यक्ष : इसीलिए हमने कहा है कि सरकार देख लेगी ।

श्री अभय कुमार सिन्हा : महोदय, हमारा विशेष आग्रह है कि इसपर एक नई कमिटी बनाकर इसकी पुनः जॉच करवा ली जाय ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय,

अध्यक्ष : ऐसा है तिवारी जी, माननीय मंत्री जी ने साफ-साफ इन सभी जगहों के बारे में कहा है कि सरकार वहां का स्थल निरीक्षण कराकर के प्रतिवेदन लेगी, इसपर आगे की कार्रवाई कर रही है । और अलग-अलग जगहों के बारे में किन्हीं माननीय सदस्यों को

कोई सूचना, कोई जानकारी या कोई पूरक सामग्री देनी हो तो आपलोग माननीय मंत्री को उपलब्ध करा दीजियेगा, सरकार उसपर संज्ञान लेकर जॉच में शामिल कर लेगी ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : महोदय, बक्सर किला .....

अध्यक्ष : ठीक है, प्रश्न सं0-2175 ।

तारांकित प्रश्न सं0-2175 (डॉ0 सी0एन0 गुप्ता)

श्री मुनेश्वर चौधरी,मंत्री : महोदय, 1. का उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । जिला पदाधिकारी, छपरा से प्राप्त पत्रांक-743 खनन दिनांक 05.10.2016 एवं खनन विभाग का जॉच प्रतिवेदन पत्र सं0-4101 दिनांक 20.12.2016 द्वारा प्रधान सचिव,गृह विभाग पत्र सं0-4102 दिनांक 20.12.2016 द्वारा प्रधान सचिव,परिवहन विभाग तथा पत्र सं0-4106 दिनांक 20.12.2016 द्वारा पुलिस महानिदेशक को भेजा गया था ।

महोदय, इस संदर्भ में गृह विभाग के द्वारा पूरे मामले की जॉच निगरानी विभाग को सौंप दी गई है, इसका फलाफल अभी अप्राप्त है । वर्तमान में जिला पदाधिकारी, छपरा ने अपने पत्रांक-113एम0 दिनांक 18.03.2017 द्वारा सूचित किया है कि सारण जिलान्तर्गत कहीं भी किसी भी घाट पर अवैध रूप से बालू का खनन व्यवसाय नहीं चल रहा है । बालू बन्दोबस्ती पदाधिकारी द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् विधिवत बालू घाटों का संचालन किया जा रहा है ।

2. उत्तर उपरोक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

डॉ0 सी0एन0गुप्ता : महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि क्या विभाग में टास्क फोर्स की बैठक का प्रावधान है और जो कोडिंग 20रू0 एवं 10रू0 का किया गया था, उसका क्या औचित्य है, उसका क्या मकसद है, यह सदन आपसे जानना चाहेगी?

श्री मुनेश्वर चौधरी,मंत्री : महोदय, बालू की अवैध उत्खनन के संदर्भ, पत्थर के अवैध उत्खनन के संदर्भ में, राज्य के संवर्द्धन के संबंध में ईट भट्ठा संबंधी कार्यों के देखने के क्रम में पूरे राज्य के सभी जिलों के कलक्टर के अध्यक्षता में टास्क फोर्स समिति गठित है, जिसको समिति देखती है और संचालन करती है । पारदर्शिता बरतने के लिए कमिटी हर महीने बैठती है और उसका मुल्यांकन करती है ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने सदन में यह बताया है, जो रिपोर्ट है, उसमें कहा गया है कि वहां अवैध खनन बन्द है और नहीं हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से सूचना देने के लिए खड़ा हूँ कि अवैध खनन का व्यापार चल रहा है, कहीं कोई रोक नहीं लगी है ? क्या माननीय मंत्री जी से विशेष रूप से यहां से कोई टास्क फोर्स

भेजकर जॉच कराना चाहेंगे और यदि जॉच में कुछ पाया जाता है तो उसपर सरकार कोई कड़ी कार्रवाई करने की मंशा रखती है ?

श्री मुनेश्वर चौधरी,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि सरकार के संज्ञान में इस तरह की जानकारी नहीं हे, जो सरकार के संज्ञान में जानकारी है , उसके तहत मैंने बताया सरकार को इस तरह की जानकारी नहीं है .....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सरकार को जानकारी दे रहे हैं, आप इसकी जॉच करा लीजिए ।

श्री मुनेश्वर चौधरी,मंत्री : महोदय, मैं बताना चाहता हूँ सदन को कि सारण जिला में 10 घाटों के निलामी की स्वीकृति है और 7 घाटों का ए0सी0 प्राप्त है, उन घाटों से वैद्य रूप से खनन हो रहा है और 4 भंडारण के कार्य का रजिस्ट्रेशन है और वहां भंडारण हो रहा है और वहां खनन हो रहा है ।

अध्यक्ष : ठीक है, 2176 ।

श्री मुनेश्वर चौधरी,मंत्री : महोदय,महोदय, मैं माननीय सदस्य को संतुष्ट करना चाहता हूँ कि यदि माननीय सदस्य जिन बातों को यहां रखने का काम कर रहे हैं .....

अध्यक्ष : आप संतुष्ट हैं कि आप उनको संतुष्ट कर दीजियेगा । प्रश्न सं0-2176 ।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी स्पष्ट क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि वहां पर कुछ लोगों को अनुज्ञप्ति दी गई है, एग्रीमेंट हुआ है, कुछ लोग उसके माध्यम से कर रहे हैं । जो गलत कर रहे हैं, आप सूचना दीजियेगा, उसपर सरकार कार्रवाई करेगी, सीधी बात है, अब इसमें क्या चाहते हैं?

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, अब तो हम सदन में खड़े होकर सूचना दे रहे हैं ।

अध्यक्ष : नहीं, यह सूचना से नहीं न होती है । आप कह दीजिये एक बार में कि समूचे बिहार में गड़बड़ हो रहा है, सरकार कहां-कहां क्या करेगी, उसकी कोई स्पेसिफिक सूचना होती है। आप सूचना दे दीजियेगा । चलिये सचीन्द्र प्रसाद सिंह जी का उत्तर, शिक्षा विभाग ।

टर्न-6/अंजनी/दि0 21.03.2017

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2176(श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह)</u>

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, क- बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 एवं तद्आलोक में अधिसूचित नियमावली 2011 के तहत प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वैसे प्रत्येक बसावट-क्षेत्र जहां 06से14 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या कम-से-कम 40(चालीस) हो, के 01 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत किया जाना है ।

ख- वस्तुस्थिति यह है कि पूर्वी चम्पारण जिला के कल्याणपुर प्रखंड के परसौनी वाजीद पंचायत के अनुसूचित जाति बस्ती वार्ड नं0-7 मध्य विद्यालय कटहरिया के पोषक क्षेत्र में आता है, जिसकी दूरी लगभग 600 मीटर है ।

ग- उपर्युक्त कंडिकाओं में उत्तर सन्निहित है ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, यह अनूसूचित जाति के बच्चों के भविष्य का मामला है, यहां सरकार को विद्यालय खोलना चाहिए ।

तारांकित प्रश्न सं0-2177(श्री सुधीर कुमार उर्फ बन्टी चौधरी)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार की वर्त्तमान नीति के तहत सिर्फ उन्हीं अनुमंडलों में सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने की योजना है, जहां पूर्व से अंगीभूत डिग्री महाविद्यालय संचालित नहीं है । जमुई का अलीगंज प्रखंड जमुई अनुमंडल के क्षेत्रान्तर्गत है, जहां पूर्व से ही के0के0एम0 कॉलेज, जमुई एक अंगीभूत महाविद्यालय के रूप में संचालित हो रहा है । प्रखंडवार सरकारी डिग्री महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है । जिन प्रखंडों में डिग्री कॉलेज संचालित नहीं है, वहां विश्वविद्यालयों के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत अध्ययन केन्द्र खोला जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न सं0-2178(श्रीमती बेबी कुमारी)

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक 216 दिनांक 18.03.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि राजकीय अम्बेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, रजवाड़ा में लो-वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु विद्यालय में ट्रांसफर्मर लगाने हेतु मुजफ्फरपुर विद्युत वितरण लिमिटेड(एस्सेल) को निदेशित किया गया है ।

विद्यालय में स्नातक शिक्षकों के कुल स्वीकृत पद 9 के विरूद्ध 7 शिक्षक कार्यरत हैं । अनिवार्य विषयों के सभी शिक्षक पदस्थापित हैं, सिर्फ शारीरिक शिक्षक एवं संगीत विषय के शिक्षक पदस्थापित नहीं हैं ।

विभागीय पत्रांक 5531 दिनांक 26.09.2016 द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गयी है । साथ-ही स्नातक शिक्षक के पद से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है ।

विद्यालय में कुल 32 शौचालय स्थापित हैं, जिसका उपयोग छात्राओं द्वारा किया जाता है । कुल 4 शौचालय टंकी स्थापित है, जिसमें एक टंकी क्षतिग्रस्त है,

जिसकी मरम्मति हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया है ।

विद्यालय में पानी की अपूर्त्ति हेतु पानी टंकी स्थापित है । मुख्य छात्रावास भवन में पानी की आपूर्त्ति में कोई कठिनाई नहीं है एवं सभी नल चालू है । सिर्फ शिक्षक आवास के लिए निर्मित भवन में पानी का पाईप लाईन क्षतिग्रस्त है, जिसकी मरम्मति हेतु कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को निदेशित किया गया है।

राजकीय अम्बेदकर आवासीय विद्यालय, राजवाड़ा में 100 आसन वाले नये छात्रावास का निर्माण कराया गया है ।

श्रीमती बेबी कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि एक समय-सीमा तय किया जाय क्योंकि स्कूल की स्थिति बहुत ही दयनीय है ।

श्री संतोष कुमार निराला, मंत्री : महोदय, सारे कामों को जो क्षति है, उसके संबंध में निदेशित कर दिया गया है, एक-दो महीना में इसको बना देंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-2179(श्री केदार प्रसाद गुप्ता)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में सभी नियोजित शिक्षक/शिक्षिकाओं का नियोजन एवं सेवाशर्त्त नियमावली 2012 के प्रावधान के अनुसार उनका स्थानान्तरण नहीं किया जाना है । उन्हें अपने सेवाकाल तीन वर्षों के बाद अपने नियोजन इकाई में ही अधिकतम दो स्थानान्तरण लेने की सुविधा प्राप्त है । किन्तु दो स्थानान्तरणों के बीच पांच वर्षों का अन्तराल आवश्यक शर्त्त है । इस प्रकार शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का इच्छानुकूल स्थानान्तरण उनके अपने नियोजन के अंतर्गत ही अवस्थित विद्यालय में नियमानुसार हो सकता है ।

जहां तक नियोजित शिक्षकों के अन्तर-नियोजन इकाई एवं अन्तर-जिला स्थानान्तरण का प्रश्न है, तो कहना है कि विभागीय संकल्प सं0-1529 दिनांक 11.08.2015 के द्वारा नियोजित शिक्षकों के नये सेवा शर्त्त के निर्धारण हेतु वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव/सचिव एवं प्रधान अपर महाधिवक्ता की एक समिति गठित की गयी है । इस समिति के द्वारा प्रश्नगत स्थानान्तरण के विन्दु पर भी विचार कर अनुशंसा किया जाना अपेक्षित है, तदोपरांत विभाग के स्तर पर अनुवर्त्ती कार्रवाई की जायेगी ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है । जिस समय शिक्षिकायें की बहाली हुई थी उनका नहिरा था अपने गांव में या अपने प्रखंड में.....

अध्यक्ष : सब आपके प्रश्न में सन्निहित है । मंत्री जी ने कहा है कि विभिन्न विभागों के प्रधान सचिवों की समिति बनाकर इसपर विचार किया जाना है । अब क्या पूरक है ?

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदय, मामला गंभीर इसलिए है कि बहुत शिक्षिकायें की शादी छूटने में लगी है चूंकि ससुराल से आना पड़ता है उनको पढ़ाई कराने के लिए और ऐसी स्थिति में या तो पति को छोड़े या नौकरी को छोड़े, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि यथाशीघ्र वैसे शिक्षिकाओं के लिए एक जल्द स्थांतरण की व्यवस्था करे ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया । सही में शादी हो गयी दूसरे जिला में, एक समय-सीमा बांध दें क्योंकि बड़ी परेशानी है । अगर महिला नवादा की है और शादी हुआ है पटना में तो पटना से डेली उनको नवादा जाना पड़ता है । उसी तरह से अन्य जिलों में तो हम चाहेंगे माननीय मंत्री जी से कि एक समय-सीमा बांधकर इसपर एक सार्थक पहल करना चाहिए और सार्थक निर्णय करना चाहिए ।

अध्यक्ष : मंत्री जी सूचना ग्रहण कर लीजिए ।

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, ये इशू है सर, खासकर फीमेल टीचर के साथ, मगर हमारे साथ समस्या यह है कि हमलोगों ने जो नियोजन इकाई बनायी है, वह पंचायतस्तर है, नगरस्तर है । कोई व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में एप्वाईंटमेंट है तो उसको बिहार में हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं ? तो यह एक लीगल इशू है लेकिन फिर भी हमने सेवाशर्त्त में किस तरह से इसको इनकौरपोरेट करे, उसके लिए एक कमिटी बनी हुई है, कमिटी उसका अध्ययन कर रही है, जिसमें अपर महाधिवक्ता भी हैं, जब कमिटी रिपोर्ट देगी तो हमलोग उसपर विचार करेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-2180(श्री सुबोध राय)

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री दिगम्बर प्रसाद मंडल, प्रभारी प्रधानाध्यापक, धनिक लाल मंडल उच्च विद्यालय, पिपरौन लौकही प्रखंड, जिला मधुबनी से प्राप्त परिवाद पत्र की जांच दिनांक 15.03. 2017 को उनके द्वारा स्वयं की गयी है ।

श्री सुबोध राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा यह जांच करायी गयी है लेकिन मेरी पूरी जानकारी है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जांच नहीं करके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से जांच करायी गयी है । महोदय, गंभीर आरोप लगाये गये हैं उस कॉलेज के जो एक किरानी है राजकुमार नवित, उन्होंने कितना घपलेवाजी किया है और कितना जाली विपत्रों पर दस्तखत कराने का प्रयास किया, जिसका रिफ्युज करने पर दिगंबर प्रसाद मंडल के खिलाफ कार्रवाई

हुई है तो इसलिए उन्होंने मांग किया था कि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बिहार से तब वहां से जो प्रश्नगत पत्र में अंकित है, उसके मुताबिक जांच का आदेश दिया था जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि वे स्वयं जांच करें लेकिन उन्होंने स्वयं जांच नहीं किया था और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से जांच कराया, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार जिला शिक्षा पदाधिकारी से नहीं जांच कराकर जिला पदाधिकारी या आर0डी0डी0 से जांच कराना चाहती है ?

श्री अशोक चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य अगर आर0डी0डी0 से जांच कराने से संतुष्ट हैं तो हम आर0डी0डी0 से जांच करा देते हैं ।

टर्न-7/शंभु/21.03.17

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 21 मार्च, 2017 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री मिथिलेश तिवारी, श्री विजय कुमार खेमका, श्री विद्यासागर केशरी, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री ललन पासवान, श्री राणा रणधीर, श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार सिन्हा । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण सभी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं को अमान्य किया जाता है। शून्यकाल ।

(व्यवधान)

अब शून्यकाल होने दीजिए न।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, महत्वपूर्ण है कि वित्त रहित शिक्षा कर्मी जो बिहार में हैं- उनको इंटर के विद्यार्थियों के कॉपी का मूल्यांकन जो करना था, 14 लाख विद्यार्थी बिहार में हैं, वित्त रहित शिक्षक जो है, शिक्षकेत्तर कर्मचारी जो हैं वे समान काम समान वेतन की मांग को लेकर के हड़ताल पर चले गये हैं, जिसके कारण 14 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया है, सात दिन होने जा रहा है। सरकार से हमारा आपके माध्यम से आग्रह है कि सरकार इसपर वक्तव्य दे, उनका हड़ताल समाप्त कराये। महोदय, दूसरा एक इम्पोर्टेंट विषय है होमगार्ड का- होमगार्ड के जवान भी समान काम समान वेतन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : महोदय, मैं आपके माध्यम से नेता प्रतिपक्ष से जानना चाहता हूँ कि कार्य स्थगन प्रस्ताव उठाने का क्या नियम है। कार्य स्थगन जिस दिन से यह हाऊस आहूत हुआ है एक दो दिन पहले दिनों को छोड़कर लगातार कार्य स्थगन प्रस्ताव आ रहे हैं और कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने का जो नियमावली है उस नियमावली में स्पष्ट कहा गया है।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय, शिक्षा मंत्री जी यहां पर हैं.....

अध्यक्ष : क्या मंत्री जी, कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष की बात पर हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने औलरेडी इसपर संज्ञान लिया हुआ है। 2 अरब 85 करोड़ पहले हमलोगों ने रिलीज किया था, 3 साल के लिए लगभग 5 अरब 85 करोड़ की आवश्यकता थी। कल ही हमलोगों ने बाकी का जो पैसा है करीब-करीब 3 अरब रूपया बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को रिलीज किया है। अध्यक्ष और प्रधान सचिव के साथ हमने तीन दिन पहले बैठक की है और बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 31 मई डेडलाइन दिया गया है और जो प्रावधान है उसको भी हमलोगों ने शिथिल किया है- पहले था कि प्रबंध समिति को हम पैसा रिलीज करते थे और प्रबंध समिति पैसा रिलीज करने के बाद भी शिक्षकों के उपर मनमानी करता था। इसलिए हमलोगों ने कहा है कि अभी जो नियम है उसके हिसाब से एक हफ्ता के अंदर टीचर को पैसा रिलीज करना है। अगर एक हफ्ते के अंदर रिलीज नहीं करते हैं तो उनको एक सप्ताह का हम और समय देंगे। उसके बाद प्रबंध समिति को हम स्वत: बंद करेंगे और वहां के डी0इ0ओ0 को स्टैब्लिश करके हम पैसा रिलीज करायेंगे, शिक्षकों के खाते में देंगे और बाकी जो तीन महीने का वित्त रहित शिक्षकों का पैसा बाकी है वह आनेवाले वित्तीय वर्ष में हम इसको पूरा करायेंगे।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल । श्री शमीम अहमद ।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय.....

अध्यक्ष : अब तो आपका संज्ञान लिया गया, अब आगे शून्यकाल चलने दीजिए न।

श्री अशोक चौधरी,मंत्री : जो हमारे वित्त रहित शिक्षक संघ हैं उनके साथ साढ़े 5 बजे का टाइम औलरेडी फिक्स है।

अध्यक्ष : ठीक है। श्री शमीम अहमद।

शून्यकाल

श्री शमीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत रक्सौल अनुमंडल में दिनांक 20.03.17 को भारी बारिश एवं ओला से रब्बी फसल का काफी नुकसान हुआ है। अतः सरकार से मांग करता हूँ कि क्षतिग्रस्त का फसलों का मुआवजा चिन्हित किसानों को मिले।

श्री अमीत कुमार : सीतामढ़ी जिला में ट्रॉमा सेंटर नहीं रहने के कारण गंभीर घायल मरीजों को चिकित्सा हेतु 70 कि0मी0 दूर मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है। चिकित्सा के अभाव में मरीज रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। अतः सरकार एन0एच0 77 के रमनगरा में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना की जाय।

श्री विनोद प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के सगाही से बेला होते हुए गरीबचक तक साढ़े 5 कि0मी0 सड़क काफी जर्जर है। विभाग के निदेशानुसार कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल शेरघाटी ने फिजिबलिटी रिपोर्ट विभाग को कार्यान्वयन हेतु भेजा है। ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण में अधिगृहित कर अविलंब निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, गोपालगंज जिला अन्तर्गत बरौली प्रखंड के आलापुर पीच से कटहरी बाड़ी होते हुए बांध के किनारे बतरदेह पीच रोड तक जानेवाली सड़क काफी जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण आमजनों को आनेजाने में काफी कठिनाई होती है। अतः सरकार उक्त सड़क का निर्माण जनहित में अतिशीघ्र करावे।

श्री लाल बाबू राम : महोदय, मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड में प्राथमिक विद्यालय बाजी राउत को मध्य विद्यालय सुन्दरपुर में टैग है, जबकि प्राथमिक विद्यालय का अपना बिहार सरकार की जमीन है। जिसका खाता नं0-214, खेसरा-391, रकबा-120 डि0 है। प्राथमिक विद्यालय बाजी राउत को पूर्व के स्थान पर चलाया जाय।

श्री ललन पासवान : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत नौहट्टा प्रखंड के जमुआं से सोन नदी के जानेवाली सड़क में बाढ़ से 2 पुल बह गया है, जिससे आवागमन बंद हो गया है। सरकार से मांग करते हैं कि उक्त दोनों पुल को जल्द से जल्द बनावे।

श्रीमती अमिता भूषण : महोदय, संपूर्ण बिहार के वित्तरहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर इंटरमीडियेट परीक्षा के मूल्यांकन का बहिष्कार, विभिन्न मूल्यांकन केन्द्रों पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से कर रहे हैं।

अध्यक्ष : अब तो सरकार ने उत्तर भी दे दिया।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत बारूण प्रखंड के जोगिया जम्होर रोड में कांस तिवारी बिगहा के पास बटाने नदी में पुल न होने से जनता को आवागमन में भारी कठिनाई होती है। मैं सरकार से बारूण प्रखंड के जोगिया जम्होर रोड में बटाने नदी पर शीघ्र पुल निर्माण कराने की मांग करता हूँ।

श्री समीर कुमार महासेठ : अध्यक्ष महोदय, पूर्व में सूरी जाति ओबीसी-2 में था, परन्तु आजकल कंप्यूटर के साफ्टवेयर से सूरी नाम ही डिलिट हो गया है। फलस्वरूप सूरी का जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पा रहा है। अतः पूर्ववत् ओबीसी-2 के तहत सूरी का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, इन्टरमीडियेट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच बिहार में मैट्रिक के शिक्षक कर रहे हैं। साथ ही मैथिली के शिक्षक को हिन्दी तथा कई स्वर्गवासी शिक्षकों को भी उत्तर पुस्तिकाओं की जॉच हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अधिकृत कर दिया है। मामले की उच्चस्तरीय जॉच कर कार्रवाई की जाय।

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, भोजपुर जिला में जिला में प्रधानाध्यापक (नियमित शिक्षक) के पद पर प्रोन्नति नहीं किया गया है, जबकि बिहार सरकार के ज्ञापांक-576, दिनांक 11.06.2011 एवं ज्ञापांक सं0-102, दिनांक 30.09.2013 तथा अवमानना वाद सं0-1130/2016 में पारित न्यायादेश के आलोक में प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति देनी है। अतएव मैं सदन के माध्यम से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति की मांग करता हूँ।

श्री अशोक कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। कैमूर जिला के दुर्गावती प्रखंड के अन्तर्गत कर्मनाशा स्टेशन रोड में नाली नहीं होने से मेन सड़क पर गंदा पानी जमा रहता है। जिससे आम जनता को काफी परेशानी होती है। मैं कर्मनाशा स्टेशन रोड में नाली बनाने की सरकार से मांग करता हूँ।

अध्यक्ष : श्री रत्नेश सदा (मा0 सदस्य अनुपस्थित)

श्री आनन्द शंकर सिंह : अध्यक्ष महोदय, औरंगाबाद जिला अन्तर्गत औरंगाबाद प्रखंड के परसडीह पंचायत के दोसमा ग्राम के समीप नदी पर पुल क्षतिग्रस्त हो जाने से रफीगंज मुख्यालय को जोड़नेवाली सड़क पर आवागमन ठप है। दर्जनों के गांव के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण चचरी का पुल बनाकर आरपार होते हैं जिससे दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अतः आग्रह है कि दोसमा ग्राम के समीप नदी पर पुल बनाकर जल्द से जल्द आवागमन बहाल कराया जाय।

टर्न-8/अशोक/21.03.2017

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में एन.एच.327E से निकल कर बगुलाहावाली नहर से जगता-खरसाही जाने वाली पथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया हैं । उक्त सड़क की मरम्मति कराने के लिए मैं सरकार से मॉग करता हूँ ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, नालन्दा जिलान्तर्गत हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल मात्र तीस बेड का है। आई.सी.यू. तथा अल्ट्रासाऊन्ड की व्यवस्था भी नहीं है । सरकार की घोषणा है कि अनुमंडलीय अस्पताल को सौ बेड में बदला जायेगा ।

अतः हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल को सौ बेड में बदलने तथा आई.सी.यू. एवं अल्ट्रासाऊन्ड की व्यवस्था करने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत कोचस प्रखण्ड के कुछिला गॉव में पावर सब स्टेशन का 80 प्रतिशत निर्माण कार्य पांच साल पूर्व में हो गया था । केवल 20 प्रतिशत कार्य नहीं होने के कारण इस पावर सब स्टेशन से विद्युत आपूर्त्ति नहीं होता है ।

सरकार से मांग करता हूँ कि उपर्युक्त पावर सब स्टेशन का निर्माण कार्य याथा शीघ्र पूर्ण कराया जाय ।

श्री रामदेव राय : महोदय, बेगूसराय जिला के बछवाड़ा प्रखण्ड स्थित 'रूदौली' बलान नदी पर पुल की स्वीकृति प्राथमिकता के आधार पर मुख्यमंत्री पुल योजना से गत वर्ष ही दी गई, परन्तु अबतक कार्य प्रारम्भ हीं होने से आमजनों में निराशा हो गई है । अतएव सरकार अविलम्ब पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ करे ।

श्री बिरेन्द्र कुमार सिन्हा : महोदय, औरंगाबाद जिलान्तर्गत ओबरा प्रखंड के गैनी पंचायत के ग्राम-अरी में नाला पर पुल बन जाने से लगभग दर्जनों गांव के आवागमन में काफी सुविधा होगी । क्योंकि इस पुल के वगैर लगभग दर्जनों गांव आवागमन की सुविधा से आजतक वंचित हैं ।

इतः इस गंभीर विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये इस पुल को बनाने की मांग करता हूँ ।

श्रीमती बेबी कुमारी : महोदय, जिला मुजफ्फरपुर के प्रखंड मुशहरी के शहबाजपुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्या मोनी कुमारी के पति प्रशांत कुमार की हत्या दिनांक 25.12.2016 को हुई थी, उक्त घटना में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है ।

मैं सरकार से घटना के कारण का उद्भेदन एवं दोषी की गिरफ्तारी के साथ-साथ पंचायत समिति सदस्या को सरकारी मुआवजा की मांग करती हूँ ।

श्री सुबोध राय : महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत सुल्तानगंज प्रखंड के उद्याडीह गांव में 2015 से ही उप-स्वास्थ्य केन्द्र का नवनिर्मित भवन बनकर तैयार है ।

अतः उपरोक्त भवन में चिकित्सा कार्य शीघ्र चालू कराने हेतु मैं सरकार से मॉग करता हूँ ।

श्री विजय कुमार खेमका : अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया सहित बिहार के सभी 73 इन्टर मूल्यांकन केन्द्रों पर वित्तरहित और अनुदानित कॉलेज तथा स्कूलों के शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में .....

अध्यक्ष : इसका तो निदान हो गया है ।

श्री विजय कुमार खेमका : इन्टर मूल्यांकन का वहिष्कार करने से अब तक 10 लाख उत्तर पुस्तिका की मूल्यांकन जांच पूर्ण तरह से प्रभावित है । अतः मैं सरकार से वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा, बिहार राज्य इन्टरमीडियट शिक्षक और शिक्षकोत्तर

कर्मचारी महासंघ से बात कर उनकी मांगों को पूरा कराने तथा मूल्यांकन कार्य ससयम पूरा कराने की मांग करता हूँ ।

श्री नीरज कुमार : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिलान्तर्गत बरारी प्रखंड के निवासियों को जमीन रजिस्ट्री, शपथपत्र इत्यादि कार्यो के लिए कटिहार अनुमण्डल जाना पड़ता है जिससे बरारी, समेली, कुर्सेला, फलका एवं कोढ़ा प्रखंड के निवासियों को काफी परेशानी होती है ।

अतः बरारी प्रखंड को अनुमंडल का दर्जा देने हेतु सरकार से मांग करता हूँ ।

श्री सुदामा प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, महागठबन्धन व राजग के बड़े नेताओं के बागमती बांध निर्माण कार्य पर स्थायी रोक लगाने के आश्वासन के बावजूद जबरदस्ती बांध निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाने वाले संवेदक पर मुकदमा दर्ज करने और उसकी गिरफ्तारी की मांग करता हूँ ।

श्री महबूब आलम : 46 साल पुराने निर्माणाधीन बागमती बांध पर चोरी छुपे बांध निर्माण कार्य के आरंभ होने से 19 मार्च को महेशवारा में जनता का गुस्सा फूट पड़ा और निर्माण कार्य का विरोध करने पर ग्रामीणों पर फर्जी मुकदमा लाद दिया गया । बांध निर्माण पर रोक लगाने और फर्जी मुकदमे की वापसी की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री सत्यदेव राम ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, अभी हमारे पार्टी के विधायक दल के नेता श्री महबूब आलम का महत्वपूर्ण सवाल है ....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपका शून्य काल महत्वपूर्ण नहीं है ? आपको अपना शून्य काल को पढ़ना है या नहीं या अगले माननीय सदस्य को बुलायें ।

श्री सत्यदेव राम : मैं अपना पढ़ूंगा महोदय ।

अध्यक्ष : आप अपनी शून्यकाल की सूचना को पढ़िये जिसमें आपने गुठनी प्रखंड का मामला दिया है । आप अपना मामला पढ़िये ।

श्री सुदामा प्रसाद : महोदय,...

अध्यक्ष : फिर आप महोदय कह रहे हैं, अब रखिये न उसको ।

(व्यवधान)

आप अपने नेता को नहीं बोलने दे रहे हैं ।

श्री सत्यदेव राम : जी मैं बोल देता हूँ, महत्वपूर्ण सवाल है । सिवान जिलान्तर्गत गुठनी प्रखंड के ग्राम गुठनी में जलापूर्त्ति योजना पहले से लागू हो चुकी है लेकिन हर घर में नल का जल . .. . . .

(इस अवसर पर भाकपा (माले) के तीनों माननीय सदस्यगण हाथ में तख्ती लिये हुये वेल में चले आये)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : महबूब आलम जी, सुदामा प्रसाद जी आपलोग तख्ती को बाहर कीजिये नहीं तो उसको खिंचवाना पड़ेगा । सत्यदेव जी आप तख्ती बाहर कीजिये नहीं तो हमको उसको खिंचवाना पड़ेगा । आप उसको बाहर करिये, यह गलत बात है जब आपको हमने अपनी बात कहने का पूरा अवसर दिया तब आप दूसरे को क्यों बाधित कर रहें हैं ? यह गलत बात है, आप उसको या तो स्वयं, मेरा अनुरोध है कि आप स्वयं अपना प्ले-कार्ड लेकर उसको बाहर रख दीजिये, नहीं तो मजबूरन मुझे दूसरे से उसको बाहर कराना पड़ेगा, आप उसको बाहर कर दीजिये । ठीक है, आप जाकर बैठिये, जाकर बैठिये, जाकर बैठिये । इनका कागज ले लीजिये।

(इस अवसर पर सुरक्षा प्रहरी के द्वारा माननीय सदस्यों के हाथ से प्ले-कार्ड ले लिया गया)

(व्यवधान)

चलिये, आप लोग बैठिये अपनी जगह पर ।

अध्यक्ष : श्री विद्या सागर केशरी ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज प्रखंड के कुखमाहा पंचायत के आमगाछी मौजा की जमीन, जिसका 1990 के दशक में पूर्ण चकबन्दी कर ली गई थी । उक्त मौजा के चकखाता संख्या-45, चकखेसरा संख्या-157 के बोर्डर रोड में भू अर्जित की गयी जमीन की, मुआवजा की राशि, चकभूधारी को जल्द भुगतान हेतु सदन से मांग करता हूँ ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के प्रखण्ड मधुबन, पकड़ीदयाल तथा फेनहारा में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर स्थाई प्रतिनियुक्ति नही होने के कारण विकास कार्य पर बुरा असर पड़ रहा है । विकास कार्य ठप्प हो गया हैं । मैं तीनों प्रखण्डों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पदस्थापना की मांग सरकार से करता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा : महोदय, लखीसराय जिला में बाढ़ पीड़ित किसानों का सूची चार महीने पहले बनाया गया लेकिन बाढ़ से हुई फसल नुकसान एवं बाढ़ रहत की राशि नहीं मिला हैं जिसके कारण चार दिनों से लोग धरना पर हैं ।

अतः सरकार किसानों के फसल क्षतिपूर्त्ति एवं बाढ़ राहत की राशि अविलम्ब उपलब्ध करावें ।

श्री शत्रुघ्न तिवारी : अध्यक्ष महोदय, छपरा के मढ़ौरा अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा व्यापक स्तर पर राशन, किरासन का कालाबाजारी किया जा रहा हैं । विगत दिनों अमौर प्रखण्ड में शेखपुरा के पास एस.आई के द्वारा 2 पीकेट अनाज के साथ जप्त की गई थी जो पूरी तरह भरी हुई थी, अनुमण्डल पदाधिकारी और थाना प्रभारी की मिली भगत से

इस मामला को रफा दफा कर दिया गया है, यह अनाज गरीब लोगों के लिए था, अनुमण्डल पदाधिकारी की मिली भगत के कारण क्षेत्र की जनता को राशन, किरासन नहीं मिलता है ।

अध्यक्ष : ठीक है । शून्य काल समाप्त हुआ । अब ध्यानाकर्षण लिये जायेंगे ।

टर्न-09/ज्योति

21-03-2017

ध्यानाकर्षण-सूचनाएं एवं उसपर सरकारी का वक्व्य

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव एवं अन्य मा0 सदस्यों की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार (कृषि विभाग) की ओर से वक्तव्य

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, कृषि । ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ी हुई है, अब सरकार का उत्तर ।

श्री राम विचार राय, मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कृषि रोड मैप के अधीन मूंग की खेती को दो उद्देश्यों से बढ़ावा दी जाती है । पहला दाल के उत्पादन के लिए दूसरा खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए । दाल उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना चलायी जा रही है । इस योजना में भारत सरकार के प्रावधान के अनुसार प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है । किसान स्वयं बीज खरीदते हैं । राज्य सरकार अनुदान की राशि 80 (अस्सी) प्रतिशत अधिकतम 120 (एक सौ बीस) रुपये प्रति किलोग्राम खाते में भेज दी जाती है। इस योजना में इस वर्ष 10000 (दस हजार) क्विंटल बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है । इसके विरुद्ध अब तक जिलों में 3029 (तीन हजार उनतीस) क्विंटल उपलब्ध कराया जा चुका है।

खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा हरी चादर योजना चलायी जाती है । इस योजना में बीज की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम द्वारा की जाती है । किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराया जाता है । बिहार राज्य बीज निगम को अनुदान की राशि राज्य सरकार द्वारा विमुक्त की जाती है। बिहार राज्य बीज निगम द्वारा हरी चादर योजना के अधीन मूंग एवं ढैचा के बीज हेतु निविदा आमंत्रित की गयी । निविदा दिनॉक 28-02-2017 को खोली गयी । अंतिम तिथि तक राष्ट्रीय बीज निगम से मात्र एक निविदा प्राप्त हुई । एक मात्र निविदा प्राप्त होने कारण वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या -एम0-04-12/ 2015-7806 दिनॉक 30 सितम्बर, 2016 में निहित प्रावधान के तहत विभाग द्वारा उक्त निविदा को स्वीकार नहीं किया गया

विदित हो कि एकल निविदा पर वित्त विभाग की राय नहीं मांगी गयी है। अत: वित्त विभाग की राय का प्रश्न नहीं उठता है । बिहार राज्य बीज निगम को

राष्ट्रीय बीज निगम से बिना निविदा का बीज खरीदने का दिशा-निर्देश भारत सरकार से प्राप्त नहीं है ।

वस्तुस्थिति यह है कि हरी चादर योजना में बिहार राज्य बीज निगम द्वारा ढैचा एवं मूंग बीज खरीद के लिए राष्ट्रीय बीज निगम के एकल निविदा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है । मूंग बोआई के लिए कृषि वैज्ञानिक द्वारा 10 (दस) अप्रैल तक बीज बोआई की अनुशंसा की जाती है । निविदा के माध्यम से बीज खरीद की प्रक्रिया को पूरा होने तथा किसानों तक पहुंचाने में लगने वाले समय को देखते हुए यह निश्चित किया गया कि मूंग बोआई का समय नहीं रह जायेगा । तद्नुसार हरी चादर योजना के लिए मात्र ढैचा बीज की खरीद हेतु बिहार राज्य बीज निगम द्वारा निविदा आमंत्रित किया गया है । निविदा खोलने की तिथि 24-03-2017 निर्धारित है।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, चूँकि यह मामला पूरे बिहार का है और किसानों के हित से जुड़ा हुआ सवाल है मूंग का बीज पूरे किसानों को समय सीमा के तहत बोआई के पहले उपलब्ध कराना होता है और सरकार उपलब्ध कराती है और उसमें खास करके भारत सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और सीड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा यह आवेदन दिया गया था, निविदा में भाग लिया गया था और माननीय मंत्री अपने उत्तर में इस बात को कहा कि पार्टिसिपेट जो किया है, सिंगल टेंडर के आधार पर, उनको खारिज किया गया जबकि वित्त विभाग के रुल 131 एल में जो सिंग्ल टेण्डर इक्वायरिस्ट है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि '' In case of emergency the required goods are necessarily to be purchased from a particular source and the reason for such decision is to be recorded an approval of competent authority obtatined.''

मतलब, स्पष्ट तौर पर है कि जब समय आपके पास एभेलेबुल है और हमको नियत समय में किसानों को बीज आवंटित करना है और राष्ट्रीय बीज निगम ने स्पष्ट तौर पर भारत सरकार ने पत्राचार करके राज्य सरकार को भी संसूचित किया है और नेशनल सीड कॉरपोरेशन में यह स्पष्ट है कि उनके पास प्रमाणित बीज है और उसमें राज्य सरकार ....

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, उन्होंने विस्तृत रिपोर्ट सबमिट किया है और डायरेक्टर एग्रीकल्चर और डिप्टी डायरेक्टर, एग्रीकल्चर ने जिसतरह से डिपार्टमेंट को गुमराह किया है सवाल यह उठता है कि आपने यह कह दिया अब जो है समय का नहीं है 20 अप्रैल तक दलहन की कटाई मसूर की कटाई के बाद भी किसान मूंग की बोआई करते हैं पूरे अप्रीत तक मूंग की बोआई करते हैं लेकिन इनके विभाग की अकर्मण्यता के कारण, लापरवाही के कारण अभी तक किसानों को उत्तम बीज क्वालिटी की बीज की आपूर्ति नहीं की गयी ।

अध्यक्ष : पूरक न पूछिये ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : पूरक यह है कि जब राष्ट्रीय बीज निगम के पास जब बीज उपलब्ध है और प्रमाणित बीज उपलब्ध है तो फिर उसको यह कह करके कि सिंग्ल टेण्डर है, टेण्डर का उसमें प्रावधान नहीं है अगर राष्ट्रीय बीज निगम अगर आपूर्ति सुनिश्चित करती है तो वित्त विभाग का जो संकल्प रुल है टेण्डर के मामले में 131 एल के तहत जिसको मैंने पढ़ा कि अगर आप नीड समझते हैं और अभी जरुरत है जो 7 दिन में, एक सप्ताह में एभेलेबुल करा सकता है किसानों तक परचेज करा सकता है तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री का यह कहना महोदय, ...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न ?

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : मैं पूरक पूछ रहा हूँ ।

अध्यक्ष : कहाँ पूछ रहे हैं ?

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : पूरक ही तो पूछ रहा हूं कि क्या माननीय मंत्री महोदय एक सप्ताह के अंदर आप आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे ।

श्री राम विचार राय, मंत्री : महोदय, मैंने बताया कि हमको कृषि रोड मैप के अधीन दो तरह से मूंग का हमलोग किसानों के बीच में वितरण करते हैं एक हरी चादर है और एक हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है और इस योजना के अंदर दस हजार क्वींटल का लक्ष्य है और तीन हजार मूंग हमारा पहुंच गया है जिला में और दूसरा हरी चादर है जिसको निगम के द्वारा टेण्डर कराया गया और टेण्डर में एक आदमी भाग लिया जहाँ तक माननीय सदस्य का कहना है कि एक आदमी इसमें भाग लिया और इनको वित्त विभाग भेजा गया, हमने कहा कि वित्त विभाग में नहीं भेजा गया और वित्त विभाग का ही गाईडलाईन है कि बिना टेण्डर के नहीं होगा । यह नियम का सवाल है । जब निगम खरीदेगा तो टेण्डर करेगा । बिना टेण्डर के नहीं खरीद सकता है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उनका कहना है कि आपको सिंगल टेण्डर है, उसी आधार पर राष्ट्रीय बीज निगम से लेने का विचार है ?

श्री राम विचार राय, मंत्री : ऐसा नियम नहीं है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, इन्होंने 3 हजार क्वींटल की चर्चा की 3 हजार क्वींटल बीज का इन्होंने जो किसानों तक पहुंचाया है, वह कहाँ पहुंचाया यह सवाल नंबर एक है । इन्होंने कहा कि तीन हजार क्वींटल बीज किसानों तक पहुंचाये वह कहाँ से पहुंचाए जो लक्ष्य निर्धारित है 10 हजार क्वींटल का तो विभाग की लापरवाही के कारण जब किसानों तक बीज नहीं पहुंचता है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है किस कारण से ?

अध्यक्ष : मंत्री जी ने तो साफ साफ कहा है कि दो तरीके से बीज जाता है एक खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत और दूसरा है हरी चादर के तहत । खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत

इन्होंने तीन हजार 29 क्वींटल मूंग का बीज किसानों को उपलब्ध कराया है लेकिन हरी चादर वाले में सिंगल टेण्डर हो जाने के कारण ये नहीं कर सकते हैं ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, नहीं नहीं हरी चादर पर सिंग्ल टेण्डर पर नहीं किया, सिंग्ल टेण्डर की चर्चा की है राष्ट्रीय बीज निगम का और राष्ट्रीय बीज निगम ने कहा और भारत सरकार का स्पष्ट है कि निगम से लेने के लिए टेण्डर की बाध्यता नहीं है, यह रुल स्पष्ट हैं कहें तो मैं भारत सरकार का पत्र सबमिट करता हूँ ।

श्री राम विचार राय, मंत्री : नहीं । बाध्यता है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी कह रहे हैं बाध्यता है ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, ऐसा है सिंगल टेण्डर में वित्त विभाग का यह संकल्प है 131 एल रुल है ।

अध्यक्ष : आप उसको पढ़ चुके हैं ।

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : महोदय, वही तो अर्जेन्ट मैटर है ।

अध्यक्ष : शक्ति जी, आपने रुल पढ़ा है वह सरकार का डिसक्रीशन है कि अगर सरकार चाहे तो और सरकार कह रही है कि हम वह नहीं करेंगे तब आप क्या पूछते हैं?

श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव : ठीक है, नहीं करेंगे लेकिन इस बीच में किसानों तक जो बीज नहीं पहुंच रहा है इसकी व्यवस्था ये कहाँ से करेंगे समय खत्म हो रहा है 30 अप्रील तक कैसे करेंगे महोदय, यह गंभीर सवाल है ।

श्री मो0 नवाज आलम : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि हरी क्रान्ति चादर के तहत हमने बीज को उपलब्ध कराया है लेकिन मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री को स्पष्ट तरीके से बताना चाहतें हैं कि हम अपने जिला भोजपुर में कहीं भी कोई जगह बीज नहीं पहुंचायी गयी है अगर बीज नहीं पहुंचा तो जो किसान इससे जो है कहीं न कहीं क्षतिग्रस्तम हुए क्या माननीय मंत्री जी वैसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे ?

अध्यक्ष : ठीक है । श्री मिथिलेश तिवारी सूचना पढ़िये ।

(व्यवधान)

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण । आप तीनों माननीय सदस्यगण से अनुरोध है कि कि आपने अपनी बात कह दी है, आपका मामला आपने उठा दिया है । अब तो अपनी जगह पर जाकर बैठिये और बाकी कार्य में सदन संचालन में सहयोग करिये । आपकी बात जो उठा रहे थे पूरे सदन ने गंभीरता से सुना है । सरकार ने भी गंभीरता से सुना है अब दूसरों की बात सुनने में क्यों बाधक बन रहे हैं ? आप बैठिये, जाकर बैठिये, सुनिये । मिथिलेश तिवारी ।

श्री मिथिलेश तिवारी की ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पंचायती राज विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री मिथिलेश तिवारी : महोदय, बिहार सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुगम बनाने एवं नागरिकों की सुविधा हेतु पंचायत सरकार भवन बनवाने का निर्णय लिया था । कुल 1435 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद आर्थिक प्रतिवेदन के अनुसार मात्र 637 भवनों का निर्माण किया गया, लेकिन आज तक सभी भवनों को ''हैण्ड ओवर'' नहीं किया गया है । जहॉ कुछ स्थानों पर हैण्ड ओवर किया भी गया है वहॉ कार्यालय कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है । पंचायत सरकार भवन के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु अभियंता, कर्मचारी इत्यादि की नियुक्ति आज तक नहीं की गयी है ।

अतएव सभी तैयार पंचायत सरकार भवनों में विधिवत कार्यालय कार्य प्रारम्भ करवाकर ग्रामीणों को सुगमता से सरकारी कार्य की सुविधा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।

टर्न-10/21.3.2017/बिपिन

(व्यवधान जारी)

श्री कपिल देव कामत, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा सभी पंचायतों में चरणबद्ध रूप से पंचायत सरकार भवन बनाने का प्रस्ताव है । पंचायत सरकार भवन निर्माण हेतु प्रथम चरण में राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को 1435 क्लस्टरों, पांच सौ पंचायतों का समूह में संगठित किया गया है । विभागीय निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक कलस्टर में से पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए वैसे ग्राम पंचायत का चयन किया जाना था जिसकी आबादी सबसे अधिक हो । सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा 12.37 करोड़ की लागत से 1435 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण की स्वीकृति दी गई जिसका कार्यकारी एजेंसी स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, योजना एवं विकास विभाग को बनाया गया है । 13वीं वित्त आयोग एवं राज्य योजना मद से वर्ष 2013-14 में 950 एवं वर्ष 2014-15 में 485, कुल 1435 पंचायत सरकार भवन बनाने का लक्ष्य था । इसमें से 807 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो चुका है एवं शेष का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में है । मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, बिहार, योजना एवं विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 18.3.2017 के अनुसार अब तक कुल 542 पंचायत सरकार भवनों का हस्तान्तरण किया गया है तथा जिले से प्राप्त प्रतिवेदनानुसार अब तक 215 पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील किया जा चुका है । पंचायत सरकार भवन में निर्धारित प्रतिनिधियों एवं पंचायत स्तर के कर्मचारियों तथा पंचायत सचिव, ग्राम कचहरी सचिव एवं ग्राम कचहरी न्याय मित्र के बैठने की समुचित व्यवस्था

है । विभागीय निर्देश के आलोक में सभी जिला पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को हस्तान्तरित पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील कर विधिवत् कार्य प्रारंभ करने का निदेश दिया जा चुका है तथा इसके प्रगति का अनुश्रवण विभागीय स्तर पर नियमित रूप से किया जा रहा है ।

(व्यवधान जारी)

श्री मिथिलेश तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने कहा कि 1435 पंचायत पंचायत सरकार भवनों को सरकार ने बनाने का निर्णय लिया है और लगभग 805 सरकार भवनों का उन्होंने कहा कि बन गया है । मैं माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि क्या सभी 805 जिनकी उन्होंने उल्लेख इस सदन में की है, क्या उसकी सूची सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे और क्या उन सभी पंचायत सरकार भवनों में कर्मचारी और जितने भी प्रकार के जो अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी, सरकार ने उसको कब की, कितने लोगों को की और उनको वहां प्रतिनियुक्त किया गया कि नहीं और वह कार्य संचालित हो रहा है, तो कहां-कहां कब से हो रहा है और जहां बाकी है, वहां कब से प्रारंभ करने की सरकार की योजना है ?

महोदय यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है । पंचायती राज संस्थाएं प्रभावित हो रही है और अरबों रूपया लगाकर पंचायत सरकार भवन पंचायतों में बने हुए हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री कपिल देव कामत,मंत्री: महोदय, 1435 ....

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य ने सिर्फ यही कहा है कि 1435 में, जैसा कि आपने कहा है, 807 का निर्माण कार्य पूरा हो गया है । यही आपने कहा है न !

श्री कपिल देव कामत,मंत्री: जी ।

अध्यक्ष : तो माननीय सदस्य चाहते हैं कि इसकी सूची आप सदन पटल पर उपलब्ध करा दें । ठीक है !

श्री कपिल देव कामत,मंत्री : जी ।

अध्यक्ष : और बाकी जहां पर क्रियाशील है तो है, बाकी जगह पर शीघ्र क्रियाशील करा दें तभी तो सरकार की मंशा पूरी होगी ।

श्री कपिल देव कामत,मंत्री : ठीक है ।

(इस अवसर पर वेल में पूर्व से बैठे भाकपा (माले) के माननीय सदस्यगण अपनी सीट पर चले गए)

श्री श्रवण कुमार,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों से आग्रह मैंने किया था कि सीट पर चले जाएं । माननीय सदस्य की भावना को मैं ग्रहण करता हूं और नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी ।

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय, होमगार्ड के जवान...

अध्यक्ष : होमगार्ड के जवान, इनके लिए होमगार्ड की जरूरत नहीं है । इन तीनों माननीय सदस्य के लिए होमगार्ड की आवश्यकता नहीं होती है और न पंचायत सरकार भवन के लिए होमगार्ड्स की आवश्यकता है । पंचायत सरकार भवन में तो कर्मचारी चाहिए, होमगार्ड कहां चाहिए ?

(व्यवधान)

अब होने दीजिए ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय ।

(इस अवसर पर भा.ज.पा. के माननीय सदस्यगण वेल में आकर कुछ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री लक्ष्मेश्वर राय : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य में फरवरी-मार्च, 2012 में 34540 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है । पुरूष सहायक शिक्षकों को अन्तर जिला स्थानान्तरण का लाभ सरकार द्वारा नहीं दिए जाने के कारण उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सहायक शिक्षकों की नियुक्ति गृह जिला से 300 कि0मी0 से 400 कि0मी0 की दूरी पर किया गया है ।

अत: मानवीय आधार पर सहायक शिक्षकों का पदस्थापन गृह जिला में हो इसके लिए मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।''

श्री अशोक चौधरी,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जिला संवर्ग के 34540 सहायक शिक्षकों के नियुक्ति हेतु बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 अधिसूचित किया गया है । उक्त नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त प्राधिकार की देखरेख में नियुक्ति हेतु वरीयता सूची एवं चयन सूची तैयार किया गया है । चयनित अभ्यर्थी को जिला आवंटन करने के पूर्व उनसे तीन अभिच्छा प्राप्त किया गया था । महिला एवं विकलांग अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए जिला आवंटित किया गया है । उन तीन अभिच्छा के अनुरूप रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में यथासंभव गृह जिला के नजदीक जिला आवंटित किया गया है । पदस्थापना के उपरान्त महिला शिक्षकों को उनके गृह जिला में स्थानन्तरण की कार्रवाई भी की गई । इस क्रम में 34540 कोटि के सहायक शिक्षकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण हेतु आवेदन की मांग की गई थी । इस तरह माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. संख्या-13966/2013 में दिनांक 18.5.2015 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में विभागीय पत्रांक 1325 दिनांक

23.11.2015 निर्गत किया गया है जिसमें अंकित है कि बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में नियुक्त 34540 कोटि के शिक्षकों को एकल स्थानान्तरण जिला के अंदर कर जिला के बाहर नहीं किया जाएगा । 34540 कोटि के कुल शिक्षक जिनका पदस्थापन गृह जिला में नहीं है, उनके द्वारा विभाग से यह मांग लगातार की जाती रही है कि उनके एकल अंतर जिला स्थानान्तरण के लिए नीति बनाई जाए । विभाग में ऐसे शिक्षकों के कठिनाई एवं द्वारा तनावरहित शिक्षा देने के उद्देश्य से इस कोटि के शिक्षकों के जिला के अंदर एवं अन्तर जिला स्थानान्तरण संबंधी नीति का निर्धारण करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक सं0-92 दिनांक 10.2.2017 निर्गत किया गया है जिसके आधार पर जिन पुरूष शिक्षकों की सेवा अवधि दो वर्ष या उससे कम रह गई है, गंभीर रोग से ग्रसित हैं एवं पति-पत्नी के स्थापन के आधार पर स्थानान्तरण की कार्रवाई की जाएगी ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : महोदय, 300-400 कि.मी. की दूरी पर हैं जिसके चलते वह अच्छा से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं ।

अध्यक्ष : लक्ष्मेश्वर राय जी, मंत्रीजी ने कहा है कि सरकार ने उनके मामले पर विचार करके जिनकी सेवा अवधि दो वर्ष तक की बच गई है या पति-पत्नी वाला मामला है, उसमें इन्होंने यह नियम बनाया है । अब आपका पूरक क्या है ?

श्री लक्ष्मेश्वर राय: महोदय, पति या पत्नी जो महिला थी उसको किया गया है, उसी संवर्ग में जो महिला शिक्षिका थी उसको कर दिया गया और जो पुरूष थे वे अभी वंचित हैं तो निश्चित रूप से यह क्या समान लगता है ? हमको लगता है कि यह एक नीति बनाकर बिहार सरकार को और शिक्षा देने के उद्देश्य से पुन: निश्चित रूप से गृह जिला में उनको स्थानान्तरण प्रस्ताव करना चाहिए जिससे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि बिहार सरकार निश्चित रूप से एक नीति बनावे ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ।

(व्यवधान जारी)

श्री हरिनारायण सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं समिति के सभापति की हैसियत से बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-211 के तहत् बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड से सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 190वॉ, 191वॉ, 192वॉ एवं 193वॉ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूं ।

(व्यवधान जारी)

श्री प्रेम कुमार,नेता विरोधी दल: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, हम आप ही से जानना चाहते हैं कि जिस मामले को आपने शून्यकाल के दरम्यान उठाया, सरकार ने उसका संज्ञान लेते हुए संपूर्ण स्थिति स्पष्ट कर

दी है और संतुष्ट होकर आप सभी लोग बैठ गए । फिर से उसी मामले पर यह व्यवधान का क्या औचित्य है ?

(व्यवधान जारी)

श्री प्रेम कुमार, नेता विरोधी दलः महोदय, होमगार्ड ...

अध्यक्ष : आप होमगार्ड कह रहे हैं....

(व्यवधान जारी)

श्री श्रवण कुमार,मंत्रीः महोदय, यह बार-बार व्यवधान पैदा करते हैं । इनको नियम-कानून-कायदा से कोई मतलब नहीं है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : अब सभा की बैठक 2.00बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न : 11/कृष्ण/21.03.2017

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

आज ऊर्जा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिये समय दिया जायेगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	:	59 मिनट,
जनता दल (यूनाईटेड)	:	52 मिनट,
भारतीय जनता पार्टी	:	39 मिनट,
इन्डियन नेशनल कांग्रेस	:	20 मिनट,
सी0पी0आई0(एम0एल0)	:	02 मिनट,
लोक जनशक्ति पार्टी	:	02 मिनट,
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	:	01 मिनट,
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	:	02 मिनट,
निर्दलीय	:	03 मिनट ।

प्रभारी मंत्री,ऊर्जा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

'' ऊर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च,2018 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिये 109,05,03,31,000/-(एक सौ नौ अरब पांच करोड़ तीन लाख एकतीस हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा, श्री संजय सरावगी, श्री तार किशोर प्रसाद, श्री अशोक कुमार सिंह, श्री मिथिलेश तिवारी, श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह एवं श्री विनोद कुमार सिंह से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं, जो व्यापक हैं एवं जिन पर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री अरूण कुमार सिन्हा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'' इस शीर्षक की मांग 10/–रूपये से घटाई जाय, राज्य सरकार की ऊर्जा नीति पर विचार–विमर्श करने के लिये । ''

महोदय, वर्तमान में हम सभी की मूलभूत जरूरत बिजली है और इसीलिये मुख्यमंत्री सात निश्चय में भी हर घर बिजली के तहत सभी घरों में बिजली देने का निर्णय लिया जा चुका है, जिसके तहत सभी बी0पी0एल0 एवं ग्रामीण ए0पी0एल0 परिवारों को दो वर्षों के भीतर विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है । परन्तु बी0पी0एल0 कनेक्शन देने में सरकार अपने लक्ष्य से काफी पीछे है । महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत गहन विद्युतीकरण के मामले में भी सरकार एक तरह से फिसड्डी साबित हो रही है । यही नहीं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जले एवं खराब ट्रांसफरमर जो हैं, उनको जो शीघ्र बदलना चाहिए, उसमें काफी देरी हो रही है, सरकार उसमें भी असफल है । महोदय, बिहार की राजधानी पटना है और ऐसे सभी शहरों में, आज भी, गांव की बात क्या करें, बांस पर बिजली का तार दौड़ाया जाता है और बिजली के कनेक्शन लिये गये हैं और सरकार उदासीन है । यही नहीं, महोदय, आज भी बिजली की चोरी हो रही है और जहां–तहां कभी–कभी धर–पकड़ किया जाता है, लेकिन खुलेआम चोरी हो रही है । गलत बिलिंग की शिकायत सरेआम हैं । साथ ही साथ, बिजली बिल जमा करने के बाद एक बार फिर दोबारा बिल आता है और उसका एरियर भी रहता है, जिसके कारण उपभोक्ता परेशान हैं । महोदय, बिहार में 24 जिलों में 44 पावर सब–स्टेशन का कार्य पूरा नहीं होने से निर्बाध बिजली देने का दावा विफल हो रही है । अंत में महोदय, एक डाटा के अनुसार पटना जिला में 1700 गांव, 2250 टोलों के 4.63 लाख मकानों में 5 लाख 46 हजार 154 परिवार रहते हैं, जिसमें 2 लाख 12 हजार 362 परिवारों के घरों में ही बिजली के कनेक्शन अभी तक मिले हैं । महोदय, बिहार राज्य के सभी शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली देने ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बी0पी0एल0 परिवारों एवं मुख्यमंत्री विद्युत संबंधन निश्चय योजना के तहत ए0पी0एल0 परिवारों को कनेक्शन देने में असफल हो रही है । इसलिए ऊर्जा विभाग की मांग में से 10 रूपये की कटौती का प्रस्ताव दिया हूं । आप ने समय दिया, इसके लिये आप को धन्यवाद ।

श्री राम विशुन सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा 109 अरब 5 करोड़ 3 लाख 31 हजार रूपये का जो अनुदान मांग प्रस्तुंत किया गया है, उसके पक्ष में और विपक्ष द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं तथा महागठबंधन के मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार,

गरीबों के मसीहा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद, उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, बिहार के वरीय ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी तथा प्रतिपक्ष के नेता श्री प्रेम कुमार जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं ।

महोदय, किसी भी देश, राज्य और गांव के विकास के लिये ऊर्जा का बहुत महत्व है । ऊर्जा के बिना विकास संभव नहीं है । आज पूरे विश्व में ऊर्जा के बल पर ही कल-कारखाने, छोटे-छोटे उद्योग धंधे एवं खाना बनाने से लेकर वस्त्रों में आयरन करने तक ऊर्जा की जरूरत है । महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने चुनाव के पूर्व ही घोषणा-पत्र में कहा था कि न्याय के साथ विकास का काम करेंगे और आज उसी सिद्धांत पर महागठबंधन की सरकार काम कर रही है तथा सभी वर्ग, सभी सम्प्रदाय सभी जातियों के लोगों के विकास को साथ-साथ लेकर चलने के लिये संकल्पित है । इस आधार पर कार्य के चलते न्याय के साथ विकास आधारित हम अपने संकल्प को दोहराते हुये आगे तीन-चार वर्षों में बिहार को देश के विकसित राज्यों में लाने का प्रयास कर रहा है । हमारे गठबंधन के वरिष्ठ ऊर्जा मंत्री आदरणीय विजेन्द्र प्रसाद यादव जी एवं वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी बिहार को देश की अग्रिम पंक्ति में लाने के लिये हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में रात-दिन कार्य कर रहे हैं ।

महोदय, राज्य के बंटवारे के बाद सारे उद्योग-धंधे झारखंड में चले गये थे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था परन्तु हमारे महागठबंधन के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के बद से बदत्तर स्थिति में रहने के बावजूद बहुत मंथन करने के बाद बिजली पर उन्होंने बहुत कार्य किया है, आज उसी का नतीजा है कि भारत वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में बिहार का नाम अगली पंक्ति में जाना जाता है । हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जनता के बीच में इसे स्वीकार किया है । हमारे महागठबंधन के तमाम मंत्रीगण कंधा से कंधा मिलाकर बिहार के विकास के रास्ते पर चलने के लिये तत्पर है और आगे भी चलते रहेंगे । हमारे पूर्वज बिजली के बारे में नहीं जानते थे कि बिजली क्या चीज होती है । जब हमलोग बड़े हो कर पढ़-लिख कर आगे बढ़े तो ग्रामीण विद्युत के बारे में हमलोगों ने समझा । आज बिहार सभी राज्यों में बिजली के मामले में आगे है जबकि छत्तीसगढ़ ने 97 प्रतिशत, मध्य प्रदेश ने 86 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश ने 93 प्रतिशत, उड़िसा ने 75 प्रतिशत उपलब्धि हासिल किया है जबकि हमारा राज्य ने 110 प्रतिशत उपलब्धि हासिल किया है ।

महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार 88 परसेंट ग्रामीण आबादी वाला बिहार सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रीय राज्य कहा जाता है । हमारी सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखकर हमारे बिहार के लोकप्रिय महागठबंधन के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेन्द्र

प्रसाद यादव जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने भयंकर प्रयलंकारी बाढ़ सुखाड़, ओलावृष्टि आदि को ध्यान में रख कर किसानों के हित के लिये खेतों तक बिजली की सुविधा मुहैय्या कराने के लिये एक संकल्प किया ।

क्रमश :

टर्न–12/राजेश/21.3.17

श्री राम विशुन सिंह, क्रमशः इसके लिए बहुत कम पैसे में 15 से 20 घंटे अलग से बिजली की व्यवस्था की गयी है ताकि किसानों को आर्थिक बोझ न पड़े, आज इसी का नतीजा है कि किसान के बच्चे पढ़ाई–लिखाई के मामले में, अपने खेती के बल पर, डाक्टर इंजीनियर बनकर बिहार का नाम रौशन किया है । महोदय, आज शहर के नजदीक बाढ़ एन0टी0पी0सी0 यूनिट, जिससे 850 मेगावाट बिजली अभी मिल रही है, कहलगॉव एन0टी0पी0सी0 से 435 मेगावाट मिल रही है, जिससे हमारे बिहार में उर्जा के क्षेत्र में काफी सुधार हो रहा है, वर्ष 2010–11 में 1738 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी, जो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 5000 मेगावाट की संभावना है, तो इस तरह से पॉच वर्षों में 120 प्रतिशत बिजली की बढ़ोत्तरी हुई है । आज हमारे कॉटी थर्मल पावर में भी बिजली के उत्पादन में बंद पड़े थर्मल पावर को 3942.16 करोड़ रुपये की लागत से इसका कार्य शुरु हुआ है, जो दो, एक महीना में समाप्त हो जायेगा और वहॉ से भी 500 मेगावाट बिजली तैयार होगा । बरौनी में क्षमता बिहार परियोजना के तहत 500 मेगावाट बिजली निर्माण तेजी से 5908.98 करोड़ की लागत से काम हो रहा है, हम समझते हैं, इसके हो जाने के बाद उत्तरी बिहार में बिजली उपलब्धता इतनी कायम हो जायगी, जिससे कि हमको उत्तर बिहार में बिजली देने की जरुरत नहीं होगी । उसी तरह से नवीनगर, औरंगाबाद में 660 मेगावाट की तीन यूनिट ईकाई, चौसा–बक्सर की ईकाई निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, पीरपैती, बॉका में जब बिजली का काम शुरु हो जायेगा, तो बिहार को 15 हजार मेगावाट बिजली मिलेगी, जिसके पूरा हो जाने से बिहार को बिजली उपलब्धता हो जायगी । महोदय, अक्तूबर, 2015 में पिक लोड पर 3439 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी, जो बढ़कर आज राज्य में 5000 मेगावाट हो गयी, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 7 निश्चय में एक, हर घर बिजली से राज्य के हर घरों को बिजली पहुंचाने का उद्वेश्य सभी बी0पी0एल0 परिवारों को और मुख्यमंत्री समग्र योजना के तहत दो वर्षों में सभी बी0पी0एल0 परिवारों को भी बिजली दी जायगी । महोदय, आज महागठबंधन सरकार के चलते बॉका में 2444 एकड़ जमीन चिन्हित कर लिया गया है, जिसपर हमारा प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेज दिया गया है, वहॉ से आते ही कार्य शुरु हो जायेगा तथा वहॉ से चार हजार मेगावाट बिजली प्राप्त होगी, इसपर तुरत कार्य शुरु हो जायेगा, तो महोदय

पिछले दिनों राज्य बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जायेगा, मैं खुद बिजली बेचूंगा और उससे जो राजस्व की प्राप्ति होगी, तो उससे बिहार का नाम बिजली के क्षेत्र में स्वर्ण अक्षरों में बिहार के इतिहास में लिखा जायेगा ।

महोदय, विद्युतीकरण के मामले में जो नाम पहले राजीव गॉधी विद्युतीकरण के नाम से जानते थे, आज उसको भगवा चोला पहना करके इसका नाम धार्मिक करने के लिए अपना हथकंडा अपनाने के लिए केन्द्र सरकार ने राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना का नाम हटाकर दिन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत इसका प्रचार कर रहे है, महोदय, केन्द्र से राजीव गॉधी विद्युतीकरण के तहत राज्य को पहले 90 प्रतिशत राशि मिलती थी, जबकि अब 60 प्रतिशत राशि मिल रही है, महोदय, यह बिहार के साथ सौतेला व्यवहार है, जबकि हमारा राज्य इस स्थिति में नहीं था कि हम पूरी राशि दे सके लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से ये सारे कार्य विकास की किये गये है, महोदय, केन्द्र सरकार से आज राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हमारी स्थिति थोड़ी कमजोर है लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उर्जा मंत्री जी, कई बार दिल्ली का दौरा किये लेकिन बकाया पैसा देने के लिए अभी तक कोई रुचि नहीं दिखाया है, यह कह कर कि हम बिहार सरकार को बहुत ही राशि दिये हैं, उन्होंने एक बहाना बना करके कि बिहार सरकार को पैसा नहीं देना पड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार प्रयास के बाद बड़े गॉवों में ट्रान्सफर्मर 100 का और 63 का टोले में देने का काम किया है, जो 15 और 16 पहले था, महोदय, पंडित दिनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत राज्य में 288 पावर सब-स्टेशन बनाने जा रहे है, जिसमे हमारे जिला में भी चार है, जो दिसम्बर या मार्च, 2018 तक पूरा हो जायेगा.....

(व्यवधान)

अध्यक्षः आप आप शीघ्र समाप्त कीजिये ।

श्री राम विशुन सिंहः महोदय, हम अपना समस्या कहॉ कहे सर, अपने क्षेत्र की बात कहा कहे सर, इसमें हमारा विधान सभा क्षेत्र भोजपुर में दुल्हिनगंज, हेकमपुर, कोथवा, अगियॉव बाजार में प्रस्तावित है । हमारे विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण का अभाव, कुछ पोल के अभाव में और ट्रान्सफर्मर के अभाव में रुका हुआ है । मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूँ कि 1000 पोल एवं 100 ट्रांसफर्मर दिलाने का कष्ट करें, जिससे जो गॉव, जो टोले, बचे हुए हैं, वहॉ बिजली पहुंचाया जा सके । महोदय, विगत एक वर्षों में गॉवों में विद्युतीकरण का काम बहुत ही तेजी से 8 लाख 17 हजार से बढ़ा करके आज 10 लाख 74 हजार लोगों को बिजली का कनेक्शन दिया गया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से मांग करता हूँ कि मेरे पीरो प्रखंड में मेरा एक गॉव है, जिसका नाम है मनैना, वहॉ पर ठीकेदार और इंजीनियर ने ठान लिया है कि हम वहॉ काम नहीं करेंगे, इसलिए मेरा माननीय मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से आग्रह है कि वहॉ के इंजीनियर को

काम दिया जाय चूंकि वहॉ कोथवा गॉव में लाइन चला गया है और मनैना टोला 60 घर का बस्ती है, वहॉ पर आज तक ठीकेदार जब से मैं विधायक बना, तो कहा, तो वह नहीं सुना, न ही ठीकेदार सुना और न ही इंजीनियर ने सुना, इसलिए हमारा अनुरोध है कि उस गॉव को विद्युतीकरण कराया जाय । महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री रमेश सिंह कुशवाहा ।

श्री रमेश सिंह कुशवाहा: अध्यक्ष महोदय, आज हम उर्जा विभाग के अनुदान मांग के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । आपने हमें समय दिया, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ । अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ और पहली बार मैं जीतकर आया भी हूँ .....

(व्यवधान)

अध्यक्ष: रमेश जी, आप पहली बार बोल रहे हैं, तो आप इत्मीनान से और अच्छे से बोलिये ।

श्री रमेश सिंह कुशवाहा: अध्यक्ष महोदय, जब जगदेव बाबू इस सदन में उर्जा मंत्री थे, तो उन्होंने कहा था कि बिजली जोड़ पानी बराबर समाजवाद बा, उन्होंने कहा था और आज मैं देख रहा हूँ कि पूरे बिहार में बिजली के मोर्चे पर काफी प्रगति हुई है, लग रहा है कि एक क्रांति आयी है, जब हमलोग गॉवों में जाते हैं, अपने विधान सभा क्षेत्रों में जाते हैं, दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में जाते हैं, तो लोग कहते हैं और जब बीते दिनों की चर्चा करते हैं कि बिजली के क्षेत्र में एक गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, एक क्रांति सी आयी है, लगभग 80 प्रतिशत, कई ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं, कई ऐसे प्रखंड हैं, जहॉ 95 प्रतिशत तक बिजली में प्रगति हुई है और गॉवों मे ंबिजली जल रही है । यह वर्ष शताब्दी वर्ष है, चंपारण से जो आंदोलन शुरु हुआ था, आज हम उसका शताब्दी वर्ष बना रहे हैं, महोदय, आज हमारे सामने दो तरह के मॉडल हैं, एक मॉडल गुजरात का है और एक मॉडल बिहार का है, ये दो मॉडल है, तो एक मॉडल कॉरपोरेट परस्त है और एक मॉडल जो बिहार का है, वह किसान परस्त है, हम कृषि के बारे में सोचते हैं, कृषि के विकास के बारे में सोचते हैं, तो कृषि के विकास के बिना मैं समझता हूँ कि हर प्रकार का विकास अधूरा रह जायेगा, किसानों की जब तक क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी, किसान जब तक अगली पंक्ति पर नहीं खड़े होंगे, तो उस विकास का कोई माने मतलब नहीं होगा, इस लिहाज से मैं कहना चाहता हूँ कि उर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है, उससे बिहार आने वाले दिनों में अन्य राज्यों के मुकाबले अग्रिम पंक्ति पर खड़ा होगा । अध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में दक्षिणपंथ के खतरे बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे हैं, तो जो भी लोकतांत्रिक शक्तियॉ हैं, जो भी लोकतंत्र पसंद लोग हैं, आज उनके लिए एक चिंता का विषय है, आज जिस तरह से देश के तमाम इन्सटिच्युशन को भगवाकरण करने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम लोगों को इसके खिलाफ एक लामबंद होने की

जरुरत है, जो भी इन्सटिच्युशन हैं, चाहे वह जे0एन0यू0 हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, यह हमलोगों ने देखा है रोहित वेमुला के मामले में कि किस तरह से दक्षिण पंथी ताकतें अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बोल रही है, आज बिहार से कोशिश की जा रही है कि बिहार की अगुआई में, माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुआई में इस भगवाकरण के खिलाफ देश की जो भी लोकतांत्रिक ताकतें हैं, जो भी जनवादी शक्तियॉं हैं, एक प्लेटफार्म पर खड़ा हो करके इस चुनौती को दृढ़ता से मुकाबला करें ।

क्रमशः

टर्न–13/सत्येन्द्र/21–3–17

श्री रमेश सिंह कुशवाहा(क्रमशः): अध्यक्ष महोदय, बिजली की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है, कांटी ताप विद्युत प्रतिष्ठान की क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 195 मेगावाट की दो इकाईयों के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है । राज्य योजना के अन्तर्गत बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान की क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 250 मेगावाट इकाई के नयी परियोजना का निर्माण कार्य निर्माणाधीन है जिसे नवम्बर, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है । नवीनगर में 660 मेगावाट की तीन ताप विद्युत इकाई जिनकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट है के निर्माण कार्य प्रगति पर है और जून, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । संचरण के क्षेत्र में भी उत्साहबर्द्धक उपलब्धियां हासिल हुई है । वर्तमान में 3769 मेगावाट पीक पावर में आपूर्त्ति की जा चुकी है और आपूर्त्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का प्रयास जारी है। महोदय, 31 राजस्व अनुमंडलों में ग्रीड उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है जिसे जून, 2017 तक पूरा कर लिया जायेगा । स्पेशल प्लान बी0आर0जी0एफ0 के तहत सात ग्रीड उपकेन्द्र की स्थापना की जा चुकी है इसके अतिरिक्त सात नये ग्रीड उपकेन्द्र का निर्माण वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक किये जाने का लक्ष्य है । वितरण के प्रक्षेत्र में स्पेशल प्लान बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत दो योजनाएं फेज 1 फेज 2 स्वीकृत है । फेज –1 में 21 उपकेन्द्र का निर्माण हो चुका है ।

(इस अवसर पर सभापति, श्री नरेन्द्र नारायण यादव ने आसन ग्रहण किया)

और शेष चार का निर्माण जून, 2017 तक कर लिया जायेगा । साथ ही कुल 379 सब स्टेशनों के आधुनिकीकरण एवं नवीकरण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा एवं शेष का 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है । पीक लोड की मांग को पूरा करने हेतु 274 कि0मी0 नये 33 के0भी0ए0 लाईन 2315 मीटर नये 11 के0भी0ए0 लाईन का निर्माण एवं 5 हजार 479 नये ट्रांसफर्मर अधिष्ठापित किये गये हैं । हर घर बिजली निश्चय का शुभारम्भ 15 जून,2016 को किया गया है । इस निश्चय के अन्तर्गत आगामी 2 वर्षो में

मुख्यमंत्री विद्युत निश्चय योजना के तहत राज्य सरकार अपने संसाधनों से ग्रामीण क्षेत्रों में सही घरों तक विद्युत उपलब्ध करायेगी इसके साथ –साथ दिसम्बर 2017 तक सभी गांव का विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया जायेगा । अध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना आगामी फेज–2 अन्तर्गत मेरे विधान सभा जीरादेई और नौतन में शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण अंतिम चरण में है लेकिन दीन दयाल ग्रामीण ज्योति योजना के तहत जीरादेई तितरा मैरवां के बरकामांझा में शक्ति उपकेन्द्र के लिए जमीन चिन्हित की गयी है लेकिन अभी भी वह लंबित है एवं नौतन के अंगौता गांव में भी जमीन की व्यवस्था प्रक्रिया में है। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ ।

श्री अशोक कुमार सिंह(203): सभापति महोदय, मैं अपने पार्टी के नेता और पार्टी के मुख्य सचेतक को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया है । मैं ऊर्जा विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । ऊर्जा की आवश्यकता सब को है चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे उद्योगपति हो ऊर्जा की आवश्यकता सब को है । आज के जमाने में बगैर ऊर्जा का चला नहीं जा सकता है जैसे आदमी को आक्सीजन की आवश्यकता है विकास के लिए ठीक आज वैसे ही ऊर्जा की आवश्यकता है । ऊर्जा के संबंध में माना जाता है कि चार–पांच बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती है, जिसमें बिजली का उत्पादन, बिजली का संचरण, बिजली का वितरण और बिजली से लोगों का संबंध का कनेक्शन और राजस्व की उगाही । मैं कहना चाहता हूँ सभापति महोदय जी, 2005 में एन0डी0ए0 की सरकार आयी और एन0डी0ए0 की सरकार ने मजबूती से बिहार में बिजली की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया और बिजली का सुधार हो रहा है और लगातार बिजली में सुधार करना पड़ेगा सरकार चाहे किसी की भी हो । वर्ष 2005 में हमारे पास बिजली उत्पादन की जो क्षमता थी हमारे राज्य में आज भी हम वहीं खड़ा हैं महोदय, जो हमारी इकाईयां 12 साल में थी उन इकाईयों का हम नवीकरण करने में लगे हैं, कोई अलग से नई इकाई लगाकर बिजली उत्पादन नहीं कर सकें हैं। ट्रांसमिशन में भारी सुधार हुआ है बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी हाउस में एक दिन रहे थे कि प्रधानमंत्री जी ने सराहा है। सही बात है प्रधानमंत्री जी कहा करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी कि सरकार बनती है बहुमत से लेकिन सरकार चलती है सर्वमत से तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार में अच्छा काम हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि 2018 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचा देंगे और देश के कोने कोने में बिजली पहुंचा देंगे । साथियों तो उसमें बिहार भी है लेकिन मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, जब सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के उस उक्ति का चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री जी ने बिहार की प्रशंसा की है तो बिहार की सरकार को यह भी

कहना चाहिए कि अगर प्रधानमंत्री जी मदद नहीं करते, केन्द्र मदद नहीं करता तो बिहार में बिजली का एक प्रतिशत भी विकास नहीं हो सकता, जो विकास हो रहा है केन्द्र के बदौलत हो रहा है यह बात आनी चाहिए । महोदय,चूंकि हमें विकास चाहिए, हमको आगे बढ़ना है और यह संभव है दोनों के मदद से, दोनों के सहयोग से संभव है एक के सहयोग से काम होने वाला नहीं है चाहे वह कहीं की भी सरकार हो । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूॅ महोदय, मैं ग्रीड के संबंध में कहना चाहता हूॅ और सदन को जानकारी देना चाहता हूॅ, महोदय, बड़ी दुख होता है विकास के लिए हम भी आये हैं, आप भी आये जीत के, आप भी चाहते हैं बिहार का विकास और हम भी चाहते हैं बिहार का विकास। महोदय, हमलोगों के यहां रामगढ़ में एक वाक्या आपको बतलाना चाहता हूॅ, हमलोगों के यहां रामगढ़ में एक ग्रीड का शिलान्यास हुआ तब हमलोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ थे और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए हमलोग हस्ताक्षर अभियान चलाये थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले । उसके साथ-साथ हमलोगों ने यह भी अभियान चलाया था कि रामगढ़ में ग्रीड की स्थापना हो । माननीय मंत्री, ऊर्जा विभाग वहां गये हुए थे रामगढ़ में और हमने कहा स्वागत में कि माननीय मुख्यमंत्री जी का यह प्रयास है एन0डी0ए0 का प्रयास है कि आज रामगढ़ में ग्रीड की स्थापना हो रही है । महोदय, मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूॅ, आज सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहां कानून का राज है, यहां न्याय के साथ विकास होता है लेकिन बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री वरिष्ठतम मंत्री जी ने मंच से कहा कि रामगढ़ का ग्रीड जो आज बन रहा है वह किसी के प्रयास से नहीं बन रहा है वह एक व्यक्ति के डर से बन रहा है और उस व्यक्ति के घर से मैं पास किया हूॅ तो मैं कहना चाहता हूॅ महोदय कि सरकार अगर किसी व्यक्ति से डरती है, उस सरकार से विकास और न्याय का क्या उम्मीद किया जा सकता है । जब सरकार के मंत्री डरते हों किसी व्यक्ति से । साथ ही साथ माननीय मंत्री महोदय ने दो पावर सबस्टेशन का शिलान्यास किया कुसहरिया का दुर्गावती प्रखंड में और माननीय मंत्री ने शिलान्यास किया रामगढ़ में देवहलिया का, एक साल बीत गया लेकिन आज तक दोनों पावर सब स्टेशन में सभापति महोदय काम नहीं लगा, दोनों में किसी में काम नहीं लगा, न देवहलिया में काम लगा न कुसहरिया में काम लगा और जो एन0डी0ए0 का काम चल रहा था वहीं फिर शिलान्यास किया गया ।(क्रमशः)

टर्न–14/मधुप/21.03.2017

...क्रमशः ....

श्री अशोक कुमार सिंह (क्षेत्र सं0 203) : सभापति महोदय, हम सदन को बताना चाहेंगे कि रामगढ़ से लेकर कलानी तक 15 कि0मी0 पोल गाड़ा गया है 1984–85 का और फिर सरकार रामगढ़ से कलानी तक पोल गाड़ना चाहती है, यह पैसे की बर्बादी है, यह सीधे–सीधे पैसे की बर्बादी है । जो पोल रामगढ़ से कलानी तक गाड़ा गया है, आज फिर नया पोल गाड़ने की क्या आवश्यकता है ? सरकार का पैसा लगा, किसान का खेत फँसा हुआ है और फिर नया पोल गाड़ा जा रहा है ।

जहाँ तक वितरण का सवाल है, वितरण की आपकी जो व्यवस्था है, कोई ऐसा गाँव नहीं है, महोदय, हमारी चुनौती है सरकार को कि किसी भी गाँव में सरकार के प्रतिनिधि चलें, किस गाँव में बाँस का पोल नहीं है ? किस गाँव में बिजली लोगों के घर में निगसता में बाँधकर और कैसे–कैसे ले जाकर लोग अपना लाईट जला रहे हैं । प्रमाण है महोदय, इसी 9 तारीख को एम0एल0सी0 का मतदान हो रहा था, हमलोग मतदान में फँसे हुये थे और एक उपरी का लड़का अजय गुप्ता, पिता– शिव कुमार साहू, उपरी सुबह–सुबह 7 बजे 11 के0वी0ए0 की लाईन में फँसकर मर गया और 11के0वी0ए0 की लाईन की ऊँचाई जमीन से 4 फीट और एकाएक वह 4 फीट वह 11 के0वी0ए0 नहीं हो गया, वह दो साल से था । आवेदन दिया गया लेकिन विभाग ने उसका नहीं सुना, तो मैं सरकार से निवेदन करूँगा, सरकार को सलाह दूँगा कि अगर ऐसे अधिकारी हैं, आप जाँच कराइये हमारी बात को, अगर यह घटना सही है, फोटो है हमारे पास, एक नहीं अनेक फोटो हैं, गरीब नौजवान 25 साल का, जान चला गया । अगर यह घटना सही है तो संबंधित पदधिकारियों को सरकार दंडित करे, सरकार उन्हें बर्खास्त करे । यह है वितरण की आपकी व्यवस्था ।

(व्यवधान)

कनेक्शन की जहाँ तक बात है, सरकार कह रही है, हम आपकी बात बोल रहे हैं, हम पूरे सदन की बात बोल रहे हैं, हम बिहार की बात बोल रहे हैं, हम अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, हम बिहार के गाँव की जमीन की सच्चाई बता रहे हैं, अगर सुनना है तो इसको सुनिये और सही है तो इसका आप भी समर्थन करिये ।

(व्यवधान)

आप जरा शांत होकर धैर्य से सुनिये । सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूँगा, मैं नहीं चाहता, जो भी कह रहा हूँ, मैं सदन को गुमराह करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, गाँव से आया हूँ, संघर्ष करके आया हूँ । अगर आप जीतकर उधर बैठे हैं तो हम हारकर नहीं बैठे हैं, किसी की कृपा से नहीं बैठे हैं, हम जनता के आशीर्वाद से बैठे हैं, हमको भी अपनी बात रखने का अधिकार है, हम जनता की आवाज रखेंगे और आपका

भी यह अधिकार है, हम आपको सहयोग करेंगे, हम निवेदन करेंगे कि आप भी हमारा सहयोग करिये ।

उर्जा से हटकर, अगर हम एक बात सदन में रखते हैं तो हम गुनहगार हैं लेकिन आज उर्जा पर चर्चा है और उर्जा की जो जमीनी सच्चाई है, अगर उसको न रखा जाय, बड़ा दुख है, बड़ा दर्द है कि राज्य का उर्जा विभाग का अधिकारी पार्टी के प्रतिनिधि का पिटाई करता है कार्यालय में और सरकार अगर नहीं मानती है कि पिटाई किया है तो बक्सर से उठाकर उसका ट्रांसफर नहीं होता, ऐसे अधिकारी को बर्खास्त होना चाहिये, नहीं तो आज वहॉ मारा, कल इधर के साथी पर भी हाथ चलायेगा और कौन जायेगा ट्रांसफर्मर मॉगने के लिये ? ट्रांसफर्मर को मॉगने के लिये कोई नहीं जा पायेगा, जो आज स्थिति है । इसपर सरकार को विचार करना चाहिये ।

मैं कहना चाहता हूॅ तीसरी बात, वितरण के संबंध में कि नुआव प्रखंड में 10 पंचायत है और 10 पंचायत में 1 पावर सब-स्टेशन है नुआव में । महोदय, नुआव प्रखंड के 5 पंचायतों की दूरी प्रखंड मुख्यालय से करीब 16-17 कि0मी0 है । मैं चाहूॅगा, अनुरोध करूॅगा सरकार से आपके माध्यम से कि नुआव प्रखंड के डुमडुमा पंचायत में, चाहे नुआव प्रखंड के ओ0पी0 पंचायत में एक पावर सब-स्टेशन का निर्माण सरकार करायें ताकि सभी किसानों को बिजली मिल सके ।

जहॉ तक जो काम चल रहा है बिजली विभाग का, उसके संबंध में आपके माध्यम से मैं सरकार को जानकारी देना चाहता हूॅ कि जो पोल गाड़े जा रहे हैं, जो केबल लगाये जा रहे हैं और जिन कम्पनियों ने इस काम को लिया है, इसमें इतना बड़ा घोटाला है कि एक नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक पेटी-कंट्रैक्टर लगे हुये हैं। मैंने पहले कहा कि मैं सदन को गुमराह नहीं करना चाहता हूॅ, आप जॉच करा लीजिये कैमूर जिला का, वहॉ इ0सी0आई0 कम्पनी काम कर रही है । बेरोजगार नौजवान जब काम मॉगने के लिये जाता है.....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : तो उसको 600 रू0 प्रति पोल दिया जाता है और एक बड़े कद्दावर वहॉ नेता हैं, वह सारा काम 900 रू0 प्रति पोल ले लिये हैं । 900 रू0 प्रति पोल लेकर 600 रू0 बॉट रहे हैं । यह है सरकार का काम और यह है कम्पनी का काम । न कहीं पोल में टुकड़ा डाला जा रहा है, न कहीं पोल की हुराई हो रही है....

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें ।

श्री अशोक कुमार सिंह : पोल आज गाड़ा जा रहा है, कनेक्शन दिया जा रहा है और पोल घटिया किस्म का लगाया जा रहा है, इसकी जॉच होनी चाहिये और अच्छी क्वालिटी का पोल लगना चाहिये । इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूॅ ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री ललन पासवान जी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री आफाक आलम ।

श्री मो0 आफाक आलम : सभापति महोदय, उर्जा विभाग के अनुदान के पक्ष में और कटौती प्रस्ताव जो लाया गया है उसके विपक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ा हूँ ।

आज उर्जा विभाग ने जो काम किया है, वह सराहनीय है और सभी लोग जानते हैं, हमारे माननीय सदस्य जितने भी सदन में हैं, वे भी जानते हैं । उर्जा विभाग में मेरे जैसा सदस्य काफी डिमांड करता था और हम माँग करते थे, हमेशा सवाल लाते थे लेकिन अब एक भी सवाल हमको उर्जा विभाग का नहीं मिलता है कि एक भी हम माननीय मंत्री जी से सवाल करें या माँगें । यह सच्चाई है कि आज 99 प्रतिशत उर्जा विभाग में काम हुआ है और खास तौर पर देहाती क्षेत्र में जो लोग बसते हैं, किसान बसता है, उनलोगों के बीच जो लाईन बिछाया गया है, लाईन का जाल बिछा दिया गया है । अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि घटिया पोल लगाया जा रहा है, हम तो कहेंगे कि जो सदस्य लाईन के मामले में ऐक्टिव रहे हैं, वह अपने विधान सभा क्षेत्र में काफी लाईन को जाल की तरह बिछवाये हैं । हम काफी ऐक्टिव रहे, मेरे विधान सभा से एक भी शिकायत हमको नहीं मिलती है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को शिकायत करें ।

हमारे लोकप्रिय नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, जो महागठबंधन के नेता हैं, उन्होंने यह घोषणा किया था कि 2016-17 तक हम सभी गाँव का विद्युतीकरण कर देंगे और यह सच निकला और सच्चाई के साथ सभी गाँवों में विद्युतीकरण हो गया है, पूरा कर दिया गया है । हमारे मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं, वह करते हैं । माननीय उर्जा मंत्री जी से भी कहना चाहेंगे कि इन्होंने भी जो काम किया है, उसके लिये आप धन्यवाद के पात्र हैं । इस तरह से काम करके आपने दिखाया है और ईमानदारी की बात है, उर्जा विभाग में आज आप देख रहे हैं कि किसी तरह का कोई ऐसा सवाल ही नहीं है, विपक्ष को बोलने का कहीं पर मुँह नहीं है कि इसमें बोल सकेंगे, बोल भी नहीं पायेंगे और आज उसके लोग भी भाग गये हैं । सब कुछ पूरा हो गया है तो अब वे उसपर क्या सवाल उठायेंगे ? बचा ही नहीं है कुछ बोलने के लिये, यह सच्चाई है । आज हम यही कहना चाहेंगे कि हर गाँव में बिजलीकरण हुआ है और सही ढंग से बिजली भी मिल रही है । हमारे यहाँ 24 घंटा बिजली शहर को मिल रहा है और 18-19 घंटा हमारे यहाँ बिजली गाँवों को मिल रही है । यह प्रमाण है कि हम इसको बराबर देखते रहते हैं और बिजली पर हम पदाधिकारीगण से बात करते रहते हैं । जहाँ तक जो सवाल आया है राजीव गाँधी विद्युतीकरण का, वह यू0पी0ए0 सरकार की देन है, हर गाँव में

बिजली पहुँचाने का काम यू0पी0ए0 सरकार ने किया है । कांग्रेस की सरकार ने किया है । ...क्रमशः....

टर्न–15/आजाद/21.03.2017

.... क्रमशः .....

श्री मो0 आफाक आलम : यह गलत बात नहीं है कि राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना कांग्रेस के जमाने में लाया गया था और हर गांवों को बिजली देने की बात कहीं गई थी । हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वे लोकप्रिय हैं, वे जो बोलते हैं, वे करते हैं और करके भी वे दिखाये हैं । सभापति महोदय, आज कोई भी विभाग ऐसा नहीं है कि जिस विभाग में काम नहीं हो रहा है । हर विभाग में काम हो रहा है, अंधाधुंध काम हो रहा है और उसको विपक्ष के लोग गलत–ब्यानी करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। उनको तो विकास से मतलब नहीं है, उनको प्रोपगंडा करना है, शिकवा–शिकायत करना है, उनको अफवाह फैलाना है और कोई विकास का बात करना नहीं है । राजीव गॉधी विद्युतीकरण योजना में क्या कारण हो गया कि उसका नाम हटाकर के दीनदयाल लाया गया । इसमें बिजली लगना है, बिजली लगेगा ही, जिस कम्पनी का है, वहां लगेगा ही, जिससे भी लगना हो, ये नाम बदलकर के कि उनका नाम नहीं हो, मेरा नाम आगे बढ़े। अगर आप काम कीजियेगा तो आपका नाम आगे बढ़ेगा ही और नाम लोग लेंगे ही ।

सभापति महादेय, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी से कि हमारे यहां कुछ समस्या है । छोटा–मोटा समस्या है, कोई बड़ी समस्या नहीं है । आज जो काम हो रहा है, वह 11हजार के लाईन में केबुल का तार लग रहा है, यह बहुत ही अच्छा काम हो रहा है । पहले जो खुल हुआ ऑपेन तार था, उसमें केबुल वाला तार लग रहा है । गांव में भी हम देखें कि हर जगह केबुल वाला तार लग रहा है। कुछ ऐसा गांव है, जहां केबुल तार नहीं लगा है । हम आग्रह करेंगे कि वहां भी केबुल तार लगा करके उसको सुरक्षित कर दिया जाय ताकि किसी तरह की घटना नहीं हो । हमारे क्षेत्र में बिजली मिस्त्री की कमी है, बिजली मिस्त्री की बहाली की जाय। अगर बिजली मिस्त्री बहाल हो जायेगा तो कंज्यूमर को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी । आज जो ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 की बात आती है, हर घर में ए0पी0एल0 और बी0पी0एल0 वाले को विद्युत कनेक्शन मिला है और उन सबके घर में मीटर भी लग गया है । महादलित घर के लोग भी पैसा देने के लिए हमलोगों के पास आते हैं कि हमारे यहां बिजली बिल आ गया है, हम पैसा कहां जमा करेंगे । अब यह सोचने की बात है कि जिस महादलित के बारे में सोचते हैं कि उसके घर में बिजली नहीं पहुँची तो वह कैसे बिजली का बिल लेकर हमलोगों के पास आता है । जब बिजली लगा है तभी न वह बिजली बिल लेकर आता है । इसलिए हम यह कहना

चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि कुछ जगह ट्रांसफर्मर लगना है, जो हमारे क्षेत्र में है, वहां पर ट्रांसफर्मर लगना बहुत जरूरी है । हम माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहते हैं कि कुछ जला हुआ ट्रांसफर्मर हैं, वह 16 के0वी0ए0 का है । बहुत जगह बदला गया है, मात्र दो-तीन जगह नहीं बदला गया है, उसको बलदने की बहुत आवश्यकता है, इसको बदलवा दिया जाय । हमारे यहां बिजली रोटेशन में मिलती है । हम पिछले बार भी माननीय मंत्री जी से कहे थे कि पूर्णिया में जब माननीय मंत्री जी थे, उसमें हम बोले थे कि हमारे यहां रोटेशन में बिजली मिलती है, रोटेशन को खतम कर दिया जाय और वहां पर परमानेंट इस तरह से लाईन मिले ताकि लोगों को लगे कि जिस तरह से शहर में मिलता है, उसी तरह से वहां के लोगों को बिजली मिलनी चाहिए । यही आग्रह करते हुये हम अपनी बात को समाप्त करते हैं । जयहिन्द, जयभारत ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, आज तीन विषय पर बजट है विद्युत,पर्यटन और कल्याण पर है । तीनों महत्वपूर्ण है और समय बहुत कम है, अगर कृपा करते तो दो-चार मिनट बोल देते ।

सभापति महोदय, स्वाभाविक है कि बिहार में बिजली का विकास हुआ है, बल्कि मैं जहां से आता हूँ, माननीय मंत्री जी को पिछले बार भी मैंने कहा था नोहट्टा, रोहतास, चेनारी, शिवसागर, अधौरा का 213 गांव बिजली का बल्ब नहीं देखा है, आजादी के 70 साल गुजर गया, अभी तक वे लोग बिजली के बल्ब नहीं देखे हैं तो पोल की बात तो छोड़ दीजिये । अभी सब लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं चर्चा करना चाहता हूँ , मैंने बहुत प्रयास किया, इसके लिए मैं विभाग को बधाई देना चाहता हूँ प्रत्यय साहेब को, इन्होंने कोशिश की, एन0ओ0सी0, अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के बावजूद सोलर लाईट का 130 करोड़ रू0 का शायद टेंडर हो चुका है, सोलर भी पहुँच जाय लेकिन वहां पर स्थायी बिजली मिले । हम कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, आपको बधाई भी देते हैं लेकिन वहां पर परमानेंट व्यवस्था नहीं हुआ । वहां पर आप देखियेगा तो पाईयेगा कि वहां पर इन्सान जानवर की तरह रहते हैं और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि सरकार इसपर पहल करे । वन विभाग को सब कुछ दिया गया, प्रत्यय साहेब ने मिलकर दिया लेकिन वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं मिलने के चलते वहां लाईन नहीं जा रहा है । रेवेन्यू गांव है, वहां पर सारी सुविधायें मिलनी चाहिए लेकिन अभी तक आजादी के 70 वर्षों के बाद भी कैमूर और रोहतास के 213 गांव, जहां समाज के हर तबके के लोग रहते हैं, लेकिन वहां पर बिजली नहीं मिली है ।

सुन लीजिये क्यों दलित के बात पर छेड़-छाड़ कर रहे हैं, मेरा समय भी कम है । आग्रह करेंगे, बधाई दे रहे हैं कि वहां पर लाईन लगवाईए और थोड़ा आप सक्रिय हो जाईए । सक्रिय होईयेगा तो अगर भारत सरकार से भी कोई बात होगा तो मिलकर के काम होगा । एन0ओ0सी0 तो मिलता है, पूरे देश में सब जगह सड़क है, बिजली जाती

है, हमारे यहां क्यों नहीं जा सकती है, इसलिए लगता है कि सरकार इस सवाल पर संवेदनशील नहीं है, सरकार संवेदनहीन है । नहीं तो आजादी के 70 साल में कितनी सरकारें आयी और गई । वहां पर गाय चराने वाले, भैंस चराने वाले, सूअर चराने वाले, बकरी चराने वाले, आदिवासी-वनवासी रहते हैं, चुआरी का पानी पीते हैं, पीने का पानी नहीं, बिजली नहीं, चापाकल नहीं । इसलिए आग्रह करते हुये कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि वहां पर चली जाय बिजली ।

नोहट्टा,रोहतास में कोई नहर नहीं है । प्रत्यय साहेब बैठे हुये हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हुये हैं । हमने पिछले बार भी कहा कि वहां बिजली थोड़ा बढ़ा दीजिये, कह रहे हैं कि 18 घंटा । हमारे यहां 12 घंटा-13 घंटा मिल रहा है । हमने कहा कि 8-8 मेगावाट बढ़ा दीजिये, मेरे यहां नहर नहीं लगता है, पूरा लगता है कि आदिवासी, गरीबों का इलाका है, सब मजदूरी करके जीता खाता है, सारे लोग गृहस्थी पर डिपेंड कर रहा है । इसलिए हमने कहा है कि वहां बिजली बढ़ा दीजिये, नहीं तो सब लोग मर जायेगा। 8-8 मेगावाट करा दीजिये, चारों ब्लौक को दे दीजिये चेनारी,शिवसागर .....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आपका समय हो गया ।

श्री ललन पासवान : सभापति महादेय, मुझे दो बात कहना है कल्याण पर और पर्यटन पर । गुप्ता धाम महोत्सव मना रही है सरकार, आपने दिया, इसके लिए आपको बधाई और इसको दो दिवसीय के रूप में मना दीजिये और रोहतासगढ़ किला, जो दुनिया में चर्चित किला है, वहां पूरे देश के सम्पूर्ण आदिवासी पूजा करने के लिए जाते हैं । उसको भी अगले साल में राजकीय महोत्सव में शामिल करिए और रोपवे का आपका टेंडर हो गया, इसको आप करा दीजिये । मेरे यहां चार सड़क है, माननीय श्रवण कुमार मंत्री जी गये हैं .....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आपका समय हो गया ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूँ । मैं आग्रह करूँगा कि चेनारी से जो बादलगढ़ होते हुये दुर्गावति नदी से जो गुप्ता धाम सड़क जाती है, एक चौड़ा से गुप्ता धाम जाता है और एक पनारी से । आप ताराचंडी धाम से गुप्ता धाम जो सड़क जाती है, उसमें आपने पैसा दिया है, हमने देखा है इस बजट में लेकिन इन तीनों सड़कों को बना दिया जाय तो वहां देवघर के बाद ज्यादा पर्यटक जायेंगे । आज वहां नदियों में पैदल पर्यटक जाते हैं, जो बह जाते हैं, इसको करा दिया जाय और रोहतासगढ़ किला को भी राजकीय महोत्सव में शामिल कर लीजिए ।

तीसरा एक आग्रह है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का आवासीय विद्यालय पहाड़ पर ही नहीं पूरे राज्य के बारे में, इसके संबंध में माननीय कल्याण मंत्री जी से आग्रह है कि आजादी के बाद भी हमलोगों के लोग महोदय, लगता है कि इन्सान नहीं है, जानवर के भाँति भोजन उनको मिलती है, खानबदोश की जिन्दगी जीते हैं छात्र-छात्रायें, वहां पर रहने वाले टोटली इन्तजाम एन0जी0ओ0 को दे दिया जाता

है । दलपनिया दाल, मोटका सड़ा हुआ चावल और जो मिलता है आलू, धनिया,तोड़ी का सब्जी मिलता है, इसको खाने वाले लोग खाकर के दिन भर भी जिन्दा नहीं रहेंगे, उनको होस्पीटल जाना पड़ेगा । सरकार इसके नियम को सुधारे । कहीं पैखाना नहीं, कहीं बिजली नहीं, कहीं उनकी चौकी नहीं, पूरे राज्य के आवासीय विद्यालय की हालत खराब है । राज्य में छात्रवृत्ति बन्द हो गई । सभापति महोदय, पहला क्लास से 10वां क्लास तक छात्र-छात्राओं की.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप भाषण समाप्त करें । आपका समय हो गया है ।

श्री ललन पासवान : सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूँ । बस, कनक्लूड कर रहा हूँ । सरकार पहला क्लास से दशम् क्लास तक धोबी, पासवान, मेश्तर, मुशहर, डोम के जो बाल-बच्चे हैं, आदिवासियों के जो बाल-बच्चे हैं, कैसे वे पढ़ेंगे, कपड़े उनको कहां से मिलेंगे, किताब कौन खरीदेगा । सरकार क्रेडिट कार्ड चालू कर दी, यह ठीक बात है लेकिन जो पहले क्लास से ऊपर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, सरकार उसपर संज्ञान लें ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : इसकी सी0बी0आई0 जॉच हो, बिहार में आवासीय विद्यालय का निर्माण इन्सान की भाँति रहने लायक हो .....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री ललन पासवान : महोदय, कर रहे हैं । सरकार ईमानदारी से काम करें, दलित विरोधी काम नहीं करें । बहुत,बहुत धन्यवाद ।

टर्न-16/अंजनी/दि0 21.03.2017

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्या श्रीमती भागीरथी देवी, आपके पास सात मिनट का समय है ।

श्रीमती भागीरथी देवी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री अरूण कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव लाया गया है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ । सदन में सभी माननीय सदस्य बिजली के संबंध में चर्चा कर रहे हैं और सुन रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय सदस्यों से कि सदन के पटल पर जो भी बात बोला जाय, वह सही-सही बोला जाय । आज हमारे महादलित क्षेत्र में, आज सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आज सब काम पूरा हो गया है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि महादलित गांव में पोल लगा दिया गया है लेकिन तार और ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लगाया गया है । करीब एक साल हो गया, न तो तार गया, न ट्रांसफार्मर गया और न बिजली ही गयी ।

सभापति महोदय, जब हम विधायक लोगों के फंड से, हमलोगों को लिखकर आया कि माननीय विधायक आप अपनी अनुशंसा पर ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं । हमने डेढ़-डेढ़ करोड़, दो-दो करोड़ का ट्रांसफार्मर लिखकर दिया, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ी हुई हूँ लेकिन मैं गलत नहीं बोलूँगी, विद्युत कार्यालय में चार-चार दलाल लोग वहां बैठाकर रखे हुए हैं, एस0डी0ओ0 के यहां चार-चार दलाल लोग बैठे हुए हैं और दलाल लोग गांवों-गांव घूमकर लोगों से पैसा वसूली कर रहे हैं । जब एस0डी0ओ0 से इस संबंध में पूछ जाता है तो उनलोगों को चुपचाप बुलाया जाता है कि तुमलोग आओ, हम यहीं पर खत्म कर देते हैं । बताया जाय महोदय, जब वे खत्म कर देते हैं तो कौन एस0डी0ओ0 के पास जायेगा । फिर वही गरीब आदमी घूमकर हमारे पास आता है और वह हमलोगों से कहता है कि इस तरह की बात है । जब हम एस0डी0ओ0 से बात करते हैं तो कहते हैं कि सुधार देते हैं । एस0डी0ओ0 कहता है कि आप गुस्साइए नहीं, हम ठीक कर देते हैं । मैं इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि सुधार लाया जाय, एस0डी0ओ0 के यहां जो दलाल लोग हैं, उनको वहां से हटाया जाय । अगर एस0डी0ओ0 साहेब के यहाँ से नहीं होता है तो कहते हैं कि जाइए फलां जगह, जाइए फलनां जगह । जो महिलायें हैं, गरीब हैं, जिनके शरीर में ठीक से वस्त्र भी नहीं है, वे कहते हैं कि हमलोगों को बी0पी0एल0 से मिला है । बी0पी0एल0 वाले से भी दलाल लोग जबर्दस्ती लिखाकर कार्यालय में रख देते हैं और ऑफिस में बैठकर एस0डी0ओ0 और दलाल लोग आपस में पैसा बांटते हैं । ये लोग गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं । महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि इसपर ध्यान दिया जाय ।

महोदय, एक बात कहना चाहती हूँ कि जब वहां बिजली ऑफिस है लेकिन कर्मचारी की कमी हैं । अगर कहीं कोई बिजली खराब होती है तो कहते हैं कि इनको बुला लीजिये, उनको बुला लीजिये, फोन करके बुलाया जाता है और अपना पैसा देकर लाईन को ठीक कराया जाता है । यहां माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कुछ का भी कमी नहीं है लेकिन कर्मचारी की कमी है, मिस्त्री की बहुत कमी है । आदमी बिजली से जलकर मर जाता है, उसको मिलता है पैसा एक लाख, दो लाख और गाय-भैंस भी बिजली से मर जाते हैं, लोग दस लाख, पन्द्रह लाख, बीस लाख का गाय, भैंस लेते हैं । क्या उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है ? क्या उनलोगों को गाय-भैंस के लिये पैसा नहीं मिलेगा ? कम-से-कम गाय, भैंस रखने वाले को पैसा मिलना चाहिए ।

(व्यवधान)

आप लोग अपने क्षेत्र में जाकर घुमकर देखिए कि क्या स्थिति है । गरीब का काम कीजिए, जनता का काम कीजिए तब जाकर जनता खुश रहेगी । हम झूठमूठ सदन में चिल्लायें तो सिर्फ बोलने से नहीं । एकदम टाईट रहिए, आप शपथ लें कि हम जनता

के लिए हैं, जनता के लिए जान देंगे, जनता के हक के लिए लड़ाई करेंगे, सदन में सही रूप में जनता की समस्या के बारे में रखा जाय । हुजूर, जनता की मॉंग पूरी की जाय, विधायक का बात पूरा नहीं किया जाय ।

महोदय, मैं एक और समस्या के बारे में बोलना चाहती हूँ । महोदय, कल और परसों हमारे क्षेत्र में इतना ओलावृष्टि हुई, बहुत पत्थर गिरा है हमारे गौनाहा क्षेत्र में, रामनगर क्षेत्र में । वहां थारू लोगों का दो औरत मर गया । यह कल का रिपोर्ट है । दो औरत पत्थर से मर गयी है और ओलावृष्टि से उनका घर गिर गया है और रब्बी की फसल बर्बाद हो गयी है और बिजली का तार टूट-टूटकर जहां-तहां बिखर गया है, गांव में बिजली की स्थिति खराब हो गयी है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि इसको देखवा लिया जाय कि क्या सही है, क्या गलत है और जरूरी कार्रवाई कराया जाय । महोदय, मैं सदन में गलत बात नहीं रखती हूँ, सही बात रखती हूँ । वहां के थारू लोग चिल्ला रहे हैं, थारू लोग के औरत दिन-रात फोन कर रही है और हम वहां अभी तुरंत जा रही हूँ । महोदय, ओलावृष्टि से बहुत बुरी दशा है । दो औरत मर गयी, उनको सरकार की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए । जब आदमी का मुआवजा मिल रहा है तो कम-से-कम गाय, बैल, भैंस, घोड़ा के लिए भी मुआवजा तय कर देना चाहिए । इस कार्य के लिए माननीय मंत्री जी को बहुत पुण्य होगा । आदमी के लिए मिल रहा है तो वह किसान भी जानवर 20 हजार, 25 हजार में खरीद रहा है, एक-एक लाख का जानवर खरीद रहा है तो इसके लिए माननीय मंत्री जी ध्यान दें । उधर के माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इन लोगों का बिजली का काम पूरा हो गया, हमारे क्षेत्र में बिजली पूरा हो गया, लेकिन हमारे यहां जो लाईन की स्थिति है, उसके बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपके पास मात्र एक मिनट है ।

श्रीमती भागीरथी देवी : सभापति महोदय, एक मिनट समय और बढ़ा दिया जाय । जब बिजली के विषय में मुझे बोलना था तो हमने जरूर सोचा था कि माननीय मंत्री जी से मवेशी के बारे में जरूर कहूंगी और मैं आशा रखती हूँ कि माननीय मंत्री जी इसपर ध्यान देंगे । अगर माल-मवेशी मर जाता है तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए । वहां जो दलाल लोग हैं, उनको वहां से हटाया जाय एस0डी0ओ0 को कहकर । महोदय, हमारे क्षेत्र में 10 ट्रैक्टर, 16 ट्रैक्टर निकल रहा है चोरी का पत्थर, बालू । ये सब चोरी से खनन करके ले जाते हैं । बालू वाले ट्रैक्टर को रास्ते में पकड़ा तो कहा कि 1200 रूपया बालू का लेता है और 400 रूपया उपर का लेता है । अब बताइए कि कहां तक लोग घूस खायेगा ? कहां तक ठीकेदारी दिया गया था ? इस संबंध में माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि चोरी के पत्थर पर ध्यान दिया जाय, माननीय पत्थर मंत्री तो हैं नहीं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय समाप्त हो गया ।

श्रीमती भागीरथी देवी : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन चोरी के पत्थर एवं बालू पर ध्यान दिया जाय, यह मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ । जय भारत, जय हिन्द ।

टर्न-17/शंभु/21.03.17

श्री लाल बाबू राम : महोदय, ऊर्जा के अनुदान मांग के समर्थन में एवं विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, आपने सदन में बोलने का मौका दिया इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। हम सदन में अपने महागठबंधन के नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी, आदरणीय ऊर्जा मंत्री विजेन्द्र बाबू, आदरणीय हमारे दल के सचेतक ललित कुमार यादव जी को आभार प्रकट करते हैं कि सदन में मुझे बोलने का मौका दिया। महोदय, ऊर्जा विभाग पर बोलने के लिए मुझे मौका मिला है। ऊर्जा विभाग, बिजली विभाग आज हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में बिजली की जरूरत है। आज बिजली बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। जिस तरह से भोजन, वस्त्र और आवास जीवन में जरूरत है आज के आधुनिक युग में बिजली का भी उतना ही महत्व है। महोदय, एक जमाना था कि बिजली शहर में ही मिलती थी और देहात के लोग उपेक्षित रहते थे। ये बिजली कुछ गांवों और कुछ परिवार तक सीमित था- गांव के गरीब लोग दलित लोग, उपेक्षित थे उन्हें बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन जब 1990 में दलितों शोषितों के मसीहा माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने देहाती क्षेत्र में गांव में जाने का काम किया और उनकी समस्या, गांव के लोगों की समस्या सुनने का काम किया, उनका निदान करने का काम किया और गरीबों को उन्होंने हिम्मत दिया, आवाज दिया और समस्या का निदान किया और बोलने का अधिकार दिया, बराबरी का हिस्सेदारी दिया और आज दलित समाज और गरीब समाज के लोगों को उन्होंने आह्वान किया कि ए गरीबों पढ़ो लिखो आगे बढ़ो। आज दलित समाज के लोग, गरीब लोग जो आज इन्हीं की देन है कि ऊंचाइयों को छू रहा है। हम विशेष तौर पर देहात के बारे में बोलना चाहते हैं, गांव के बारे में बोलना चाहते हैं कि शहर और गांव में बहुत अंतर था, असमानता थी। बिजली शहर में मिलती थी, देहात में मिलती भी थी तो कुछ परिवार तक, कुछ गांव तक मिलता था जो उस जमाने में जिसको बिजली था उसको शान समझा जाता था। जब हमारे बिहार का बंटवारा हुआ तो बिहार के बंटवारे में उस समय बिहार में बिजली जो मिलती थी वह अधिकतर उत्पादन झारखण्ड में हुआ करता था जो विभाजन के बाद तेनुघाट, पतरातू घाट सब झारझण्ड में चला गया बिहार में सिर्फ बरौनी थर्मल पावर और

मुजप्फरपुर में कांटी थर्मल पावर बचा गया था, जो जीर्णशीर्ण अवस्था में था। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को, ऊर्जा मंत्री जी को हम बधाई देते हैं कि कम संसाधन के बावजूद कुशल नेतृत्व देकर के सही दिशा देकर के इस विभाग को ऊंचाइयों पर लाने का काम किये हैं और इन्होंने उस समय जो बिजली की जो व्यवस्था थी, एक चुनौती थी उस चुनौती को स्वीकार किया और वादा किया जनता से कि अगर हम बिजली में सुधार नहीं करेंगे तो हम वोट मांगने नहीं जायेंगे और इन्होंने दिनरात मेहनत करके, कुशल नेतृत्व देकर के वादा के अनुरूप गांव और शहर में बिजली देने का काम किया है। बिजली इस कदर आज मिल रहा है कि गांव और शहर का जो अंतर था मिट गया है। पहले बिजली आती नहीं थी, आज बिजली आती है तो जाती नहीं है। आज लगातार बिजली मिल रही है यह सारा देन हमारे मुख्यमंत्री जी को और माननीय ऊर्जा मंत्री जी को है। हम कहना चाहते हैं कि आज ऊर्जा विभाग में पहले होता था कि आंधी तूफान में पोल गिर जाते थे, तार टूट जाते थे कोई पूछने वाला नहीं होता था, औफिस का चक्कर लगाने के बाद भी ठीक नहीं होता था, लेकिन आज कुशल प्रबंधन की देन है कि कहीं भी कोई पोल गिर जाय, तार गिर जाय तो 24 घंटा के अंदर में तार को बदला जाता है। कहीं भी पहले ट्रांसफार्मर जल जाता था तो ट्रांसफार्मर बदलने के लिए भी दर-दर की ठोकर खानी पड़ती थी, लेकिन आज स्थिति है कि विभाग द्वारा सेम डे मैक्सिमम 72 घंटा के अंदर में हर जगह ट्रांसफार्मर बदलने का काम हो रहा है। यह सारा देन हमारे मुख्यमंत्री जी की है और माननीय ऊर्जा मंत्री जी की है। हम कहना चाहते हैं ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन, संचरण और वितरण के क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। क्रमशः

टर्न-18/अशोक/21.03.2017

श्री लाल बाबू राम : क्रमशः .. आज जो बिजली मिल रही है, पहले बिजली जिनको मिलती थी वह बड़ों की पहचान थी आज गरीबों का पहचान बन गया, हर व्यक्ति का पहचान बन गया हैं । आज हर घर में, आज हर क्षेत्र में न कोई क्षेत्र उपेक्षित हैं, हर क्षेत्र में बिना रूकावट के बिजली मिल रहीं हैं, हर व्यक्ति को हर वर्ग के लोगों को बिजली मिल रहीं हैं, चाहे ए.पी.एल. धारी हो, बी.पी.एल. धारी हो, सभी को बिजली मिल रहीं हैं हम नहीं कह रहे हैं, जब इस राज्य से गुजरते हैं हमारे देश के लोग, कोई दूसरे राज्य के लोग, वे भी कहते हैं बिहार में सबसे ज्यादा अगर सुधार हुआ है तो बिहार में सुधार हुआ हैं और यहां पर निर्बाध बिजली बिना रूकावट के लगातार बिजली मिल रही है । हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी वह भी यहां आये, उनको भी कहना पड़ा कि बिहार में बिजली की व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुआ है और बहुत आगे बढ़ करके काम हो रहा हैं । हम बतलाना चाहते हैं कि उत्पादन के

परिक्षेत्र में सार्थक परिणाम आना शुरू हो गया हैं । मुजफ्फरपुर का विद्युत प्रतिष्ठान क्षमता विस्तार योजना के तहत 195 मेगावाट की दो इकाई जो पूर्ण है, 390 मेगावाट का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं तथा बरौनी ताप विद्युत परियोजना का विस्तार किया गया हैं, पहले 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था आज 500 मेगावाट उत्पादन करने का काम हो रहा हैं । ईकाई संख्या- सात को 2016 में चालू कर लिया गया है तथा ईकाई संख्या- छः को 2017 तक चालू करा लिया जायेगा । महोदय, हम कहना चाहते है कि संरचना के क्षेत्र में उत्साहबर्द्धक उपलब्धि हासिल हुई है, वर्त्तमान में 3769 मेगावाट का पावर आपूर्त्ति की जा रही है तथा वित्तीय वर्ष के अंत तक चार हजार मेगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है । महोदय, सभी राजस्व अनुमण्डलों में 31 ग्रीड उप केन्द्रों का काम प्रगति पर है, बी.आर.जी.एफ. योजना के तहत स्वीकृत योजना का कार्य 2017 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है, वितरण के प्रक्षेत्र में तीव्र गति से कार्य हो रहा है, बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत दो योजानायें फेज-1 एवं फेज-2 की स्वीकृति हुई है, ग्रामीण विद्युतीकरण महोदय, ग्रमीण विद्युतीकरण पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत 1141 गांव में विद्युतीकरण किया गया तथा 12943 अदद आंशिक विद्युतकृत गांव में 894 गांवों को विद्युतीकरण किया जा चुका है, शेष चार हजार 49 गांवों को 2017 तक पूरा कर लिया जायेगा । महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 12 वां प्लान के तहत 2032 गांव में से 1255 गांवों का कार्य पूरा कर लिया गया हैं।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री लाल बाबू राम : मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे विपक्षी के लोग कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, लेकिन उनको भी मौका मिला, मैन्डेट मिला, वायदा किये जनता से कि हम अच्छे दिन लायेंगे, वे कहां गये ? वो कहते थे कि बेरोजगारी दूर कर देंगे, वे कहते थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री लाल बाबू राम : वो कहते थे कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे और जहां कहीं भी जाते थे तो कहते थे कि बिजली नहीं आई, लेकिन बिजली आई और आपने जो भी वायदा किया था एक भी वायदा पूरा करने का काम नहीं कर रहें हैं । आप दलितों का शोषण करने का काम करते हैं, दलितों को अपमान करने का काम करते हैं, दलित के बेटा जो रोहित बेमुला हैं उसे मारा जाता हैं और आप कभी कभी बात करते हैं कि हम आरक्षण समाप्त कर देंगे । ये तो काम करते हैं । हमारे महागठबन्धन के लोग जो

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री लाल बाबू राम : महागठबन्धन के लोग जो वायदा किये थे, उन वायदों को पूरा करने काम काम किये थे उन्होंने हमारे माननीय नेता महागठबन्धन के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी तेजस्वी बाबू ने वायदा किये थे चुनाव से पहले कि गठबन्धन की सरकार बनेगी तो हम शराबबन्दी लागू करेंगे और शराबबन्दी लागू किया गया । वायदा किया था कि घर-घर को बिजली देने का काम करेंगे, आज घर-घर में बिजली देने का काम किया जा रहा है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य अब आप आसन ग्रहण करें ।

श्री लाल बाबू राम : आप अपने वायदा को निभायें, आप जो वायदा करके गये हैं उसको निभाने का काम करिये, महागठबन्धन के लोग सभी स्तरों पर एक जुट होकर के अपने वायदा को पूरा करने का काम कर रहें हैं, इतना कह कर बात समाप्त करते हैं ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्या श्रीमती कविता सिंह जी ।

श्रीमती कविता सिंह : माननीय सभापति महोदय, आज मैं उर्जा विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 में 10905.03 (एक सौ नौ अरब पांच करोड़ तीन लाख रू0) की जो मांग की गई है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ ।

महोदय, मैं आभार प्रकट करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उर्जा मंत्री जी का, हमारे दल के सचेतक श्री राम सेवक सिंह जी का जिन्होनें मुझे बोलने का मौका दिया ।

महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य किये जा रहे हैं वह बिहार के विकास को आसमां तक लेने जोने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, चाहे बिजली का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र में, चाहे वह सड़क के बारे में हो या कृषि के बारे में या पर्यटन हो या परिवहन हो या कला एवं संस्कृति हो या स्वास्थ्य हो, स्वच्छ जल हो या ग्रामीण कार्य हो या पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग हो या ग्रामीण विकास विभाग हो । सभी विभागों में, सभी कार्य जमीनी स्तर पर किये जा रहे हैं । महोदय, राज्य की बिजली की स्थिति में दिन दुना और रात चौगुना सुधार हुआ है । महोदय, स्पेशल प्लान बी.आर.जी.एफ. के तहत 7 ग्रिड उप-केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त 7 नये ग्रिड उप-केन्द्रों का निर्माण वर्त्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक किये जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए हमारी सरकार दृढ़संकल्प है ।

महोदय, हर घर बिजली, सात निश्चय का शुभारंभ 15 नवम्बर, 2016 को किया गया है । महोदय, हमारी सरकार बिजली के क्षेत्र में जो उन्नति के नये आयाम पेश कर रही है उसके लिए मैं एक कविता के माध्यम से बतलाना चाहती हूँ :

" उगे हम धरा पर नयी रोश्नी लें ,
उगे हम धरा पर नयी रोश्नी लें
अंधेरी निशा को मिटाने चले हम ,
जगे हम जगत में हुआ फिर सबेरा ,
मिटा भू-गगन से तीमीर का बसेरा ,
नयी भावना का नया राग लेकर,
मधुर गीत जग को सुनाने चले हम
उगे हम धरा पर नयी रोश्नी लें ।
अंधेरी निशा को मिटाने चले हम "

महोदय, इस निश्चय के तहत राज्य के सभी घरों को विद्युत संबंधन देने के उद्येश्य से ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत सभी बी.पी.एल. परिवार एवं मुख्यमंत्री विद्युत संबंधन निश्चय योजना के तहत अगल दो वर्ष में सभी ग्रामीण के ए.पी.एल. परिवार को विद्युत संबंधन देना ही हमारी सरकार का लक्ष्य हैं महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत पिछले एक वर्ष में 392 अदद अविद्युतकृत गांवों को बिजली देकर प्रकाशित किया गया हैं । आठ लाख सतहतर हजार पांच सौ सनतावन बी.पी.एल. परिवारों को नया विद्युत कनेक्शन दिया गया है ।

महोदय, राज्य के सभी राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड उप केन्द्र की स्थापना करना हमारी सराकार की योजना में शामिल है। महोदय, संरचन के क्षेत्र में उत्साहवर्द्धक उपलब्धियां हमारी महागठबन्धन सरकार को हासिल हुई है । वर्त्तमान में 3769 मेगावाट पीक आवर में आपूर्त्ति की जा चुकी हैं और इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक इसे 4000 मेगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य है । महोदय, राज्य से जल विद्युत उत्पादन करने का भी प्रयास हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है जो बड़ा ही सराहनीय हैं इसके तहत अभी तक लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापित क्षमता 53 मेगावाट पहुंच गई है तथा इस वित्तीय वर्ष में यह क्षमता 60 मेगावाट तक पहुंच जायेगी, इसके अतिरिक्त लघु जल विद्युत परियोजनाओं के अन्तर्गत कोशी क्षेत्र में कुल 23 मेगावाट क्षमता की बथनाहा, निर्मली एवं अरारघाट जल विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू कर दिया गया है । ...क्रमश: ...

टर्न-19/ज्योति
21-03-2016

क्रमश:

श्रीमती कविता सिंह : सभापति महोदय, इन छोटी परियोजनाओं के अलावा हमारे यहॉ डाघमरा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट भी कार्य कर रहा है । महोदय, हमारी सरकार दिन

दुनी रात चौगुनी मेहनत करके अकेले अपने दम पर जो केन्द्र से सहायता मिलनी चाहिए थी, उसके अनुरुप नहीं मिल रही है फिर भी सरकार बिहार का नाम देश और विदेश में रौशन कर रही है । महोदय, इसके अलावा नवीनगर स्टेज वन में 660 मे0वा0 की तीन इकाईयों का निर्माण कार्य जारी है और चौसा बक्सर में 660 मे0वा0 की दो इकाईयों के पावर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु सतलज जल विद्युत निगम के साथ हमारी सरकार ने समझौता किया है ताकि और पर्याप्त बिजली बिहार को मिल सके । महोदय, बांका में 106 अल्ट्रा मेगा वाट पावर प्रोजेक्ट लगभग 4 मे0वा0 की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है माननीय भाजपा के सदस्यों से आग्रह है कि केन्द्र से कम से कम सिफारिश तो कर दें आपलोग कि जो बिहार को बिजली के क्षेत्र में मिलना चाहिए जो वहाँ से आना चाहिए बजट उस बजट को बढ़ा दिया जाय ताकि और हमलोग मिलकर साथ चलके बिहार को आगे बढ़ाने में कार्य कर सकें । महोदय, उर्जा समस्या के निदान के लिए गैर पारम्परिक उर्जा स्त्रोत का विकास एक महत्वपूर्ण विकल्प है जिसके तहत बिहार ब्रेडा के द्वारा गैर पारम्परिक उर्जा के विकास के परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका सिर्फ एक मिनट समय बचा है ।

श्रीमती कविता सिंह : महोदय, सोलर रुफ टौप पावर प्लांट अधिष्ठापन योजना अंतर्गत राज्य के शहरी एवं ग्रामीण आवासीय व्यवसायिक परिसरों में वन के0डब्लू0पी0 क्षमता के 6000 अदद रुफ टौप सोलर प्लांट का अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है जो अपने आप में अद्भुत है । यह आम जनता को बिजली की राहत पहुंचाने के लिए है । महोदय, जो बिहार विकास की ऊंचाईयों को छू रहा है उसके बारे में मैं दो शब्द कहना चाहूंगी । माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए कि '' दूर नहीं पास नहीं मंजिल अनजानी , दूर नहीं पास नहीं मंजिल अनजानी, सासों की सरगम पर चलने की ठानी '' और केन्द्र सरकार के बारे में मैं कहना चाहूंगी आप बार बार कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी शायद आप विपक्ष हैं इसलिए बोलते हैं कि लेकिन जो विकास हो रहा है वह शायद उससे आप भी लाभान्वित हो रहे हैं इसके लिए मैं कहना चाहूंगी ''पानी पर लकीर सी खुली जंजीर से कोई मृगतृष्णा मुझे बार बार छलती है'' आप लोग बिहार के साथ छलावा करते हैं । आप वादा करते हैं कि विशेष पैकेज देंगे विशेष राहत देंगे । माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा था कि ''बिजली मिली, बिजली मिली '' । प्रधानमंत्री जी से हम कहना चाहते हैं कि आप बिहार के उन गांवों में उन दलित बस्तियों में आकर देखिये जहाँ पर बिजली की रौशनी से टिमटिमाते हुए गांव जगमग जगमग कर रहे हैं । महोदय, इसी के साथ मेरे क्षेत्र की भी कुछ समस्यायें हैं । उनको मैं बताना चाहूँगी । हमारे क्षेत्र के सिसुआ प्रखंड अंतर्गत महानगर में 25 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर जल चुका है।

वहॉ पर अभी तक ट्रांसफार्मर नही लगाया गया है इसलिए आग्रह है कि महानगर में ट्रांसफार्मर लगाया जाय और ग्राम कचनार के अति पिछड़ों का जो घर हैं वहॉ पर अभी न बिजजी का तार, पोल, ट्रांसफार्मर कुछ भी नहीं लगा हुआ है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादवस) : अब अपना भाषण समाप्त करें ।

श्रीमती कविता सिंह : महोदय, आज पर्यटन विभाग का भी बजट है इसलिए मैं इस सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करती हूं कि आने वाले 25 मार्च को हमारे बिहार सरकार द्वारा मेहन्दार महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी को निमंत्रण है कि कृपया आप उस महोत्सव में शामिल होकर हमें गौरवान्वित करने का अवसर प्रदान करें । आपने मुझे सुनने का मौका दिया । कहने का मौका दिया इसलिए सभी सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री प्रकाश राय जी ।

श्री प्रकाश राय : सभापति महोदय, मैं आसन के प्रति और अपने दल के नेता श्री प्रेम कुमार जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे उर्जा पर बोलने का मौका दिया गया । महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि '' वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उर्जा विभाग हेतु प्रस्तावित 109 अरब 5 करोड़ 3 लाख रुपये की राशि में से 10 रुपये की राशि घटायी जाय ।'' महोदय, किसी भी राज्य की तरक्की करने के लिए मूलभूत सुविधाओं का होना बहुत जरुरी है । बिना इसके कोई भी राज्य आगे नहीं बढ़ सकता । इन मूलभूत सुविधाओं में बिजजी का भी प्रमुख स्थान है । आज बिजली आम लोगों की जरुरत बन चुकी है । महोदय, सरकार ने अपने 7 निश्चय में से एक ''हर घर बिजली के'' तहत आज के सभी घरों को बिजली देने का निर्णय लिया है जिसके तहत सभी बी.पी.एल. परिवारों और मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत दो वर्षों में सभी ग्रामीण ए.पी.एल. परिवारों को विद्युत संबंध देने का लक्ष्य रखा गया है परन्तु महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बी.पी.एल. कनेक्शन देने में सरकार लक्ष्य से काफी पीछे है महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बी. पी.एल. परिवार को मुफ्त बिजली कनेक्शन देने में बिहार देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे पीछे चल रहा है । महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा प्रति बी.पी.एल. परिवार तीन 3 हजार रुपये अनुदान देने के बावजूद बिहार में 83 लाख बी.पी.एल. परिवारों में से मात्र 8 लाख 77 हजार 557 परिवारों को ही विद्युत कनेक्शन दिया गया है जबकि ग्रामीण ए.पी.एल. परिवार को अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत गहन विद्युतीकरण के मामले में सरकार फीसड्डी साबित होती जा रही है । ग्रामीण विद्युतीकरण के अंतर्गत गहन विद्युतीकरण 46,475 गांवों में किया जाना था परन्तु राज्य सरकार अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है । महोदय, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जले ट्रांसफार्मर शीघ्र बदलवाने में भी

सरकार असफल साबित हो रही है । महोदय, राज्य सरकार द्वारा 24 घंटे में शहर के इलाके में और 72 घंटे में ग्रामीण क्षेत्रों के इलाकों के जले और खराब ट्रांसफार्मर बदलने का दावा किया जा रहा है परन्तु वास्तविकता इसके उल्टा है । शहरों में तो किसीतरह जले और खराब ट्रांसफार्मर बदल भी दिए जाते हैं परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रांसफार्मर बदलवाने में ग्रामीणों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । महोदय, राज्य की राजधानी पटना सहित राज्य के तमाम शहरों में बस गए अथवा तेजी से बस रहे नये मोहल्लों में आज भी लोगों द्वारा बांस के सहारे तार खींच कर बिजली का कनेक्शन लिया जा रहा है परन्तु सरकार इस मुद्दे पर भी उदासीन बनी हुई है । महोदय, बिजली चोरी रोकने में भी सरकार असफल साबित हो रही है । एक तरफ सरकार निर्बाघ विद्युत आपूर्ति करने का दावा करती है । अन्डरग्राउन्ड केबलिंग का कार्य करा रही है वहीं दूसरी तरफ लोगों द्वारा बिजली की चोरी भी की जा रही है परन्तु सरकार इसे रोकने में असफल है । लोग टोका फंसाकर बिजली चोरी कर रहे हैं परन्तु सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे पा रही है, जिस कारण बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी घाटे में चल रही है । महोदय, गलत बिलिंग के शिकायतों को लेकर उपभोक्ता बिजली औफिस दौडरने पर मजबूर हो रहे हैं । मीटर से अधिक बिलिंग तथा कभी कभी विपत्र की रकम जमा करने के बावजूद अत्यधिक बिल आने से आम उपभोक्ता काफी त्रस्त हैं । उन्हें बिल का सेट्लमेंट के लिए बिजली औफिस का चक्कर लगाना पड़ता है परन्तु सरकार द्वारा इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । महोदय, विभाग मीटर रीडर को ट्रेनिंग की समुचित व्यवस्था करे ताकि गलत बिलिंग और गलत मीटर रीडिंग नहीं हो सके । महोदय, बिहार के 24 जिलों के 44 सब स्टेशनों का कार्य पूरा नहीं होने से निर्बाघ बिजली देने का सरकार का दावा विफल प्रतीत होता है जिसमें पूर्णिया, सिवान, में एक एक भोजपुर में दो सब स्टेशन, पूर्वी चम्पारण में 6 बेगुसराय एवं पश्चिम चंपारण में तीन तीन, कटिहार में 7, सीतामढ़ी, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बक्सर, जमुई, अरवल, लख्खीसराय, शेखपुरा, गोपालगंज,समस्तीपुर में एक एक, सारण में चार दरभंगा, शिवहर और भागलपुर में दो दो सब स्टेशन का निर्माण आधा अधूरा पड़ा हुआ है जबकि इसकी स्वीकृति तीन साल पूर्व 2013 में ही मिल गयी थी । महोदय, सब स्टेशनों का निर्माण नहीं होने से 30-35 लाख की आबादी को निर्बाघ बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है । महोदय, पटना जिला में 1700 गांव और 2250 टोलों के 4 लाख 63 हजार मकानों में 5 लाख 46 हजार 154 परिवार रहते हैं । जिसमें से 2 लाख 12 हजार 362 परिवार के घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है । महोदय, चूँकि बिहार सरकार राज्य के सभी शहरों और ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली देने, ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत बी.पी.एल. परिवारों एवं मुख्यमंत्री

विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत ए.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने में असफल साबित हो रही है इसलिए मैं उर्जा विभाग की इस मांग की कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ । महोदय, मैं उर्जा मंत्री जी का ध्यान एक तरफ और आकृष्ट करना चाहता हूँ कि बिहार में जो हमारे ग्रामीण विद्युतीकरण का काम चल रहा है, यहाँ माननीय सभी सदस्य इससे वाकिफ हैं और मैं पिछले साल भी उर्जा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि जो तार लग रहे हैं, जो पोल लग रहे हैं, वह बहुत घटिया क्वालिटी के हैं काफी लोग- इससे तार टूट कर गिरने से सिर्फ मेरे क्षेत्र में 30 मौत हो चुकी है जो तार और पोल लगे हुए हैं आज उसका मैंने कहा है सी0एम0डी0 प्रत्यय अमृत साहेब को देखिये कि जो तार पोल बिजली लग रहे हैं वे छः महीना एक साल के अंदर बेंट कर जा रहे हैं बहुत जगह टूट गए हैं मैं आसन कके द्वारा यह बताना चाहूगा उर्जा मंत्री जी को कि जो घटिया तार की क्वालिटी जो केबुल वायर लग रहा है उसकी जॉच करायें और उचित कार्रवाई करें । जो पोल को जो एक मानक है जो पोल हेलाने का उस मानक में वह पोल नहीं हेल रहा है जिसके कारण पोल का सारे पोल या तो गिर जा रहे हैं या झुक जा रहे हैं और मैंने पिछले बार भी कहा था महोदय, कि बिजली के तार जो 11 हजार वाट के जो तार हैं उसकी मैंने जॉच करायी है मैं सदन के पटल पर जब भी चाहेंगे रख दूँगा कि वह 11 हजार की कैपेसिटी नहीं ले सकता है और यही कारण है कि निर्बाघ बिजली प्रवाहित होती है तो बिजली का तार टूट कर गिरता है और लोग भी मरते हैं । फसल भी जल कर उससे बर्बाद होती है । माल जानवर कितने मर गए और सभी हमारे क्षेत्र की बात नहीं है पूरे बिहार की बात है और मैं माननीय उर्जा मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहूँगा कि इस ओर जाय और उसकी जॉच करायें। जो कंट्रैक्टर की धीमी गति है हमलोग बार बार इस बात को नोटिस में लाकर देते हैं कि ये कंट्रैक्टर जो हैं, काम जो कर रहे हैं जो जो मैं बता रहा हूँ जो कंट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनके पीछे पेटी कंट्रैक्टर हैं, पेटी के बाद सेटी कंट्रैक्टर हैं , सेटी के बाद हेटी कंट्रैक्टर हैं और कंट्रैक्टर हर गांव में वसूली कर रहे हैं । पैसा वसूल करते हैं बिजली के पोल को पैसा लेकर ग्रामीणों से ढोलवाते हैं और वह काम सही नहीं हो रहा है । माननीय महोदय, मैं ये आपके द्वारा बताना चाहता हूँ कि अगर इसपर सही ढंग से इंक्वायरी हो तो ये बहुत बड़ा स्कैण्डल पकड़ा जायेगा । धन्यवाद ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी आपके पास 6 मिनट का वक्त है ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी : सभापति महोदय, मैं उर्जा विभाग के 109 अरब 5 करोड़ 3 लाख 31 हजार रुपये के अनुदान के पक्ष में एवं विपक्ष के कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूँ । सभापति महोदय, जैसा कि सभी जानते हैं

कि आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के द्वारा स्थापित 1985-90 के कार्य काल में पूरे देश को चिन्हित किया गया कि पिछड़े अति पिछड़े जो भी लोग हों पूरे हिन्दुस्तान में उनको राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत जोड़ा जाय । मान्यवर, अपार हर्ष होता है जब ये लोग कहते हैं कि सारा काम हमने किया ।

क्रमशः

टर्न-20/21.3.2017/बिपिन

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः क्रमशः सारे सदस्य लोग जानते हैं । आदरणीय मुख्यमंत्री अपने प्रथम कार्यकाल में जब बिहार का दौरा कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से अगले बार वोट मांगने के लिए आपके बीच में नहीं आऊंगा और हरेक गांव को बिहार के हरेक टोला और बसावट को बिहार के बीच अगर विद्युतिकरण नहीं किया गया तो मैं आपके बीच वोट मांगने नहीं आऊंगा । मान्यवर, आपलोगों ने सुना होगा । महागठबंधन की जब चुनाव चल रही थी तो एक आवाज आती थी क्या बिहार में बिजली आई ? लोग कहते थे-बिजली आई, बिजली आई । आदरणीय हमारे विपक्षी साथी आरोप लगाने के पहले अपने गिरावाँ में अवश्य झांकना चाहिए कि पूर्व की यू.पी.ए. सरकार ने इस देश के लिए क्या किया और वर्त्तमान की आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार ने बिहार के लिए क्या किया और क्या कर रहे हैं । इनके सात निश्चयों में एक हमारा निश्चय हर घर को लगातार बिजली का निश्चय दिया गया है । माननीय साथियों, कुछ आंकड़ा है बिहार सरकार का जो कि मैं आपके बीच में देने जा रहा हूं । वर्ष 2010-15 तक 1712 मेगावाट बिजली की सप्लाई होती थी लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 3796 मेगावाट बिजली हमारे बिहार को अनवरत रूप से मिल रही है । साथियों, आंकड़ों पर यदि गौर करें तो इन पांच सालों में बिहार में बिजली के क्षेत्र में 120 प्रतिशत् की बढ़ोत्तरी हुई । यह अपने आप में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए काफी है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में औसत उपलब्धता से जो 6 से 8 घंटा पहले बिजली रहती थी, आज 14 से 18 घंटे हमारे गांव में और कृषि के लिए बिजली उपलब्ध है । साथियों, शहर में बिजली जो 16 से 18 घंटा मिलती थी, आज वह बिजली 18 से 22 घंटा अनवरत हमारे शहरों में मिल रही है । साथियों ...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, आप यहां साथियों नहीं, माननीय सदस्य बोलें ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारीः जी । क्षमा । बोलने के क्रम में गलती हो जाती है । मैं इसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं ।

आदरणीय सदस्यगण, अभी जो हमारी विद्युत की स्थिति थी सभापति महोदय, 2010-15 में 145 कि0वा0 घंटे से बढ़कर 2017 में 258 कि0वा0 हमारी विद्युत आपूर्त्ति अभी निर्बाध गति से हमारे बिहार को मिल रही है । सभापति महोदय, उल्लेखनीय है कि राज्य में विद्युत खरीद और उत्पादन के मामले में 1196 करोड़ यूनिट से बढ़ कर

2015-16 में 2167.07 करोड़ यूनिट आज वर्त्तमान में हो गई है । सभापति महोदय, अभी तक जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बांका ताप विद्युत परियोजना चल रहा है, 2500 एकड़ जमीन चिन्हित् करके उसका पैसे का आबंटन भी आदरणीय मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया है । हमारे बक्सर में जो 1320 मेगावाट विद्युत की ऊर्जा की आपूर्त्ति होगी, सभापति महोदय, उसको आज से पांच वर्ष पहले आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, ऊर्जा मंत्री के नेतृत्व में पूरा कर लिया गया है और वहां काम द्रूत गति से शुरू कर दिया गया है । सभापति महोदय, आज कृषि में भी हमारे बिहार का अव्वल स्थान है । राज्य में विद्युतिकरण जो कृषि में 620 करोड़ कलेक्शन पहले था, आज उसके 2.240 करोड़ के कलेक्शन का अनुमान बिहार सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में लगातार यह प्रयास बिहार सरकार का है कि कृषि क्षेत्र में हमारा ऊर्जा का प्रयास लगातार जारी रहे । सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान विद्युत जल परियोजना पर भी आकृष्ट कर रहा हूं । सभापति महोदय, अभी 13 परियोजनाएं, हमारे लघु विद्युत परियोजना 13 चल रही है बिहार में जिनमें 54 मेगावाट बिजली मिल रही है और 17 परियोजनाओं पर हमारा काम द्रूत गति से चिन्हित् कर उनको करने का काम बिहार सरकार कर रही है ।

सभापति महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक समस्या की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में पांडेयपट्टी एक बस्ती है । पांडेयपट्टी की आबादी ढ़ाई से तीन हजार है । उसके छत के उपर से 11000 वोल्ट का तार प्रवाहित होता है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि निकट भविष्य में या तो उसको कॉपर से युक्त करा दिया जाए अथवा उस 11000 वोल्ट के तार को वहां से स्थानान्तरित कर बगल में कराने की कृपा अगर करेंगे तो भविष्य में वहां की जान-माल की सुरक्षा हो सकती है। आज पर्यटन के उपर भी, चूंकि पर्यटन में बक्सर, सभापति महोदय, बिहार में अव्वल स्थान रखता है.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): आपका समय हो गया है ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: महोदय, यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, पर्यटन मंत्री भी बैठी हैं । महोदय, हमारा बक्सर में सीताराम विवाह महोत्सव होता है और चाहे वह लिट्टी-चोखा का ही महोत्सव क्यों न हो, सर्वोपरि है और वहां बहुत तगड़ा भोज होता है । उसमें पंचकोसी परिक्रमा होती है । हमारे आदरणीय साथी जो शाहाबाद से बिलॉग करते हैं, आते हैं.....

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): अब अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी: सभापति महोदय, मैं पर्यटन मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बक्सर में पर्यटन पर ध्यान देते हुए निश्चित रूप से आप उस काम को आगे बढ़ाएं । नारायण सर्किट से हमारा बक्सर जुड़ गया है । आपने हमें आश्वस्त किया है । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे बक्सर को उचित स्थान देने का कृपा करें । इन्हीं चंद

शब्दों के साथ-साथ सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी सयबात समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री प्रहलाद यादव जी । पांच मिनट है प्रहलाद बाबू आपको ।

श्री प्रहलाद यादव : सभापति महोदय, आज ऊर्जा विभाग का जो डिमांड है, उसका समर्थन करते हैं और कटौती प्रस्ताव का विरोध करते हैं ।

मुझे बहुत कम समय है, इसलिए कम समय में ही अपनी बात को रखना चाहता हूं सभापति महोदय ।

सभापति महोदय, निश्चित रूप से ऊर्जा विभाग पूरे बिहार के लिए एक वरदान साबित हुआ है । इस मद में जो रिपोर्ट में आया है, जैसे, शहर में 22 घंटा तक की बात आई है । माननीय मंत्री जी, हमलोग के गांव में 22-23 घंटा तक बिजली आती है, देहात में, यह स्थिति है बिजली का । बिजली का कोई चुनौती विपक्ष के लोग नहीं दे सकता है, जो स्थिति अभी बनी हुई है । जरूरत इस बात की थी कि जब राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण का शुरूआत हुआ था तो उस समय हमलोग को नब्बे रूपया मिलता था, सौ में नब्बे मिलता था भारत सरकार से, दस रूपया हमलोग को खर्च करना पड़ता था । अभी एक तरफ कह रहे हैं कि हम बिहार को देख रहे हैं, तो बिहार को यही देख रहे हैं कि अब हमको देना पड़ता है दस के जगह पर चालीस और साठ परसेंट आप देते हैं । स्पेशल प्लान जो था बी.आर.जी.एफ. का, इसमें जो था, सरकार को ससमय केन्द्र सरकार को यह दे देना चाहिए, नहीं दिया । बिहार सरकार अपने संसाधन से लोन लेकर इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है । यह कोई मामूली काम नहीं हो रहा है और बिजली के सवाल पर, बिजली के लिए जितनी भी हम अनुशंसा करें, वह कम होगा । पहले प्रति यूनिट 203 था एक आदमी पर, आज कितना है, 258 है । यह स्थिति है बिजली का । जहां तक संचरण की बात है, जहां तक गांव में बिजली की बात है, कोई ऐसा गांव नहीं है कि जहां बिजली आज के डेट में नहीं है । हर जगह बिजली है और निश्चित रूप से बिजली अबाध रूप से मिल भी रही है । हम माननीय मंत्री जी को, हम अपने क्षेत्र, अपने जिला की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, चूंकि विशेष बोलने के बाद हमलोगों का समय कम है, इसलिए अपना बात छूट जाएगा ।

महोदय, लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड के कजरा में, कजरा एक जगह है जहां कि पावर प्लांट लगना था, जमीन भी एक्वायर हो गया । उसके कुछ एरिया में टेंडर होकर टावर भी बन गया लेकिन एकाएक वह प्लांट हम समझते हैं कि वह बंद हो गया .... क्रमशः

टर्न : 21/कृष्ण/21.03.2017

श्री प्रह्लाद यादव : (क्रमशः) हम समझते हैं कि वह बंद हो गया । तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि वह उस इलाके के लिये एक बहुत बड़ी चीज थी और बहुत जरूरी था । इसलिए इस प्लांट को निश्चित रूप से चालू किया जाय, जिस किसी कारण से हो, वह पावर प्लांट बंद है । सरकार राशि भी दे चुकी है, जमीन भी एक्वायर्ड है, किस कारण से बंद है, हम को पता नहीं है । महोदय, दूसरी बात यह है कि दो सब स्टेशन है हमारे सूर्यगढ़ा विधान सभा क्षेत्र में - एक है सूर्यगढ़ा प्रखंड के माधवपुर गांव के बगल में आरै दूसरा है चानन प्रखंड के रामपुर इटौन के बगल में । ये दोनों सब स्टेशन पिछले तीन-चार वर्षों से बन ही रहा है, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है । माननीय मंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि इस को भी पूरा किया जाय । चूंकि दोनों बड़ा एरिया है, जिसके कारण बिजली सही ढंग से नहीं मिल पाती है । हमारे क्षेत्र में एक है पीरी अभयपुर है, जो जमालपुर से सटा हुआ है, उसका बिजली जमालपुर से मिलती है, जिससे लखीसराय जिला के पीरी अभयपुर जोन में सही ढंग से, जो बिजली आना चाहिए, वह नहीं आ पाता है । इसलिये इसका भी सुधार हो । या तो इसको सूर्यगढ़ा ग्रीड से जोड़ दिया जाय या लखीसराय सब-ग्रीड से जोड़ा जाय । चूंकि दूसरे जिला से आने में हमेशा दिक्कत होती रहती है । महोदय, इतना ही नहीं, लखीसराय के तीन पंचायत है - मोरमा, अमहारा और कछियाना है । ये तीनों रामगढ़ प्रखंड के ग्रीड से जुड़ा हुआ है, जो बहुत दूरी पर है, जिस के कारण इन तीनों पंचायतों में बिजली आने में काफी व्यवधान होता है, हमेशा दिक्कत होती रहती है । इसलिए माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इन तीनों पंचायतों को लखीसराय ग्रीड़ से जोड़ा जाय ताकि उसको सुविधा हो ।

दूसरी बात जमुई के संबंध में है । पिछड़ा, अतिपिछड़ा, दलित, महादलित गांव में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, तार, पोल भी रखा हुआ है, जिसे सामंती ताकत उठाकर जबर्दस्ती ले गये हैं । विभाग के पदाधिकारियों से कई बार इसकी शिकायत की गयी । कम से कम दलित गांव है। इस पर ध्यान दिया जाय ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य, आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, एक मिनट और दिया जाय ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, इनको मेरी पार्टी की ओर से दो मिनट और दे दिया जाय ।

श्री प्रह्लाद यादव : महोदय, तो इस तरह से वहां जो दलित है, पिछड़ा है, वहां निश्चित रूप से विद्यतीकरण होना चाहिये ।

महोदय, आज पर्यटन विभाग का भी है । मैं माननीया मंत्री महोदया को याद दिलाना चाहता हूं कि जलप्पा स्थान एक शक्तिपीठ है, पहाड़ के बगल में है । वहां सालोभर ब्याह होता है, मुंडन होता है और वहां प्रतिदिन लोग हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिये जाते हैं । महोदय, एक सिंहऋषि है, जो चारो तरफ से पहाड़ से घिरा

हुआ है, वह बड़ा ही रमणिक जगह है, जहां पर रामजी का मुंडन हुआ था । वह सूर्यगढ़ा प्रखंड में पड़ता है । माननीया मंत्री महोदया से आग्रह करूंगा कि इसको भी नोट कर लिया जाय और उसको पर्यटक स्थल के रूप में घोषित किया जाय । वह बड़ा ही ऐतिहासिक है, देखने लायक है और पर्यटन विभाग की सारे शर्त्तों को वह पूरा करता है ।

महोदय, आज विभाग का जो प्रस्ताव आया है, निश्चित रूप से जनोपयोगी है और प्रदेश के लिये यह एक वरदान है और हम इस तरह कह सकते हैं कि विद्युत विभाग हो या कल्याण विभाग हो या पर्यटण विभाग हो, महागठबंधन की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के के नेतृत्व में यह सरकार बड़ा ही कायदे से, बड़ी ही शांतिपूर्वक चल रही है । हम उम्मीद करते हैं और विपक्ष से आग्रह करते हैं कि आप सहयोग करते रहें और महागठबंधन की सरकार बहुत तेजी से और समाज को आगे बढ़ाने का काम करती रहेगी । जय हिंद ।

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय सभापति महोदय, लोकतंत्र के इस पवित्र सदन में वित्तीय वर्ष 2017-18 के व्यय विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांग के समर्थन में आप के द्वारा मुझे बोलने का समय दिया गया है, जिस के लिये मैं आप का आभार व्यक्त करता हूं । मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय ऊर्जा मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी का और मैं आभार व्यक्त करता हूं संसदीय कार्य मंत्री महोदय का ।

महोदय, बिजली बिजली हो रहा है लेकिन बिजली की मैं जितनी भी बड़ाई करूं, वह कम होगा । आज बिजली की कहीं कोई शिकायत नहीं है । हमारे कई माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं । यह सही बात है कि आज हमलोगों को कहीं बिजली की शिकायत नहीं मिल रही है । खासकर हम अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहते हैं, एक साल हो गया है, महागठबंधन का अपार बहुमत मिला और जब क्षेत्र का भ्रमण करना शुरू किये तो मुरलीगंज के ग्वालपाड़ा प्रखंड से 12, 13 टोला से बिजली का पीटीशन मिला था, बिजलीविहीन टोला की शिकायत मिली थी, आज मात्र सात-महीने में हमें जहां शिकायत मिली, उस आवेदन को विभाग में भेजने का काम किया और केवल एस0डी0ओ0 को फोन से बोले और इस सरकार के ऊर्जा विभाग का, माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरूष की देन है और हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय की देन है कि मेरे क्षेत्र में आज बिजली की कोई शिकायत नहीं है और हरेक बिजलीविहीन टोला आज बिजली मय है । मेरे यहां दो अल्पसंख्यक टोले हैं, वहां ट्रांसफरमर चार्ज हो गया, वहां के लोगों ने दो दिन इंतजार किया कि जबतक माननीय विधायक अपने से

आकर बटन नहीं दबायेंगे तो हमलोग बिजली नहीं जलायेंगे । ऐसा बिजली का हाल है, हम क्या बड़ाई करेंगे महोदय, पहले ट्रांसफरमर 6 महीना में नहीं लगता था, अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि 15 दिन, एक महीना में नहीं लगता था, इस सदन में तीन लाख के जनप्रतिनिधि बैठे हुये हैं, जब पीटीशन जाता है, आवेदन जाता है कार्यपालक अभियंता को तो ट्रांसफरमर दो दिन में लग जाता है, हमने तो 12 घंटा में फोन कर के ट्रांसफरमर लगवाया है, अपने क्षेत्र में तथा और कहीं कोई शिकायत नहीं है। बिजली सबों के लिये मूलभूत आवश्यकता है, आज बिजली नहीं रहेगी तो न तो ए0सी0 चलेगा, न मोबाईल चार्ज होगा । आज हरेक कार्यक्रम बिजली से होता है । आज सब जगह बिजली है । इसलिए मेरा आग्रह है कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य बड़ाई करें । माननीय प्रधानमंत्री बिहार आकर शराबबंदी और बिजली की बड़ाई कर के गये हैं । हाजीपुर के एक सभा में शराबबंदी की बड़ाई कर के और मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देकर हमारे प्रधानमंत्री महोदय यहां से गये । इसलिये हम विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में विरोधी दल सरकार के अंग माने जाते हैं तो उसका सदुपयोग कीजिये । बिजली विभाग की बहुत सारी उपलब्धियां है और उन उपलब्धियों को हम इस सदन में पेश करना चाहता हूं । माननीय ऊर्जा मंत्री हमारे इलाके से आते हैं और वे हमारे गार्जियन भी हैं । राज्य में बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है । कांटी विद्युत प्रतिष्ठान की क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 195 मेगावाट की दो इकाईयों के निर्माण का कार्य अंतिम चरण में है । राज्य योजना के तहत ताप विद्युत इकाई, बरौनी की क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 250 मेगावाट का दी गयी इकाईयों का कार्य निर्माणाधीन है ।

क्रमश :

टर्न-22/राजेश/21.3.17

श्री निरंजन कुमार मेहता, क्रमशः जिसे नवंबर, 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है, नवीनगर में 660 मेगावाट की तीन ताप विद्युत इकाई जिसकी कुल क्षमता 1980 मेगावाट है, के निर्माण में प्रगति हो रही है और इसे जून, 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । सभापति महोदय, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत प्रतिष्ठान की क्षमता विस्तार परियोजना के तहत 3345 करोड़ रुपये की योजना से 195 मेगावाट की दो ईकाईयॉं, कुल 390 मेगावाट के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, दोनों ईकाईयों को चालू करने का लक्ष्य फरवरी, 2017 है । सभापति महोदय, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड एवं एन0टी0पी0सी0 के 50-50 अनुपात में संयुक्त उपक्रम नवीनगर पावर जेनरेशन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड द्वारा नवीनगर में नये ताप विद्युत केन्द्र 1980 मेगावाट फेज-1 की

15132 करोड़ की लागत से की जा रही है, इस परियोजना को जून, 2018 तक किये जाने की संभावना है । सभापति महोदय, संचरण के क्षेत्र में भी उत्साहवर्द्धक उपलब्धियॉं हासिल हुई है । वर्तमान में 3769 मेगावाट पावर की आपूर्ति की जा चुकी है और आपूर्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि करने का भी प्रयास जारी है । महोदय, 31 राजस्व अनुमंडलों में ग्रीड उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2017 तक पूर्ण किया जायेगा । स्पेशल पावर बी0आर0जी0एफ0 के तहत 7 ग्रीड उपकेन्द्रों का निर्माण वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत तक किये जाने का लक्ष्य है । सभापति महोदय, ग्रीड सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि 47 उपकेन्द्रों में क्षमता वृद्धि के कार्य कराये जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत 220 के0भी0ए0 स्तर पर 360 एम0भी0ए0, 132 स्तर पर 2490 एम0भी0ए0 तक का क्षमता विस्तार होगा, उपर्युक्त सभी परियोजना को 2017 तक पूरा करने का लक्ष्य है । सभापति महोदय, वितरण के प्रक्षेत्र में भी स्पेशल बी0आर0जी0एफ0 के अन्तर्गत दो योजनाएँ स्वीकृत हैं, फेज–1 में 21 उपकेन्द्र का निर्माण कार्य हो चुका है और शेष चार का निर्माण जून, 2017 तक कर लिया जायेगा । विद्युत क्षेत्र में लोड की मांग को पूरा करने हेतु 274 किलोमीटर नये 33 के0भी0ए0 लाईन, 20315 किलोमीटर तथा 11 के0भी0ए0 लाइन का निर्माण .....

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य, अब एक मिनट का वक्त आपके पास है ।

श्री निरंजन प्रसाद मेहता: सभापति महोदय, बिजली विभाग का बहुत बड़ी उपलब्धि है, अगर बिजली विभाग पर दिनभर बोलेंगे तब भी कम होगा, लेकिन आपका आदेश मानेंगे और सिर्फ एक मिनट अपनी बात को रखने का मौका दिया जायेगा । सभापति महोदय, 7 निश्चय के तहत हर घर में बिजली निश्चय का शुभारंभ 15 नवंबर, 2016 को किया गया है और इस अभियान के अन्तर्गत विगत दो वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विद्युत निश्चय सब योजना के तहत राज्य सरकार अपने संसाधनों से पहले बहुत से माननीय सदस्य बोले हुए हैं, 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार से मिलता था लेकिन अब इसमें कटौती करके 60 प्रतिशत ही मिलता है और आज हमारी सरकार, महागठबंधन की सरकार, अपने संसाधन से बिजली उपलब्ध करायी है, अगर उसपर दिन भर बोलेंगे, तब भी कम होगा, तो बिजली का बड़प्पन तो बहुत है लेकिन एक बात हमारे क्षेत्र से संबंधित है, उर्जा मंत्री जी हमारे क्षेत्र से ही है, हमारे इलाके से है, एक बहुत छोटी सी बात है, मैं इनको कहने के लिए नहीं चाहा था लेकिन आज से तीन महीना पहले, हमलोगों को तीन लाख लोगों का प्रतिनिधित्व मिलता है महान जनतागण से, तीन महीना पहले, यहॉं बैठे हुए है एम0डी0 नॉर्थ बिहार संदीप साहब, हमने एक रिकोमेनडेशन करके इनके चैम्बर में जाकर मिला था, मैंने पहले ही बोल दिया कि छोटी सी बात के लिए मैं माननीय मंत्री जी के यहॉं नहीं गया, हमारे यहॉं उदाकिशुनगंज अनुमंडल में

प्रकाश मंडल जी एक एस0डी0ओ0 है, किसी का भी फोन आता है लेकिन वह नहीं सुनता है, जबकि आपको मालूम होगा कितना आपात स्थिति बिजली में होता है लेकिन वह फोन नहीं उठाता है, तो बिजली विभाग कितना इमरजेंसी विभाग है, अस्पताल कितना इमरजेंसी विभाग है, इस बात को सभी हमारे माननीय सदस्य जानते हैं लेकिन आज एस0डी0ओ0 का क्या क्षमता है, हमलोगों का फोन भी वह नहीं उठाता है, महोदय हमने एक शिकायत दिया था और जिला पदाधिकारी महोदय का रिकोमेनडेशन है और आज तक लगता है कि उस कागज को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, सभापति महोदय, आज आसन पर बैठे हुए हैं, उस एस0डी0ओ0 से हमारे सभापति महोदय भी परिचित है, मेरा मांग है कि उस सहायक अभियंता को निलंबित करते हुए दूसरा सहायक अभियंता दिया जाय और मेरी मांग को स्वीकार किया जाय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ और आपके माध्यम से बिजली मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ । जय हिन्द, जय बिहार, जय महागठबंधन ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव): माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार । आपके पास 7 मिनट का समय है।

श्री मनोज कुमार: सभापति महोदय, आज हमारे नेता और हमारे दल के सचेतक श्री अरुण सिन्हा जी के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में और सरकार के द्वारा एक सौ नौ अरब, पॉच करोड, तीन लाख, एकतीस हजार रुपये का जो अनुदान की मांग आज सदन से की है, उसके विरोध में मैं बोलने के लिए खड़ा हूँ ।

महोदय, बिजली एक ऐसा क्षेत्र है, जब तक बिजली में पूर्ण शत-प्रतिशत उपलबधियॉ हासिल नहीं करते हैं, तो विकास के क्षेत्र में आप पीछे चले जायेंगे क्योंकि अकेला बिजली एक ऐसा क्षेत्र है, इसलिए इसकी उपयोगिता हमारे लिए, इस सदन के लिए, सभी माननीय सदस्यों के लिए उपयेगिता इतनी बड़ी हुई है कि आज उसके बारे में जब हमलोग विमर्श कर रहे हैं, तो हमें 100 प्रतिशत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाना होगा । महोदय, मैं यह मानता हूँ कि उत्पादन के क्षेत्र में मुझे यह दिख रहा है कि आने वाले तीन, चार वर्षों में, बिहार उत्पादन के क्षेत्र में काफी अग्रणी राज्य हो जायेगा, जितनी योजनाएँ यहॉ चल रही हैं, चाहे वह बरौनी की ताप योजना हो, चाहे वह कॉटी की योजना हो, नवीनगर में रेलवे या एन0टी0पी0सी0 हो या बिहार सरकार की योजना हो, चौसा की जो योजना हो, बॉका में जो आप ग्रीन फिल्ड एरिया में जो काम करने जा रहे हैं, चाहे सोलर सिस्टम में काम करने जा रहे हैं, मेरा पूरा यह विश्वास है कि आने वाले वर्षों में बिजली उत्पादन के मामले में बिहार देश का अव्वल राज्य बनेगा लेकिन साथ ही साथ समस्या कहॉ आयेंगी, जो मुझे समस्या दिख रही है, मुझे समस्या दिख रही है ट्रान्समिशन की, मुझे समस्या दिख रही है डिसट्रिब्यूशन में, मुझे समस्या दिख रही है रेवेन्यू कलेक्शन में और इन सर्किलों को जब तक हम पूरा दुरुस्त नहीं

करेंगे, तब तक उत्पादन करने के बाद भी, जब तक हम अपने संचरण पूरी तरह से 100 प्रतिशत नहीं सुधार लें, डिस्ट्रिब्यूशन को जब तक एक-एक घर में बिजली नहीं पहुंचा दें और रेवेन्यू सिस्टम को जब तक दुरुस्त नहीं कर लें, मैं आपको कुछ उदाहरणों से बताना चाहूंगा कि हमलोग ट्रान्समिशन में कैसे फेल कर रहे हैं, ट्रान्समिशन की जो मैक्सिमम योजनाएँ चल रही हैं, जो सारी वृहद योजनाएँ चल रही है, बी0आर0जी0एफ0 फेज-टू से जिसमें 33 के0भी0ए0, 11 के0भी0ए00 का पावर सब-स्टेशनों का निर्माण, अगर यह सारे जिलावाईज, ब्लॉक वाईज माननीय मंत्री जी, सचिव जी, अगर इसको जिलावाईज, ब्लॉकवाईज एक-एक योजना को देखे और उसका जो एचिभमेंट है, उसको अगर देखेंगे, तो हमलोग 20 से 30 प्रतिशत ही एचिभ कर पाये है, बी0आर0जी0एफ0 फेज-टू में मैं जब बात करता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि केन्द्र सरकार के पैसे का यहाँ काफी कमी है, मैंने तो देखा है कि राज्य सरकार ने अलग से पॉच हजार करोड़ के ऋण की व्यवस्था की है, मैं यह चाहता हूँ कि इन सारी योजनाओं को जो लक्ष्य के आधार पर निर्धारित योजनाएँ हैं, अगर समय से इसको पूरा नहीं करेंगे, तो कल होकर इसके कॉस्ट का जो ओभर रन होगा, तो उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ेगा महोदय । महोदय, अब ग्रामीण विद्युतीकरण में बी0आर0जी0एफ0 फेज-टू के बारे में बता दिया, हमारे जिला में बी0आर0जी0एफ0 योजनाओं के तहत फेज-टू में जो योजनाओं को होना था, वह पिछड़ रहा है और दिन दयाल योजना से भी जो काम होना था, वह भी काफी पिछड़ गया है, महोदय पूरे औरंगाबाद जिले में 1900 गॉव हैं, 900 गॉवों में आधी अधूरी काम करके ऐसे ही पड़ा हुआ है, कहीं पोल गाड़ा गया है, कहीं ट्रान्सफर्मर ऐसे ही रखा हुआ है, कहीं तार नहीं है और शेष जो 900 गॉव हैं, वह बिल्कुल अन-इलेक्ट्रीफायड है, जहाँ पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है, उसकी समस्या आज बिल्कुल ही ठप्प पड़ी हुई है । महोदय, ये जो समस्याएँ आ रही हैं और अब मैं रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में बोल रहा हूँ, रेवेन्यू कलेक्शन की जो स्थिति है, जो गलत बिलिंग की परम्परा चली आ रही है, वह आज भी चली आ रही है, राज्य सरकार ने काफी अच्छा निर्णय लिया था कि हर डिवीजनल बिजली ऑफिस में हर महीने के 15 तारीख को उपभोक्ताओं की समस्या का निबटारा उसी समय किया जायेगा लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है, अब एक चीज और हो गयी है रेवेन्यू लिंक सिस्टम से, अब तो पावर सप्लाई को भी जोड़ दिया गया है ।

क्रमशः

टर्न-23/सत्येन्द्र/21-3-17

श्री मनोज कुमार (क्रमशः): और हमारे यहां स्थिति यह है कि 6-6 घंटे एक-एक पावर सब स्टेशनों में रेवन्यू लिंक सिस्टम के तहत में बिजली की कटौती कर दी जा रही है । अब एक तो प्रोपर बिलिंग नहीं हो रही है और पंचायत बाईज मीटर रीडिंग नहीं हो रही है

जिससे रेवेन्यू कलेक्ट नहीं हो पा रही है और उस रेवन्यू कलेक्शन का रेवन्यू लिंक से हमारे यहां 6-6 घंटे बिजली की आपूर्त्ति बाधित हो जा रही है तो महोदय, इन तमाम बातों में मैं कुछ कुछ बातों पर मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा और कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा । हमारा एक सुझाव है कि एक स्मार्ट मीटर लगाया जाय, स्मार्ट मीटर लगाने से इन समस्याओं पर काफी हद तक उसको हमलोग वहीं पर रोक सकते हैं और जो फीडर वाईज जैसे हमारे क्षेत्र में 9 फीडर है, फीडर वाईज दो-दो मानव बल की नियुक्ति की जाय। फीडरवाईज मानव बल की नियुक्ति नहीं हो पाने से तो जब कहीं भी कोई समस्या आती है तो उसे निपटारा करने में काफी समय लग जाता है इसलिए हमारा एक सुझाव है कि हर फीडरों में दो दो मानव बल की नियुक्ति की जाय और रूलर रेवन्यू फ्रेंचाईजी का जो चयन होना है उसे सुनिश्चित किया जाय और हर पंचायत में एक आर0आर0एफ0 एजेंसी एक महीने में, दो महीने में आज सदन में मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट कर रहा हूँ कि ये सुनिश्चित की जाय कि हर पंचायत में आर0आर0एफ0 एजेंसी का चयन जितनी जल्दी कर के हो सके एक महीने के अन्दर उसको कर लिया जाय ताकि हमलोग रेवन्यू सिस्टम को ठीक कर सकें । दूसरा मैं यह देखता हूँ कि सरकार की नीति है कि छतीस घंटे में बंद ट्रांसफर्मर को आपको रिप्लेस कर देना है । अब समस्या ऐसी है कि आज किसी गांव का ट्रांसफर्मर जला तो एक दिन बाद सूचना हमलोग तक पहुंचती है या दो दिन बात पहुंचती है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हर अनुमंडल में एक डेडीकेटेड वाहन केवल बंद ट्रांसफर्मर को चेंज करने के लिए हो, ऐसी व्यवस्था की जाय ताकि जैसे ही सूचना आये वह डेडीकेटेड व्हेकिल एक्टिव हो जाये। अब गांव वाले कोई ट्रेक्टर व्यवस्था करते हैं तो वहां से ट्रांसफर्मर लाने डिवीजनल स्टोर में या फिर आपके जिले के स्टोर या फिर आपके सर्किल के स्टोर में जाते हैं तो हमारा सुझाव है कि एक गाड़ी होनी चाहिए बिजली विभाग के पास में जिसमें एक-दो टेक्निशियन भी होनी चाहिए जो डेडीकेटेड वाहन केवल बंद ट्रांसफर्मर को चेंज करने के लिए हो । महोदय, सबसे बड़ी समस्या है वैसे बंद ट्रांसफर्मर में जो प्रोजेक्ट वाले ट्रांसफर्मर लगा रहे हैं, 16 के0भी0ए0 का ट्रांसफर्मर, 25 के0भी0ए0 का ट्रांसफर्मर रिप्लेस कर रहे हैं या कोई नये गांव जहां विद्युतीकरण हुआ है, वहां ट्रांसफर्मर उन्होंने लगा दिया बिजली चालू हो गयी और हैंड ओवर नहीं हुई सप्लाई विभाग को, अगर वह ट्रांसफर्मर जल जा रहा है तो महोदय उसको बदलने के लिए नौ नतीजा करना पड़ता है फिर भी वह ट्रांसफर्मर बदला नहीं जा सकता है। सप्लाई डिपार्टमेंट बोलता है कि वह प्रोजेक्ट का है और प्रोजेक्ट की जो स्थिति है जो दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना में ठीकेदार काम कर रहे हैं, उनकी जो स्थिति है, उनसे तो कोई उम्मीद करना ही बेमानी है । महोदय, शहरी क्षेत्रों में हर जगह मैं देखता हूं कि आपलोग ने जो सोलर स्ट्रीट लाईट और इसके बाद एल0ई0डी0 स्ट्रीट

लाईट लगा रहे हैं । मेरा ये कहना है कि हमलोग बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हमारे विधान-सभा क्षेत्र में कोई एक नगर पंचायत भी नहीं है लेकिन जो प्रखंड मुख्यालय हमारे दो हैं और दोनों में काफी बड़े बड़े बाजार है, गोह बाजार, हसपुरा बाजार। मेरा ये कहना है कि जो स्ट्रीट लाईट आप लगा रहे हैं...

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) एक मिनट और समय है ।

श्री मनोज कुमार : एक दो मिनट और समय लूंगा और मैं अपनी बात को समाप्त कर दूंगा तो वह स्ट्रीट लाईट का जो प्रोविजन है वह ग्रामीण क्षेत्रों के प्रखंड मुख्यालयों में भी किया जाय और शहरी क्षेत्र के साथ-साथ उसे भी जोड़ा जाय । महोदय, और भी जो निविदा की शर्त्त दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना में 12 फेज का जो काम है, मुझे इस निविदा की शर्त्त में जो कमी लगती है उसे मैं आज बतलाना चाहता हूँ । इस निविदा में जो पेमेंट का प्रोविजन किया गया है वह चार आईटम में 50 प्रतिशत पेमेंट का प्रोविजन है- ट्रांसफर्मर में,पावर में, कंडक्टर में और आपका जो बी0पी0एल0 किट है उसमें मीटर बगैरह है और बाकी कार्यों का पेमेंट काम पूरा होने के बाद में है जबकि इस दौर में पूरे देश में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य जोरों पर है तो हमें बहुत अच्छे ठीकेदार नहीं मिल सकते हैं तो हमें जो उपलब्ध कान्ट्रेक्टर हैं उन्हें सपोर्ट कर के काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा । विभाग ने अच्छी पहल भी की है, कुल लोगों को टाई-अप कराया है लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है पेमेंट टर्म्स में भी कुछ उदार होना पड़ेगा तब हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर पायेंगे और इस ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, सचिव महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि मैंने एक साल पहले इसी समय में मैंने कुछ गांव के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट कराया था कि अगर बरसात के पहले इन गांव तक बिजली नहीं पहुंचायी जायेगी तो समस्याएं उस गांव की बनी की बनी रहेगी लेकिन महोदय आज भी वैसी ही स्थिति है । मैं परेशान हो गया हूँ ,ये कॉन्ट्रेक्टर के प्रोजेक्ट मैनेजर को चेज करने में ..

सभापति(श्री नरेन्द्र नारायण यादव) अब आप अपना आसन ग्रहण करें ।

श्री मनोज कुमार : तो सभापति महोदय, मेरा यही आग्रह होगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने कटौती प्रस्ताव में कि इसकी राशि 10 रू0 घटायी जाय। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्रीमती बेबी कुमारी: सभापति महोदय, सरकार द्वारा उर्जा विभाग के प्रस्तुत बजट पर लाये गये कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये मैं खड़ी हुई हूं। महोदय, बिजली विभाग को अगर यह कहा जाय कि भ्रष्टाचार की जननी है तो यह कहीं से गलत नहीं होगा । बिजली विभाग आज बिचौलियों के हाथों में चला गया है । मीटर रीडिंग बिचौलियों के द्वारा होती है, बिलिंग बिचौलियों के द्वारा होती है । जानबूझ कर गलत बिल दे दिया जाता है और फिर सुधार के नाम पर दौड़ाया जाता है । हमारे

मुजफ्फरपुर में तो फ्रेंचाईजी का आतंक हो गया है । शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उसी एजेंसी से बात करने के लिये कहा जाता है । महोदय, केबल से बिजली सप्लाई करने का निर्णय लिया गया और पिछले ढाई–तीन वर्षों से पोल पर केबल ला कर छोड़ दिया गया है । उसकी लाईफ समाप्त होती जा रही है लेकिन उसे चालू नहीं किया गया है । इससे एक तरफ जहां दुर्घटनाएं घट रही हैं वहीं बिजली चोरी भी चरम पर है। महोदय, बिजली विभाग में नियमित पर्यवेक्षण नहीं है जो ट्रांसफार्मर दस–बीस वर्ष पहले लगे वहां स्वतः सर्वेक्षण कर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर नहीं लगाया जा रहा है बल्कि मुहल्ले या गांव के लोग चंदा कर जब चढ़ावा देंगे तब अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगता है । ट्रांसफार्मरों के रख रखाव की जिम्मेवारी विद्युत कनीय अभियंता की होती है परंतु शायद ही कोई कनीय अभियंता किसी ट्रांसफार्मर को देखने जाता हो । ट्रांसफार्मर के लिये मापदंड निर्धारित हैं, उनमें लाईटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग, ए0बी0 स्विच होना चाहिये परंतु किसी भी ट्रांसफार्मर, चाहे वह नया हो या पुराना ये सब चीजें नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के बसावट टोले, सड़क के उपर से 11000 वोल्ट का तार गुजरता है, जिससे खतरा उत्पन्न होता रहता है। वैसे खतरनाक स्थल को चिन्हित कर 11000 के तार को बसावट टोले से हटाकर नए मार्ग के विकल्प पर सरकार का विचार करनी चाहिए। जिला मुजफ्फरपुर में विद्युत विभाग का कार्य एस्सेल कंपनी के अधीन है, मैं कहना चाहती हूँ कि जिले के सभी माननीय विधायकगण पंचायती राज के प्रमुखगण इनके कार्य संचालन, कार्य शैली पर सरकार मंतव्य लेने का विचार करना चाहेगी एवं प्राप्त मंतव्य पर निर्णय लेकर मुजफ्फरपुर जिला को एस्सेल से मुक्त करने पर विचार करना चाहेगी। बोचहाँ के लोहसरी में किसानों के लिए सिंचाई सुविधा हेतु पावरग्रिड सब स्टेशन की स्वीकृति दी गई लेकिन जमीन अधिग्रहण के कारण कार्य अभी तक नहीं हो पाई है। निजी व्यक्ति जमीन देने के लिए तैयार है सरकार को अविलंब बनानी चाहिए।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) अब आपका समय हो गया ।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदय, एक मिनट और दिया जाय हमारे क्षेत्र की समस्या है। आज अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का बजट भी पारित होना है इसलिये मैं एक बिंदु की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं । अनुसूचित

जाति के लोग बड़े पैमाने पर राशन कार्ड, वृद्धावस्था, विधवा पेंशन से वंचित है। इनके टोले को मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए संपर्क सड़क नहीं है। सभी तरह की योजनाएं सरकार द्वारा संचालित किए जाने के बाद भी मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं हो पाना खेदजनक है। सभापति महोदय, एक मिनट और देना चाहिए चूंकि मुझे क्योंकि निर्दलीय चार विधायक का चार मिनट होना चाहिए।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) अब आपका समय समाप्त हो गया,आसन ग्रहण करें।

श्रीमती बेबी कुमारीः अनुसूचित जाति में कमजोर वर्ग को चिन्हित कर महादलित बनाया गया जिसमें बड़ी समस्याएं हैं । सभापति महोदय, अनु0 जाति के लोग बड़े पैमाने पर राशन कार्ड वृद्धावस्था और विधवा पेंशन से वंचित है।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) अब आप अपना आसन ग्रहण करें।

श्रीमती बेबी कुमारीः सभापति जी, मुझे मौका दिये इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ।

टर्न–24/मधुप/21.03.2017

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य श्री सत्यदेव राम जी । दो मिनट आपका समय है ।

श्री सत्यदेव राम : सभापति महोदय, आज उर्जा विभाग पर बोलने का मुझे अवसर मिला है, इसके लिये धन्यवाद है । महोदय, वैसे तो सभी विभाग महत्वपूर्ण हैं लेकिन उर्जा विभाग अति महत्वपूर्ण है । आप देखेंगे कि सुखमय जीवन की जितनी सुविधाएँ हैं वह बिजली से, उर्जा से प्राप्त होती हैं । यही कारण है कि लोग गाँव छोड़कर शहर में आते हैं तो सरकार को इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीरता से विचार करना होगा । मैं कोई शिकायत, कोई आलोचना करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूँ ।

महोदय, मैं इसकी महत्ता को सिर्फ इसलिये बता रहा हूँ चूंकि मैंने देखा है रिपोर्ट में कि शहर को 20–22 घंटे विद्युत आपूर्ति होती है और देहात को 15–16 घंटे, ऐसा क्यों हुआ है महोदय ? तब तो आप शहर को अलग से देखते हैं और देहात को अलग से देखते हैं । इस प्रबंधकीय व्यवस्था पर हमारी कड़ी आपत्ति है । चूंकि गाँवों में +2 के स्कूल चल रहे हैं, आप दावा करते हैं कि हम कम्प्यूटराइज कर रहे हैं, बच्चों को कम्प्यूटर सिखा रहे हैं । उन विद्यालयों में आज गरीबों के ही एकमात्र बच्चे हैं और वहाँ बिजली नदारद है । कैसे वे कम्प्यूटर सीखेंगे, कैसे कम्प्यूटर की पढ़ाई होगी ? यह दोहरी नीति गलत है । मैं इसका विरोध करता हूँ ।

साथ-ही, मैं कहना चाहता हूँ चूंकि उसकी कुछ मूल चीजों को ही मैं रखना चाहता हूँ कि पूर्व में लोगों ने कनेक्शन ले लिया, कंज्यूमर बन गये, उपभोक्ता बन गये, आंधी-तूफान से तार टूट गया है, पोल गिर गया है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आपका समय हो गया है माननीय सदस्य ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, दो मिनट । ट्रांसफर्मर जल गया है, विद्युत आपूर्त्ति बंद है और आपका विभाग के द्वारा बिल जारी है । बिल आप जारी रखे हैं और उसको आपूर्त्ति करते जा रहे हैं, विभाग को इसपर कोई ध्यान नहीं रहता है । मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विद्युत आपूर्त्ति के अभाव में लघु सिंचाई योजना के तहत सारे नलकूप, ट्यूबवेल आज बन्द हैं और सिंचाई क्षमता घट गई है, किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक मिनट । हम ज्यादा समय नहीं लेंगे । किसानों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, ट्यूबवेल सारा बन्द है, पूरे बिहार में । रिपोर्ट आया था लेकिन मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूँ कि सीवान में आपने 98 ट्यूबवेल दिया है, उसमें से एक भी नहीं चल रहा है, विशेष त्रुटियों के कारण बंद हैं ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : अब आप अपना भाषण समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री शम्भु नाथ यादव जी ।

श्री सत्यदेव राम : महोदय, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ । सुन लिया जाय ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आप कृपया आसन ग्रहण करें । आप अपना भाषण शुरू करें माननीय सदस्य श्री शम्भु नाथ यादव जी ।

श्री सत्यदेव राम : एक बात और सुन लिया जाय, काफी महत्वपूर्ण है ।

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : आप माननीय मंत्री जी को अपनी समस्या लिखकर दे दीजियेगा । श्री शम्भु नाथ यादव ।

श्री शम्भु नाथ यादव : महोदय, आज के डिबेट में बोलने का मौका दिया गया है, इसके लिये मैं सदन का आभार व्यक्त करता हूँ ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री नरेन्द्र नारायण यादव) : माननीय सदस्य सत्यदेव राम जी, आप बैठ जायं । उनको बोलने दिया जाय ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : श्री शम्भु नाथ यादव जी, आप जारी रखिये । श्री सत्यदेव राम जी, आपका समय दो मिनट था और आपको तीन मिनट से बैठने के लिये कहा जा रहा है । श्री शम्भु नाथ यादव जी ।

श्री शम्भु नाथ यादव : महोदय, मैं अपने विपक्ष के नेता प्रेम बाबू को पूरे टीम के साथ बधाई देता हूँ, जो हमलोगों को सावधान करने के लिये हमेशा तत्पर रहते हैं । इसके लिये मैं इनके पूरे टीम को बधाई देता हूँ ।

महोदय, इस सदन में हमारे माननीय लोगों का कहना है कि कहीं बिजली का काम नहीं हुआ है, मैं मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ, अपने उप मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ । हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री महोदय बोलते हैं कि जनता जीता कर भेजी है भोग लगाने के लिये नहीं, काम करने के लिये । मैं अपने विरोधी दल के नेता को बताना चाहता हूँ अपने माननीय लोगों को कि दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है, या तो आप पेपर में फोटो खिंचवायेंगे या काम करवा कर दिखायेंगे ।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बिहार में विद्युत के मामले में काम हो रहा है, पूरे हिन्दुस्तान में कहीं हमको नहीं लगता है कि इस तरह का काम हो रहा होगा । मैं इस सदन में बैठे ऊर्जा मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ और बिजली विभाग के पूरे परिवार को सी0एम0डी0 साहब के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बधाई देता हूँ । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि बक्सर जिला में ब्रह्मपुर विधान सभा क्षेत्र में यदि कोई दिग्भ्रमित हैं कि बिजली का काम नहीं हुआ है तो हम अपना गाड़ी भाड़ा लगाकर ले चलते हैं, दिखा देते हैं कि बिजली के क्षेत्र में कैसे काम हुआ है। (व्यवधान)

महोदय, मैं अपने यहाँ के काम की बात कर रहा हूँ । हमारे यहाँ जितने पंचायत में पूर्ण रूप से बिजली का काम हो गया है, मैं बताना चाहता हूँ - चक्की पंचायत, जवही पंचायत, चाना पंचायत, अरंग पंचायत, खड़हाटाड़ पंचायत, सैहार पंचायत, ऐकौना पंचायत, काजीपुर पंचायत, केशोपुर पंचायत, मानीकपुर पंचायत, नियाजीपुर पंचायत, राजापुर पंचायत, राजपुर पंचायत, छपरा पंचायत, सुकरटोला पंचायत, भदवर पंचायत, मनकी पंचायत, धरौली पंचायत, बराढी पंचायत, भादा भंशारी पंचायत, मझवारी पंचायत ।

महोदय, मैं पूरे बक्सर जिला की बात करता हूँ, इसमें मेरा भी सहयोग है और हमने इस काम को सरकार की योजना को धरातल पर लाने का काम साथ में रहकर कराया है । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मपुर में एक साल में 250 कि0मी0 3 के0वी0ए0 कवर-वायर का काम करवाये हैं । यह बिजली का, हमारी सरकार की देन है। एक साल में पूरे ब्रह्मपुर विधान सभा क्षेत्र में 300 नया ट्रांसफर्मर लगवाने का काम किया है । महोदय, ब्रह्मपुर विधान सभा क्षेत्र में 11 हजार के0वी0ए0 लाईन का काम 100 कि0मी0 एक साल में कराने का काम किया गया है ।

...क्रमशः ...

टर्न–25/आजाद/21.03.2017

..... क्रमशः .....

श्री शम्भुनाथ यादव : हमारे यहां महोदय, 33हजार के0वी0ए0 का काम, हमारे यहां चक्की प्रखंड में अपना 2 बीघा जमीन, अपना 75 डिसमिल जमीन दान देकर के और 12 कि0मी0.....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब एक मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री शम्भुनाथ यादव : महोदय, अभी कहां समय हुआ है सर ।

अध्यक्ष : एक मिनट में ।

श्री शम्भुनाथ यादव : दो मिनट सर । महोदय, हमारे यहां मात्र 75 दिनों में 12 कि0मी0 33000 के0वी0ए0 का काम करके पी0एस0एस0 को चालू कराने का काम किया गया है ।

मैं अब अपने माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय को बताना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि पावरग्रीड के लिए महोदय 7 एकड़ जमीन उपलब्ध है, दान देने के लिए हम तैयार हैं, यदि आपका कृपा होगा तो उस दियारा में उजाला हो जायेगा और आपका भी नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जायेगा, मैं यह आपसे मांग करता हूँ ।

महोदय, हमारे जिला के कलक्टर हमारी सरकार के प्रति भूखे रहकर के और इस चीज का एलान किया कि जब तक हम स्वच्छता अभियान पूरा नहीं कर लेते हैं, तब तक फलाहार रहकर इस काम को पूरा करेंगे । हमारे जिला के डी0डी0सी0 साहेब टोपी पहने और प्रतिज्ञा किया कि जब तक स्वच्छता अभियान खतम नहीं होता है, तब तक हम अपना टोपी नहीं उतरोंगे महोदय । उस जिला में 10 तारीख को 5.20 बजे असामाजिक तत्वों ने बिजली के ऑफिस में घुसकर के सारे कर्मचारियों को मारकर गर्दा करने का काम किया । महोदय, उसका सी0डी0 भी है और इस तरह से बुरी हालत हुआ, इतना देर तक नौटंकी चलता रहा कि वे लोग अपने बचाव के लिए पुलिस बुलाया, प्रशासन और थाना के लोग आये, डी0एस0पी0 भी आये, उसके बाद भी लोग दौड़ा–दौड़ा कर मारते रहे और हमारे जिला के .....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री शम्भुनाथ यादव : वहां पर लोग रोड जाम कर रहे हैं और लग रहा है कि बहुत गुनाह कर दिया है । महोदय, ...

अध्यक्ष : ठीक है । आपने सरकार के साथ–साथ अपनी भी अच्छी उपलब्धि गिनायी है, इसलिए अब आप समाप्त करें ।

श्री शम्भुनाथ यादव : महोदय, मैं मांग करता हूँ इस सदन से .....

अध्यक्ष : अब आप बैठ जाईए । माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र कुमार सिंह ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : अध्यक्ष महोदय, 12 वर्षों के बाद आज बड़ा अच्छा महसूस हुआ इस हाऊस में कि हमारे अरूण बाबू के द्वारा जो कटौती प्रस्ताव आया, उनके मन

में सवाल उठ रहा है कि हम पार्टी के फेरा में फंसकर कटौती प्रस्ताव दे दिये, वे मुस्कुरा भी रहे हैं, चूँकि मैंने जो अनुभव किया बिहार की राजनीति में .....

श्री अरूण कुमार सिन्हा : महोदय, वे पूर्ण असत्य बात कह रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : महोदय, वे मुस्कुरा रहे हैं । वे इसलिए मुस्कुरा रहे हैं ....

अध्यक्ष : वे आपके वक्तत्य की नहीं, वे आपके दिल की बात कह रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : बिहार की राजनीति एवं सामाजिक परिवर्तन में आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमने जो अनुभव किया, वे नेता कम, एक सामाजिक जीवन जीने में अधिक विश्वास करते हैं । बिजली के सवाल पर पूरे बिहार में हाहाकार था । इस देश में प्रथम नेता के रूप में उन्होंने कहा कि मेरे पुतला जलाने से यदि बिजली आ जाय तो मैं पुआल भेज देता हूँ, पूरा पुतला जलाईए । उन्होंने कहा कि 2015 के चुनाव में हम तब तक नहीं जायेंगे, जब तक बिजली की व्यवस्था में सुधार नहीं करते हैं । हमारे विपक्ष के भाई कहने लगे कि उन्होंने कहा कि बिजली सब जगह नहीं पहुँचाऊंगा, तब तक वोट मांगने नहीं जाऊँगा । भईया, इसपर विचार कीजिए, उनके भाषा को ईमानदारी से अध्ययन करने का प्रयास कीजिए और आज मेरा घर केशावे पंचायत में पड़ता है । इस देश के हम अवतारित पुरूष आये बेगूसराय जिला में 2015 में, संयोग से वहां का लीडर के द्वारा मंच का मुँह पश्चिम की तरफ बना दिया, लेकिन पुनः उस मंच को पूरब मुँह किया गया । पश्चिम मुँह का मंच रह जाता तो मेरे छत पर भी लोग बैठे होते और कहीं मेरा घर भी नहीं गिर जाता । उन्होंने पूछा कि बिजली आयी, बिजली आयी, बिजली आयी, आयी,आयी करते रह गये और उस हवाईअड्डे से लाखों की संख्या में लोगों ने आवाज दी कि बिजली आयी और जिसका रिजल्ट बिहार की जनता ने देने का कार्य किया ।

मेरा क्षेत्र मटिहानी विधान-सभा है । तकनीकी और मानवीय भूल के कारण बिजली विभाग में 2-3 कठिनाईयां हैं । एक कठिनाई है और हम आग्रह करेंगे आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहेंगे कि हमारे क्षेत्र बेगूसराय में बिजली झोपड़पट्टी तक पहुँचा है । सामो प्रखंड तीन तरफ से गंगा से घिरा हुआ है, माँ गंगा के गोद में है और 22 घंटा बिजली सामो प्रखंड में है और एक-एक झोपड़पट्टी में बिजली पहुँची है, उसमें एक कमी है । मैं आग्रह करूँगा कि कुछ जगहों पर बांस-बल्ला के सहारे भी लोग बिजली का उपयोग कर रहे हैं, जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है । हम आग्रह करेंगे सरकार से कि इसको प्राथमिकता में रखनी चाहिए कि बिजली जो कंज्यूम कर रहे है, यदि बिहार में कहीं बांस-बल्ला के सहारे आपका बिजली जा रही है तो पहले प्राथमिकता तय करके बांस-बल्ला से तार को हटाने का प्रयास होनी चाहिए ।

दूसरी कठिनाई है कि बिजली बिल में मानवीय भूल के कारण बिजली बिल का सिस्टम सही नहीं हो पा रहा है । जिस कारण रीडिंग और बिजली का जो बिलिंग

होता है, उसमें डिफरेंस होता हे, जिस कारण हमारे ग्रामीण क्षेत्र के 80 प्रतिशत लोग अभी भी बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पिछड़े हुये हैं । चूँकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो खेत-खलिहान में हमारे बच्चे हैं, उनको हम पहले विद्यालय लाने का कार्य करेंगे, जब हम बच्चों को विद्यालय लाने में सफल हो जायेंगे, तब वहां पर गुणवत्तायुक्त शिक्षा देने का सार्थक प्रयास करेंगे । उस ओर बिहार सरकार का कदम अब तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है । इसलिए हम चाहेंगे कि जो बिजली के क्षेत्र में बड़ा बेहतर प्रयास हुआ है और देश और बिहार की चर्चा करना बेईमानी होगा । क्योंकि बिहार का नेतृत्व वर्ग अपने आपको देश के अवतारित पुरूष कहते हैं, हम बड़ा खराब शब्द है, अहंकार है तो कम से कम महागठबंधन के जो नेता है आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके कार्य करने का जो शैली है, उनका जो विजन है, उनका जो करनी और कथनी है, उनके चरित्र को अपने जीवन में अंश मात्र यदि उतार लेने का कार्य करें बिहार के धरती पर तो हमें लगता है कि बिहार में सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना हो जायेगी । आज मैं देखा अखबार में, टेलीविजन में आ रहा है, इतिहास के पन्ने में बापू के चरित्र को पढ़ने का मौका लगा, बापू ने कहा कि हिन्दुस्तान की आत्मा गांवों में बसती है, झोपड़पट्टी में बसती है, खेत-खलिहान में बसती है और इस देश के हम,

महोदय, आपने तो समय बताया नहीं कि हमें कितना मिनट बोलना है और हमें घड़ी देखने के लिए कह रहे हैं । इसलिए अध्यक्ष जी, आपकी कृपा होनी चाहिए....

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका बोलना तो जरूरी है ही लेकिन सरकार का भी विस्तार से उत्तर ज्यादा आवश्यक है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : महोदय, हम इसके लिए तैयार हैं । आपका आदेश होगा, एक सेकेंड में बैठ जायेंगे .....

अध्यक्ष : अब एक मिनट में आप समाप्त कीजिए ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : चूँकि हम जिस विद्यालय के छात्र रहे हैं, हमें पता है कि घड़ी का इशारा है बैठ जाओ ।

टर्न-26/अंजनी/दि021.03.2017

अध्यक्ष : एक मिनट है आपके पास ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमने अनुरोध किया, जो हम कह रहे हैं, जो मैं इस देश को बुलेट ट्रेन पर चढ़ा दूंगा । हम कह रहे हैं कि मैं अच्छे दिन लाने जा रहा हूँ, आज इस देश में तीन वर्षों का शासनकाल गवाह है कि जो जानवर की तरह रेलगाडी में लोग ठूंसे जा रहे हैं और 48-48 घंटा ट्रेन लेट चल रही है और बिहार की धरती पर ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर यदि पूछा जाय तो बापू के सपने को बिहार

की धरती पर झोपड़पट्टी और खेत-खलिहान में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने का यदि कार्य किया गया तो उसके लिए बिहार की धरती के मिट्टी-मिट्टी से आवाज आती है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बापू के सपने को झोपड़पट्टी में पहुंचाने का काम किया अध्यक्ष महोदय । हमारे मंत्री जी आग्रह करेंगे ही और आज मैं बड़ा राहत महसूस किया कि विपक्ष की तरफ से कोई तीखा बहस बिजली विभाग पर नहीं किया गया । चूंकि उनके घर में भी 18 से 22 घंटा बिजली जल रही है तो उनको लगा कि जिस चीज का, जिस वस्तु का हम सदुपयोग कर रहे हैं उसपर तीखा बहस करने की कोई आवश्यकता उन्होंनें महसूस नहीं किया । मुझे लगता है कि आदरणीय विपक्ष के नेता श्री प्रेम जी जरूर अंतिम तक सरकार का उत्तर सुनकर ही जायेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद । जय हिन्द, जय भारत ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय मंत्री उर्जा विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, लगभग 18 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव सदन में आपके माध्यम से अपनी जानकारी के अनुरूप रखने का प्रयास किया । मैं मनोज जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ और मैं लंबे समय से, 1990 से लगातार इस सदन का सदस्य हूँ, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ । मनोज जी पहली बार एम0एल0ए0 बने और जितना शानदार तरीके से विपक्ष में रहकर भी उन्होंने अपनी बातों को रखा, उन दिक्कतों को रखा, जानकारियों के आधार पर पढ़-लिखकर के, यह प्रशंसा योग्य बातें हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्यों को इंक्लूडिंग प्रेम बाबू को भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, सीखनी चाहिए, यह मेरा आग्रह होगा । जो आदमी अच्छा करेगा, मैं उनकी अच्छी प्रशंसा करूँगा क्योंकि हल्ला और हसरत लोकतंत्र में विपक्ष का धर्म नहीं है । लिखा हुआ है कि विपक्ष भी सरकार का ही अंग हुआ करता है । आप के ही आदरणीय नेता प्रधानमंत्री जी ने अभी फिलहाल कहा है कि बहुमत से नहीं, सबको मिलाकर शासन चलता है । अच्छी बात है कि उनको भी तीन सालों के बाद अनुभव हुआ । इस लोकतांत्रिक देश में, इस देश की खासियत है, इसकी संस्कृति की यह विशेषता है । हजारों साल पुरातन देश है महोदय, लोकतंत्र, यहीं बुद्ध पैदा हुए थे और बुद्ध ने मध्यम मार्ग, अतिउग्रवाद, कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि विपक्ष जैसे लगता है कि युद्ध करने पर आतुर है, यह ठीक नहीं है । आप भी जनता से चुनकर आये हैं, जन-प्रतिनिधि हैं.....

अध्यक्ष : आज तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि बिजली से ही करेंट भी लगता है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप साथ में रहे हैं, हमलोग भी कभी-कभी उत्तेजित हो जाते हैं लेकिन माननीय मुख्यमंत्री को कभी आपने शालिनता, गंभीरता को तिलांजलि देते हुए देखा है, यह लोकतंत्र के लिए अदभुत शैली

है । एक बड़ी बात है, एक महान परम्परा का एक शानदार उदाहरण है । इसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए । महोदय, मैं मनोज ती की बात से ही शुरू करता हूँ । ठीक ही कहा उन्होंने कि उर्जा के क्षेत्र में पांच महत्वपूर्ण अवयव होते हैं । नम्बर-1 जेनरेशन, नम्बर-2 ट्रांसमीशन, नम्बर-3 डिस्ट्रीव्यूशन, जिस सब-स्टेशन का जिक्र कर रहे थे, वह डिस्ट्रीव्यूशन होता है, ट्रांसमीशन सिस्टम का पार्ट होता है, उसका हिस्सा नहीं होता है । फिर कलेक्शन, एगेन कलेक्सन, ये पांचों में कहीं अगर सिक्वेंस में गड़बड़ी हुई तो उससे परेशानी बढ़ती है । महोदय, माननीय सदस्यों ने उन चीजों का जिक्र किया लेकिन कभी हमलोगों ने नहीं कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने, कभी यह दावा नहीं किया कि सब कुछ ठीक हो गया । कभी हमने नहीं कहा कि हर घर को बिजली मिल गयी है । इरादा तो है, घोषणा तो है कि दो साल में हर घर को बिजली देंगे । यह बहुत आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है, हर घर को बिजली देना । अन्य कोई भी सेक्टर जो है, अगर आप एक सड़क बना दें तो दस-पन्द्रह पंचायत को 15-20 किलोमीटर सड़क में कवरेज हो जाता है लेकिन हर घर को बिजली देना और वह भी बिहार जैसे राज्यों में, जहां का पोपुलेशन डेनसिटी हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादे है और आज तो संयुक्त परिवार की कोई शैली है नहीं । आज तो माइक्रो फेमिली का विस्तार हो रहा है, मां-बाप से भी बेटे अलग हो जाते हैं, ज्योंहि वे कमाने-धमाने लगते हैं तो हर को अलग-अलग कनेक्शन चाहिए, इसलिए यह आसान काम नहीं है । अब महोदय, कहां से हम चले थे और आज कहां हैं, ऐसा नहीं है । महोदय, झारखंड से अलग हुआ था बिहार, 2005 में हमलोग चले थे जो उप-केन्द्र है, जो ग्रिड है, जिसको आप ट्रांसमीशन सिस्टम कहें मनोज जी तो उसकी संख्या थी 45 और आज मार्च, 2017 में 106 पर खड़े हैं और अगले साल वर्ष 2018 में 152 पर रहेंगे । साथ ही, सब-स्टेशन, जो घर को बिजली देता है 11 हजार लाईन से, उसकी संख्या थी उस समय 268 और आज है 674 और आगे होगा 792 । यह मैंने ट्रांसमीशन, डिस्ट्रीव्यूशन का सिस्टम बताया । अब जेनरेशन में 2005 में अपना जेनरेशन जीरो था, अब अपने का कन्सेप्ट भी बेकार चीज है, उसपर मैं बाद में बोलूंगा । मार्च, 2017 में आज 525 मेगावाट बिहार में जो बिजली पैदा हो रही है, जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, वह मिल रहा है और मार्च, 2018 में 2650 मेगावाट में जायेंगे, वह नवीनगर का है, बरौनी भी अपना आ जायेगा, अन्य चीजें भी । एक चीज बराबर लोग बोलते हैं कि भारत सरकार की बिजली है, प्रेम बाबू भी कभी-कभी बोलते हैं तो भारत की सरकार आपकी है क्या ? भारत की सरकार हमारी भी है, देश की भी है और बिहार भी उसका हिस्सा है । ऐसा नहीं कि भारत की सरकार केवल, मैं आपको बताऊं, मिर्ची न लगे, भागियेगा नहीं, मैं इस बिहार राज्य की धरती पर शिंदे साहेब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि आज जो कुछ भी उपलब्ध हो रहा है, जितनी चीजों में

उस आदमी की सबसे बड़ी देनदारी रही है, उससे इन्कार नहीं किया जा सकता है । आप तीन साल में एक मेगावाट भी बिजली पैदा नहीं कर पाये बल्कि जो समझौते हुए थे, जिसका जिक्र प्रह्लाद जी कर रहे थे । क्या हुआ ? घोषणा हुई थी चुनाव के पहले चौसा, कजरा, पीरपैंती उन दोनों को भी छोड़ दीजिए । अल्ट्रा मेगा का क्या हुआ ? अभी तक तो कैबिनेट डिसीजन नहीं हो पाया है । बी0आर0जी0एफ0 का मैं जिक्र करूँगा, भारत सरकार की उस समय की जो योजना थी राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, 90 प्रतिशत् ग्रामीण विद्युतीकरण में जिसमें सब-स्टेशन का भी निर्माण कार्य संलग्न था । 90 प्रतिशत भारत सरकार ने की थी और 10 प्रतिशत राज्य सरकार का लगता था ।

क्रमशः.....

टर्न-27/शंभु/21.03.17

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : क्रमशः.....और ये योजना आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री, जो भारत सरकार एन0डी0ए0 में मंत्री थे वाजपेयी जी ने शुरू किया था दस वर्षीय पंचवर्षीय योजना में और अभी 60/40 कर दिया, वाजपेयी जी के सपनों को पूरा नहीं करके उनको चकनाचूर कर दिया 40 परसेंट और कहते हैं भारत सरकार की बिजली, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युीकरण योजना का टेंडर होकर अभी काम ही प्रारंभ हुआ है। इसलिए ऐसा मत कहियेगा और मैं यह स्वीकारता हूँ, मैं भी कह रहा हूँ सरकार लगातार की क्रिया होती है। इसीलिए मैंने जिक्र किया कि भारत सरकार केवल आप ही की नहीं है- सरकार, सरकार हुआ करती है, विपक्ष का भी हिस्सा है और रूलिंग पार्टी की जिम्मेवारी है। यही लोकतंत्र की परिभाषाएं हैं।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय.....व्यवधान।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : कोई हर्ज नहीं है। मेघा नहीं मेगा।

अध्यक्ष : माननीय नेता प्रतिपक्ष, कम से कम सदन को तो सही ढंग से- आपने मंत्री जी से इजाजत ले ली और मंत्री जी ने इजाजत दे दी, आसन की भी भूमिका होती है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप पहले आसन से इजाजत लीजिए न, आप मंत्री जी से इजाजत लेते हैं और वे भी दे देते हैं।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के बारे में आप चर्चा कर रहे थे कि भारत सरकार की योजना है- 4000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। राज्य सरकार को जमीन देना है क्या राज्य सरकार जमीन चिन्हित करके दे दी है, बताइये।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, यह भारत सरकार की योजना है उसमें ज्यादा क्रेडिट मत लीजिए। मैं फिर शिन्दे साहब के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहूंगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी के यहां उनका खाना हो रहा था और खाते वक्त भी मैं टेबुल पर कुछ

चर्चा कर रहा था तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि खाने के वक्त तो बंद रहिये। उस समय कहा कि हर बार मीटिंग में हमसे झगड़ा करते हैं। एक अल्ट्रा मेगा देंगे जिसमें 50 परसेंट होगा और उसी क्रम में 1320 मेगावाट का बाढ़ का भी उसी समय उन्होंने निर्णय करने का काम किया, जो बनकर तैयार हो गया और आधा उसमें से हमको आता है। इसमें है क्या महोदय, जमीन हमलोगों ने आइडेन्टीफाई कर लिया है- बीड होगा, प्राइवेट पार्टी आयेगी, कोयला का ब्लॉक भारत सरकार आइडेन्टीफाई करके देगी और बीडिंग में जो कंपनियां आयेगी वह पैसा लेकर के हम तैयार हैं। आप बीडिंग करवा दीजिए कैबिनेट का डिसिजन भी अभी तक नहीं हुआ है। यही स्थिति है अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट का और राज्य सरकार का 50 परसेंट उसमें हिस्सा है। इसीलिए गलतफहमी में मत रहिये, पावर प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं बनता है। भारत सरकार की बिजली- एन0टी0पी0सी0 भारत सरकार का आर्गेनाइजेशन जैसे लगता है कि अभी ही स्थापित हुआ है, एन0एच0पी0सी0 जैसे लगता है कि अभी ही स्थापित हुआ है। वह सब नवरत्न कंपनियों में वह कंपनी है और पावर ग्रीड कॉरपोरेशन भी पहले से स्थापित है। उसके इतिहास को पढ़ने की जरूरत है और भारत सरकार की कौन सी बिजली होती है महोदय ? कोयला किनका है। तब तो कहे झारखण्ड सरकार कि हमारा कोयला है, मध्य प्रदेश कहे हमारा कोयला है, बहुत राज्य में कोयला नहीं है, बिहार राज्य में कोयला नहीं है, नॉर्थ इस्टर्न के बहुत राज्यों में पावर हाऊस नहीं है और बिजली मुफ्त में नहीं मिलती! एन0टी0पी0सी0 के साथ करार है और हमको लेना है। बाजार में उससे सस्ती बिजली मिलती है, लेकिन चूंकि देश एक है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारी जवाबदेही है जो पैसे जाते हैं देश का पैसा है, राज्य का पैसा देश के हिस्से में जा रहा है, यह तो पहले से अवधारणा है। हां, अगर आप अमेरिकन थ्योरी पर चल रहे हैं, कैप्टलिस्ट थ्योरी पर कि सबकुछ को प्राइवेटाइजेशन करो- आज मैं चिंता करता हूँ इस सदन के माध्यम से महोदय और आरोप भी लगाता हूँ कि कोल इंडिया को खत्म करने जा रही है भारत सरकार की नीतियां जो एक बड़ा भारी चीज था। जब बैंक और कोल का नेशनलाइजेशन हुआ था तब हुआ था कि गरीबों का लाभ होगा उसमें गरीबों के लिए हितकारी चीजें होगी।

श्री प्रेम कुमार,ने0वि0द0 : महोदय.....

अध्यक्ष : मंत्री जी, आप जारी रखिये।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : और मेरी चिंता है, शंका है कि आनेवाले वक्त में रेल भी प्राइवेट में जायेगा और बिजली भी प्राइवेट में जायेगा, सड़क भी प्राइवेट सेक्टर में जाने को है। इसलिए महोदय, ये लोग गलतफहमी में है कि भारत सरकार की बिजली- भारत सरकार की बिजली का एक जिक्र मैं करना चाहूंगा कि एक बार गौर से सुनिये.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप ही इनकी सुनने लगते हैं।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, ये सुनने के काबिल हैं ही नहीं तो मैं क्या करूँ ? मैंने बार-बार कहा कि मनोज जी से सीखिये, लेकिन ये सीख नहीं सकते।

(इस अवसर पर भाजपा के सदस्यगण ने सदन से वॉक आउट किया।)

महोदय, अब मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि कांटी यूनिट-4 ये अप्रैल, 2017 में आ जायेगा, बरौनी युनिट-6 110 मेगावाट की और कांटी का 195 का मई, 2017 में आ जायेगा। बरौनी का दोनों यूनिट 8 और 9 नवम्बर, 2017 में आयेगा, नवीनगर की यूनिट 660 मेगावाट की दो- एक सितम्बर में और एक मार्च में आयेगा। अब महोदय, बराबर ये लोग कहेंगे कि भारत सरकार की बिजली, अब तो सुनकर हतप्रभ होना पड़ेगा, बार-बार हमलोगों ने उठाया इस देश में पांच रीजन में बंटा हुआ है बिजली और पांचों रीजन का अलग-अलग रेट है। हमलोग हैं इस्टर्न रीजन में और इस्टर्न रीजन में कौन-कौन राज्य है- बंगाल है, बिहार है, झारखण्ड है, सिक्किम है, उड़ीसा है और हाइयेस्ट रेट है इसमें- सबसे ज्यादा कोयला इसी रीजन में है और सबसे ज्यादा बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता है इसी राज्य को, अगर नेशनल टैरिफ हो जाय पूरे देश का रेल की तरह या टेली कम्युनिकेशन की तरह या अन्य जितने सिस्टम हैं एक रेट है। आप एक सौ कि0मी0 की यात्रा तमिलनाडु में करें या एक सौ कि0मी0 की यात्रा बिहार में करें या गौहाटी-असम में करें तो टिकट का दर सेम है। यहां वो नहीं है, अगर ये हो जाय तो 200 करोड़ रूपया बिहार सरकार को बचत होगी, बंगाल को बचत होगी, सभी राज्यों को बचत होगी। इतना बड़ा का अंतर है, लेकिन कहते हैं कि भारत सरकार की बिजली है। पैसा लगता है ज्यादा, रेट है ज्यादा और पूरा जो एलोकेशन है वह दे भी नहीं पाता, उसके एलोकेशन के बाद भी हमें बाजार से खरीदना पड़ता है फिर भी रोज भाषण देंगे- भारत सरकार की बिजली, भारत सरकार की बिजली। महोदय, अब दीन दयाल उपाध्याय विद्युतीकरण की योजना बड़ा जोरदार भाषण देते हैं। अब एक आंकड़ा मैं रखना चाहता हूँ- हां कुछ जिक्र मैं करना चाहता हूं महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य करने में 10-11 जिले में कार्रवाई की गयी है, सभी माननीय सदस्यों के साथ बैठक भी की गयी है और उसपर एक्शन लिये जा रहे हैं। अब दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कुल स्वीकृत राशि कितना है 5827.23 करोड़ केन्द्रांश 3496.33 करोड़ और राज्य का अंश 2330.90 करोड़। हम तो मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे एक दो बार बातचीत भी कर चुके हैं। दीन दयाल उपाध्याय मुख्यमंत्री ग्रामीण विद्युतीकरण योजना क्यों नहीं नाम हमलोग कर सकते हैं। मेरी यह मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ। हम जब इतना पैसा देते हैं तब केवल वही योजना क्यों होगी। हमारी योजना, हमारे राज्य का इतना पैसा लग रहा है हम क्यों उसका नामकरण करें। अब महोदय, एक बात का और मैं जिक्र करना चाहूंगा बी0आर0जी0एफ0- कितना दूं, कितना

दूं 1 लाख 25 हजार करोड़ और इसपर भी मैं आदरणीय मनमोहन सिंह जी और आदरणीय शिन्दे साहब का आभार प्रकट करना चाहूंगा। एक मीटिंग में मैंने कहा प्रधानमंत्री जी- प्रधानमंत्री जी भी आये थे- शिन्दे साहब ने कहा कि 20वीं सदी के अंत तक जिस आदमी को हम सभी माननीय मंत्री लोग सभी सहयोगी हैं, जिस आदमी को बिजली विभाग मिलता था तो उनके क्षेत्र के लोग मजाक में भी कहते थे कि काहे के लिए सड़ा हुआ विभाग लिये, इसमें क्या हमलोगों का प्रयोजन है ? इससे बढ़िया था एनीमल हस्बेंडरी ही ले लेते ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन आज 21वीं सदी के पहले पांच वर्ष के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री- शिन्दे साहब ने कहा जूते फेंके जाते हैं, पुतले जलते हैं, गालियां दी जाती है.....क्रमशः

टर्न-28/अशोक/21.03.2017

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : क्रमशः जैसे अभी जिक्र किया भाई नरेन्द्र जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा पुतला दहन से अगर बिजली मिल जाय तो हम भी पुआल देंगे जलावे, ये स्थितियां आई 21 वीं सदी में, उन्होंने उसी समय हमने कहा था जिक्र करते हुये कि आप फुड सिक्यूरीटी एक्ट माननीय प्रधान मंत्री जी लागू करने जा रहे हैं, स्वामीनाथन साहब बहुत बड़े एग्रीक्लचर के साईटिस्ट हैं, उनकी रिपोर्ट है कि जो फर्स्ट ग्रीन रेभ्यूलेशन हुआ वह इर्स्टन यू.पी. में और आन्ध्रा प्रदेश के कौस्टल ऐरिया में केवल गौसिप कर पाया, इस्टर्न रिजन अनकेयरर्ड रहा, सेकेन्ड ग्रीन रिभ्यूलेशन जो होगा वह बिहार निक्यूलियस होगा और इर्स्टन रिजन को आधार बनाना पड़ेगा ताकि वहां की केपेसिटी, तीन फसला जमीन जो हैं, वह अनाज की भरपाई देश के मामले में कर पाय । मेंने कहा आदरणीय प्रधान मंत्री जी केवल दस-बारह हजार करोड़ रूपया अगर आप हमें दे दें तो हम एग्रीक्लचर फीडर को अलग कर दें इनसे, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना हैं तो हमारा एग्रीक्लचर का प्रोडक्शन दुगना हो जायेंगा क्योंकि अभी लोग डिजल से हमारे किसान खेती करते हैं जो बहुत कास्टली हुआ करता है, बहुत महंगा होता है। बी.आर.जी.एफ. का प्रोग्रम लेकिन उसी मैंने एक जिक्र कर दिया था हमारे घर में लोग अंधरे में रहेंगे, खेत सूखा रहेगा तो हमको इतना बताने में कोई हर्ज नहीं हुआ कि यह ट्रांसमिशन लाईन अपना है और यह ट्रांसमिशन लाईन भारत सरकार का है I will not send the police यह मैंने कहा, जो प्लानिंग कमीशन के वाईस चैयरमैन थे उन्होंने कहा कि यह नेशनल थ्रेट है, मैंने कहा कि If you feel it is a national threat I am repeating it. Bihar is a part of the country or not प्रधानमंत्री जी ने कुछ इशारा किया खाते वक्त वे आ गये हम कहा कि हम

प्रोब्लम फेस कर रहे हैं तो 12 हजार करोड़ का प्लानिंग कमीशन ने पैसा दिया, अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने, गुरू गोविन्द सिंह के मामले में कुछ पैसे उधर भी हो गये लेकिन बिजली सेक्टर को मिला 9 हजार 210 करोड़, खर्चा कितना कर चुके हैं हमलोग, 5 हजार 749 करोड़, राशि अभी तक कितनी मिली है? 13-14 सौ करोड़, वायदा तो था कि इतना दू, कितना दूं, अब नतीजा है कि हमलोग कर्ज लेकर खर्च कर रहें हैं महोदय । यह तो हाल है, बड़ाई तो हो रही है, अब ठीक ही कहा नरेन्द्र बाबू ने कि हमारे यहां की बिजली आई, बिजली आई, लोगों ने कहा बिजली आई, अब वही जब हाजीपुर में आये तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने में लाज से चूंकि सामने वे कैसे बोलते कि बिजली नहीं आई, बिजली में अच्छा काम हुआ है फिर अभी रिपिट किये और वे रिपिट कोनो कृपा नहीं किये, जो ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य चल रहा हैं महोदय, आर.ई.सी. जो भारत सरकार का संगठन है, वह मॉनेटरिंग करता हैं, सुपरविजन करता हैं, डाटा कलेक्ट करता हैं उसके आधार पर जो रिपोर्ट जाती हैं उसके आधार पर कहा गया बिहार ने बिजली के मामले सबसे बेहतर काम करने का काम किया, इसका मतलब एक बात और भी है, बड़ी चर्चायें होती हैं कि भारत, देश भर में जब बिहार बेहतर काम कर रहा है तो अन्य राज्य पिछुआया हुआ हैं, इसका मतलब देश के हर गांव में बिजली अभी तक नहीं पहुंची है यह भी सत्य बात हैं, इसी से साबित हो रहा है, नहीं तो ग्रामीण विद्युतीकरण दीन दयाल उपाध्याय में परिवर्तित क्यों होता, बिहार के लिए केवल यह योजना तो चलेगी नहीं, ऐसा नहीं है लेकिन बिहार की अपनी बिजली, आपने इतना आपने नहीं किया, अरे भाई पूरे देश की स्थिति हैं फिर क्या कहेंगे घाटे का, होल्डिंग कम्पनी घाटे में हैं अब महोदय, एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा मोटा मोटी:

अब महोदय, बी.पी.एल. रूरल- बिहार का टैरिफ रेट कितना है, 1 रूपया 70 पैसे, वेस्टबंगाल का कितना है- 3.42 पैसे, उत्तर प्रदेश का 2.50 पैसे, मध्य प्रदेश का 2.90 पैसे और राजस्थान 5.05 पैसे।

अरबन, बी.पी.एल. अरबन- बिहार में 2.05 पैसे, वेस्ट बंगाल में 3.42 पैसे उत्तर प्रदेश में 2.50 पैसे, मध्यप्रदेश में 2.90 पैसे, महाराष्ट्र में कम है और राजस्थान में 5.05 रू0 ।

उसी प्रकार महोदय, रूलर डामेस्टीक- बिहार 2.25,बंगाल 4.89, उत्तर प्रदेश 5.65, मध्यप्रदेश अच्छे दिन आ गये 4.07 पैसे और राजस्थान बहुत ही अच्छे दिन आ गये- 5 रूपया 30 पैसे,

रूरल एन.डी.एस., बिहार 2 रूपये 40, वेस्टबंगाल 6 रूपये10 पैसे, उत्तर प्रदेश 3 रूपये 65 पैसे, मध्यप्रदेश 6 रूपया 40 पैसे और राजस्थान 8 रूपये 85 पैसे,

इस ढंग से महोदय कटोगरीकली है, माने बिहार सबसे लोयेस्ट है । हमलोगों से पैसे नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि माननीय मुख्यमंत्री थोड़ी दया रखते हैं कि हमारे यहां के किसान, मजदूर, 89 परसेंट रूरल एरिया है, जब कभी टैरिफ की बात होगी तो कहेंगे छोड़िये, छोड़िये और जगह से पैसा इकट्ठा कीजिए लेकिन गरीबों को, किसानों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए । लेकिन यहां आलोचनायें होती हैं, होल्डिंग कम्पनी घाटे में जा रहीं है, होल्डिंग कम्पनी घाटे में जा रही है, टैरिफ पिछले तीन सालों से हमलोगों ने रिभाईज नहीं किया लेकिन बगल के राज्यों से भी हमारे यहां कम टैरिफ है । तो महोदय, बगैर जाने, अब महोदय एक आंकड़ा और मैं रखना चाहूंगा, कुछ भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, आज कल बी.जे.पी. वाले लोग खाली भ्रम पैदा करने में ही लगे रहते हैं, As per survey, सर्वे के अनुसार 49 लाख बी.पी.एल. हैं, जिसमें से 20 लाख को मिला चुका है, 29 लाख को दो सालों में करने का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सात निश्चय में योजना में जो कहा हैं कि दो साल में, दिसम्बर, 2017 तक इसको करेंगे । अब पटना की चर्चा कर रहे थे अरूण बाबू, वे चले गये, 1244 गांव है, 942 एलक्ट्रीफॉयड हैं और क्या-क्या, लाख-लाख की जनसंख्या बता रहे थे, एक लाख पटना में भी एलेक्ट्रीफायड नहीं है गांव । महोदय, दुर्भाग्य यह है कि इधर भी रहे लोग, माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठते थे बहुत सारे लोग, बुद्धि उनकी विकसित नहीं हुई, क्षरण हो गया । ज्योंही उधर गये पता नहीं क्यों हतप्रभ हैं, हताशा में हैं, क्या-क्या बोलते रहते हैं, क्या-क्या करते रहते हैं । अब कल जो एक अदभूत बात कौंसिल में हुआ, उसका जिक्र मैं नहीं करना चाहूंगा । मुझे तो हैरत हुई माननीय उप मुख्यमंत्री जी को वे कह रहे थे कि उपमुख्यमंत्री जी सभी विभागों की समीक्षा करें, कह रहे थे मैं जब था तो करता था । अब बताइये वित्तमंत्री जी है, सब विभाग की फाईल वित्त विभाग में तो जाती ही है, उप मुख्यमंत्री की हैसियत से उनके पास कौन फाईल जा रही थी । योजना विभाग के पास भी जाती है, योजना विभाग भी करता है उसको, अब उप मुख्यमंत्री रहकर के यह ज्ञानहीनता अगर हो भगवान बचाये महोदय । ये हताशा का द्योतक है, परेशानी में है लोग, तो महोदय परेशानी और हताशा से राज्य का विकास नहीं होगा, हम उनसे आग्रह करूंगा कि सभी लोगों से कि सच्चाई को समझे, वास्तविकता को समझे । अब कुछ गड़बड़िया की शिकायत की, हम सभी लोगों का दायित्व है कि गड़बड़ी अगर हो रही है तो माननीय मुख्यमंत्री ने जो कठोर कानून बनाया है, कोई भी आदमी अगर गड़बड़ी

करता हुआ पाया जाय तो पकड़वाइये और पकड़ कर गिरफ्तार करवाइये, कोई उसको बचाने वाला नहीं होगा, लेकिन यहीं से बैठकर हमारे ऑफिसर और हमी लोग सब कुछ तो नहीं कर सकते हैं । सबको मिलकर करना होगा । जन प्रतिनिधियों को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा । कठिन काम है टोले-टोले, महुल्ले मुहल्ले बिजली पहुंचाना तो महोदय, अब आपका इशारा हो रहा हुक्म तो मानना अनिवार्य हैं...

अध्यक्ष : हमारा इशारा नहीं है, घड़ी का इशारा है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं तो आप से ही गाईड हूंगा घड़ी से क्या मतलब महोदय, मैं अंत में, चले गये अरूण बाबू, हैं नहीं, दुर्भाग्य है कभी नही रहते हैं, पेश तो कर देते हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कटौती का प्रस्ताव वापस करे लेकिन एक बात के साथ, उनके प्रधानमंत्री प्रशंसा करते हैं ये कटौती करते हैं तो शायद प्रधानमंत्री मुंह से प्रशंसा करते है और पैसे में ये कटौती करते हैं, यही धंधा ये लोग भी करते हैं यह अच्छी बात नहीं है, राज्यहित की बात नहीं है, राज्य के लोग देख रहे हैं, इसलिए मैं उनसे फिर आग्रह करूंगा कि वे वापस लें । बहुत बहुत धन्यवाद ।

महोदय, जो अनुदान मांग मैंने पेश किया, मैं निवेदन, दर्खास्त करूंगा सदन से कि उसे पारित करने की कृपा करें ।

महोदय, इसे प्रोसिडिंग्स का हिस्सा महोदय ।

अध्यक्ष : ठीक । माननीय मंत्री जो लिखित दस्तावेज सदन पटल पर रख रहे हैं, वह कार्यवाही का हिस्सा बनेगा । (परिशिष्ट द्रष्टव्य)

टर्न-29/ज्योति

21-03-2017

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(मा0 सदस्य श्री अरुण कुमार सिन्हा अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटायी जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

'' उर्जा विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 109,05,03,31,000/-(एक सौ नौ अरब पॉच करोड़ तीन लाख एकतीस हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनॉक 21 मार्च, 2017 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 42 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें सबंधित विभागों को भेज दिया जायेगा ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनॉक 23 मार्च 2017 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

मुख्य बिन्दु

1. ग्रिड/शक्ति उपकेन्द्र की संख्या :

वर्ष	ग्रिड उपकेन्द्र की संख्या	शक्ति उपकेन्द्र की संख्या
2005	45	268
मार्च 2017	106	674
मार्च 2018	152	792

2. सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड में 132/33 के०वी० ग्रिड उपकेन्द्र के निर्माण का कार्यक्रम।

3. उत्पादन

वर्ष	उत्पादन क्षमता (मेगावाट)
2005	—
मार्च 2017	525
मार्च 2018	2650*

* कॉंटी यूनिट–4 (195 मेगावाट) – अप्रैल, 2017
बरौनी यूनिट – 6 (110 मेगावाट) – मई, 2017
बरौनी यूनिट – 8 एवं 9 (2x250 मेगावाट) – नवम्बर, 2017
नबीनगर यूनिट – 1 (660 मेगावाट) – सितम्बर, 2017
नबीनगर यूनिट – 2 (660 मेगावाट) – मार्च, 2018

4. ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्य में कतिपय जिला यथा, सारण, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), कटिहार, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, लखीसराय, बांका में कार्य की प्रगति अपेक्षाकृत धीमी है। इसके लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :–

(क) मुख्यालय स्तर पर नियमित समीक्षात्मक बैठक जिसमें जनप्रतिनिधिगण भी भाग लेते हैं।

(ख) निविदा के शर्तों के आलोक में कार्यरत एजेंसियों को डीबार किया गया है, साथ ही सारण, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), औरंगाबाद, लखीसराय एवं जहानाबाद जिलों में नए एजेंसियों को कार्य विभाजित किया गया है।

(घ) सीतामढ़ी जिला में कार्यरत एजेंसी के विरूद्ध Termination प्रक्रियाधीन है।

(ड.) मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर जिलों के फ्रेंचाईजी क्षेत्र में पड़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के विद्युतीकरण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रक्रियाधीन।

5. ग्रामीण विद्युतीकरण में हुई उत्साहवर्धक प्रगति की सराहना माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई है। बिजली के क्षेत्र में हो रहे कार्यों के बारे में एक भ्रांति फैलाने का प्रयास किया जाता है कि सारे कार्यों के लिए केन्द्र की राशि का ही उपयोग किया जाता है। इस भ्रांति को दूर करने के लिए कुछ तथ्यात्मक आँकड़े निम्न हैं:–

(क) <u>दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)</u> – केन्द्र सरकार की इस योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में प्राप्त होती है। इस योजना में Dedicated Agriculture Feeder का निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण, पावर सब स्टेशन का निर्माण इत्यादि का कार्य शामिल है।

कुल स्वीकृत राशि	–	**रू0 5827.23 करोड़**
केन्द्रांश (60 प्रतिशत)	–	**रू0 3496.33 करोड़**
राज्यांश (40 प्रतिशत)	–	**रू0 2330.90 करोड़**

(ख) <u>ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाएँ</u> (पूर्ववर्ती राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) के लिए पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा 90 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 10 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के सफल सम्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा **10 प्रतिशत के अतिरिक्त** स्पेशल प्लान (बी०आर०जी०एफ०) एवं अपने संसाधनों से **रू0 1669 करोड़** व्यय किए जा रहे हैं।

- हर घर **बिजली** के अन्तर्गत मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा **रू0 1897.50 करोड़ स्वीकृत है।** इस योजनान्तर्गत विस्तृत सर्वे के बाद लगभग 40 लाख ग्रामीण परिवार, जो गरीबी रेखा से ऊपर श्रेणी के हैं, को विद्युत संबंद्ध उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना की शुरूआत की जा चुकी है एवं **दिसम्बर, 2018 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है।**

- 219 गाँवों में ग्रिड के माध्यम से बिजली आपूर्ति करने में बहुत कठिनाई है अतः इन गाँवों में सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युतीकरण करने हेतु अधिकांश राशि राज्य सरकार के द्वारा ही वहन की जा रही है। **(लगभग रू0 200 करोड़)**

- स्पेशल प्लान (बी०आर०जी०एफ०) :–

कुल स्वीकृत राशि	–	**रू0 9210 करोड़**
केन्द्र से प्राप्त राशि	–	**रू0 4737 करोड़**
कुल अद्यतन व्यय	–	**रू0 5749 करोड़**

केन्द्र सरकार से ससमय राशि नहीं उपलब्ध होने के बावजूद कार्य की महत्ता एवं समय सीमा (Cost overrun को रोकने हेतु) के अन्दर कार्य निष्पादन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा **ऋण (लगभग रू0 5260 करोड़)** लेकर कार्य को द्रुत गति से सम्पन्न कराया जा रहा है ताकि हर घर बिजली के निश्चय को साकार किया जा सके।

6. विद्युत टैरिफ

- राज्य में वर्तमान विद्युत टैरिफ देश के अन्य राज्यों के तुलना में अपेक्षाकृत काफी कम है।
- गत दो वर्षों में विद्युत उपलब्धता में **24.5%** की दर से वार्षिक वृद्धि हुई है।
- 2014–15 में विद्युत टैरिफ में **कोई बढ़ोत्तरी नहीं** हुई।
- 2015–16 में विद्युत टैरिफ में बढोत्तरी मात्र **2.40%** के दर से हुई।
- 2016–17 में विद्युत टैरिफ में **कोई बढ़ोत्तरी नहीं** हुई।

7. बिलिंग

- ❖ राज्य के 68 शहरों में SAP Software पर Android Mobile के माध्यम से स्पॉट बिलिंग किया जा रहा है। प्रत्येक माह सभी उपभोक्ताओं को उनके घर पर ही मोबाईल से मीटर रिडिंग लेते हुए ब्लुटूथ प्रिंटर से विद्युत विपत्र (रिडिंग के फोटो सहित) निर्गत कर उपलब्ध कराया जा रहा है।राज्य के शेष उपभोक्ताओं (छोटे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित) को भी NIC सॉफ्टवेयर पर Android Mobile के माध्यम से स्पॉट बिलिंग का कार्य जनवरी, 2017 से शुरू किया गया है।
- ❖ मई 2017 तक इन क्षेत्रों के सभी उपभोक्ताओं को उनके घर पर ही मोबाईल से मीटर रीडिंग लेते हुए ब्लुटूथ प्रिंटर से विद्युत विपत्र (रीडिंग के फोटो सहित) निर्गत कर उपलब्ध करने का लक्ष्य है।
- ❖ बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत बिलिंग से संबंधित शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। बिलिंग से संबंधित 6219 मामले पूरे राज्य में दायर हुए जिसमें 4653 मामलों का निष्पादन हुआ।

8. बिजली खरीद की दर से संबंधित

स्त्रोत	मात्रा (मेगावाट)	औसत दर (रू० प्रति यूनिट)	अभियुक्ति
केन्द्रीय प्रक्षेत्र	2942	4.46	1. एन०टी०पी०सी०, बाढ़ रू० 5.70 प्रति यूनिट 2. फरक्का–3 रू० 4.55 प्रति यूनिट
दीर्घकालीन पी०पी०ए०	250	3.25	
अल्पकालीन पी०पी०ए०	246	3.16	
बाजार से	552	2.82	
कुल	3990	4.27	

9. Renewable Power Purchase Obligation

वर्ष	सौर ऊर्जा (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)	गैर–सौर ऊर्जा (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)
2016–17	266	105 (43 मेगावाट अप्रैल, 2017 तक)	576	86 (शेष के लिए सर्टिफिकेट क्रय)
2017–18	576	300 SECI 250(MP) मध्यप्रदेश	732 Solar Energy Corporation of India	86+100 Wind - SECI (Rs. 3.47) शेष 546 मेगावाट के लिए मार्केट से अल्पकालीन पी०पी०ए० किया गया है।
2022तक	2185	—	2458	—

TARIFF IN OTHER STATES VS. BIHAR

Consumers Category	Bihar	West Bengal	Uttar Pradesh	Madhya Pradesh	Maharastra	Rajasthan
KJ/BPL (RURAL)	Rs 1.70	Rs 3.42	Rs 2.50	Rs 2.90	Rs 0.97	Rs 5.05
KJ/BPL (URBAN)	Rs 2.05	Rs 3.42	Rs 2.50	Rs 2.90	Rs 0.97	Rs 5.05
RURAL DOMESTIC	Rs 2.25	Rs 4.89	Rs 5.65	Rs 4.07	Rs 4.26	Rs 5.30
RURAL NDS	Rs 2.40	Rs 6.10	Rs 3.65	Rs 6.40	Rs 7.12	Rs 8.85
DS II	Rs 3.55	Rs 5.04	Rs 5.65	Rs 4.27	Rs 4.26	Rs 5.30
NDS II	Rs 6.95	Rs. 6.12	Rs 8.95	Rs 6.40	Rs 7.12	Rs 8.85
LTIS	Rs 6.85	Rs. 6.40	Rs 8.95	Rs 7.75	Rs 8.38	Rs 5.95
HT S1	Rs. 8.00	Rs 9.34	Rs 9.80	Rs 8.00	Rs 13.50	--

Maxm demand met of BIHAR (in MW)

Year	Month	Max. Load	Date	Time
2012-13	Aug-12	1751	27.08.2012	24:00
2013-14	Nov-13	2314	08.11.2013	22:00
2014-15	Oct-14	2831	21.10.2014	19:50
2015-16	Oct-15	3459	02.10.2015	19:28
2016-17	Oct-16	3770	07.10.2016	19:36

14th ANNUAL REPORT
2013-2014

RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A Government of Rajasthan Undertaking)

LIST OF DIRECTORS
(AS ON DATE OF THE ADJOURNED 14th AGM)

1. Sh. Narendra Mal Mathur	-	Chairman & Managing Director
2. Sh. Sanjay Malhotra, IAS	-	Director
3. Sh. Praveen Gupta, IAS	-	Director
4. Sh. Prakash Chand Jain	-	Director (Projects)
5. Sh. Arun Kumar Gupta	-	Director

CHIEF CONTROLLER OF ACCOUNTS
Sh. A.K.C. Bhandari

COMPANY SECRETARY
Sh. S.G.V.S. Subrahmanyam

AUDITORS
M/s P.C. Modi & Co.
Chartered Accountants,
R-20, Yudhishter Marg,
C-Scheme, Jaipur-302005
Tel: 2222735, 2228503,
Fax: 0141-2222697

BANKERS
State Bank of Bikaner & Jaipur

REGD. OFFICE & HEAD OFFICE
CIN - U40102RJ2000SGC016484
Vidyut Bhawan
Janpath, Jyoti Nagar
Jaipur - 302005
Phone : 0141-2740381-2
Fax : 0141-2740633
Website : www.rajenergy.com
www.rvunl.com

CIN - U40102RJ2000SGC016484

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2014

(Amount in ₹)

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2014	As at 31st March, 2013
EQUITY AND LIABILITIES			
Shareholders' funds			
Share Capital	1	65,73,92,33,000	58,04,59,00,000
Reserves & Surplus	2	(6,95,06,23,835)	(3,73,87,35,310)
Share application money pending allotment	3	1,31,66,67,000	1,61,00,00,000
Non-current liabilities			
Long-Term Borrowings	4	1,42,77,57,59,787	1,19,62,22,17,859
Other Long Term Liabilities	5	6,15,19,23,121	6,08,85,35,355
Current liabilities			
Short-Term Borrowings	6	5,00,00,00,000	5,00,00,00,000
Trade Payables	7	3,81,64,99,210	7,87,46,22,683
Other Current Liabilities	8	32,10,03,25,524	34,15,44,08,188
Short-Term Provisions	9	2,51,87,45,408	2,88,79,94,991
		2,52,46,85,29,215	**2,31,54,49,43,766**
ASSETS			
Non-current assets			
Fixed Assets			
- Tangible Assets	10	97,82,16,79,617	82,10,03,76,302
- Capital Work-In-Progress	11	1,05,67,01,32,684	97,75,94,15,213
Non-Current Investments	12	20,00,002	20,00,001
Deferred Tax Assets (Net)	13	-	-
Long-Term Loans and Advances	14	21,97,37,12,368	16,72,61,29,337
Other Non-Current Assets	15	2,01,38,47,866	2,21,02,54,433
Current Assets			
Inventories	16	5,52,43,86,975	8,67,89,57,268
Trade Receivables	17	9,90,55,73,398	15,55,81,10,215

(Amount in ₹)

Particulars	Note No.	As at 31st March, 2013	As at 31st March, 2012
Cash and Bank Balances	18	1,14,30,89,196	3,40,96,39,756
Short-Term Loans and Advances	19	3,24,74,30,084	1,39,77,26,693
Other Current Assets	20	5,16,66,77,025	3,70,23,34,548
		2,52,46,85,29,215	**2,31,54,49,43,766**
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON FINANCIAL STATEMENT	I & II		

As per our separate report of even date

For P.C. MODI & CO.
Chartered Accountants
FRN 000239C

(Anirudh Singh)
Partner
M.No. 418686

Place : Jaipur
Date : 18th September, 2014

For and on behalf of the Board of Directors

(P.C. JAIN)
DIN-03545146
Director (Projects)

(N.M. MATHUR)
DIN-03033375
Chairman & Managing Director

(S.G.V.S. SUBRAHMANYAM)
Company Secretary

(A.K.C. BHANDARI)
Chief Controller of Accounts

CIN - U40102RJ2000SGC016484

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2014

(Amount in ₹)

Particulars	Note No.	For the year ended 31st March, 2014	For the year ended 31st March, 2013
Revenue:			
Revenue From Operations	21	84,01,00,34,122	87,81,44,51,437
Other Income	22	25,00,82,007	45,22,53,300
Total Revenue		84,26,01,16,129	88,26,67,04,737
Expenses:			
Generation & Other Direct Expenses	23	69,07,93,12,343	71,65,84,08,038
Repairs & Maintenance	24	2,38,51,20,680	2,21,51,57,481
Employee Benefits Expense	25	1,89,11,41,514	1,73,75,79,259
Finance Costs	26	7,51,56,52,002	7,96,39,26,372
Depreciation and Amortization Expense	27	5,93,30,15,787	6,15,59,97,209
Administrative and Other Expenses	28	56,89,66,345	53,66,00,790
Total Expenses		87,37,32,08,671	90,26,76,69,149
Profit / (Loss) Before Prior Period Items and Tax		(3,11,30,92,542)	(2,00,09,64,412)
Prior Period Income/(Expenses)	29	(1,54,95,984)	14,88,12,080
Profit / (Loss) Before Tax		(3,12,85,88,526)	(1,85,21,52,332)
Tax Expense:			
Current Tax		-	-
Income Tax (Earlier year tax)		-	-
Deferred Tax		-	-
PROFIT / (LOSS) FOR THE YEAR		(3,12,85,88,526)	(1,85,21,52,332)
Earnings Per Equity Share	30		
Equity Share of Par Value ₹10/- Each			
(1) Basic & Diluted		-0.54	-0.35
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES ON FINANCIAL STATEMENT	I & II		

As per our separate report of even date

For P.C. MODI & CO.
Chartered Accountants
FRN 000239C

(Anirudh Singh)
Partner
M.No. 418686

Place : Jaipur
Date : 18th September, 2014

For and on behalf of the Board of Directors

(P.C. JAIN)
DIN-03545146
Director (Projects)

(S.G.V.S. SUBRAHMANYAM)
Company Secretary

(N.M. MATHUR)
DIN-03093375
Chairman & Managing Director

(A.K.C. BHANDARI)
Chief Controller of Accounts